₹ 20

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

अप्रैल 2024

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

RNI NO.-BIHHIN/2006/18181, DAVP NO.-129888, POSTAL REG. NO. :- PS-35

किसकी प्रतिष्ठा दाव पर ?

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.

(Serving nation since 1990)

WESTOCITRON
WESTOCLAV
WESTOFERON
WESTOPLEX
QNEMIC

AOJ
AZIWEST
DAULER
MUCULENT
AOJ-D
BESTARYL-M
GAS-40
MUCULENT-D

SEVIPROT
WESTOMOL
WESTO ENZYME
ZEBRIL

WESTERLIN DRUGS PVT. LTD.
Industrial area, Fatuha-803201
E-mail- westerlindrugsprivatelimited@gmail.com
Phone No.:0162-3500233/2950008

जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ

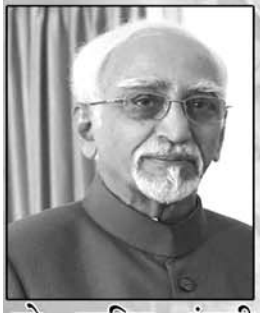

मो० हामिद अंसारी
01 अप्रैल 1937

अजय देवगन
02 अप्रैल 1969

प्रभु देवा
03 अप्रैल 1973

जया प्रदा
03 अप्रैल 1962

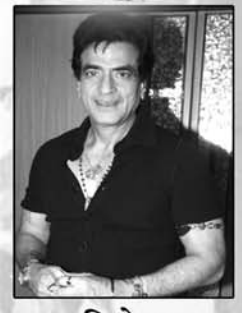

जितेन्द्र
07 अप्रैल 1942

रामगोपाल वर्मा
07 अप्रैल 1962

अल्लु अर्जुन
08 अप्रैल 1983

जया बच्चन
09 अप्रैल 1948

जयराम रमेश
09 अप्रैल 1954

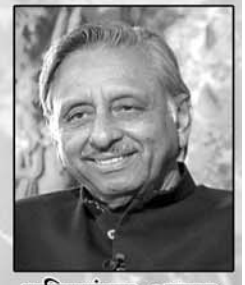

मणिशंकर अय्यर
10 अप्रैल 1941

टैरेंस लेविस
10 अप्रैल 1975

स्व० सतीश कौशिक
13 अप्रैल 1956

मुकेश अंबानी
14 अप्रैल 1957

मंदिरा बेदी
15 अप्रैल 1972

लारा दत्ता
16 अप्रैल 1978

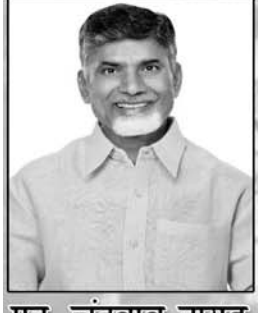

एन. चंद्रबाबू नायडू
20 अप्रैल 1950

चेतन भगत
22 अप्रैल 1974

मनोज बाजपेयी
23 अप्रैल 1969

सचिन तेन्दुलकर
24 अप्रैल 1973

आशिष नेहरा
29 अप्रैल 1979

निर्भीकता हमारी पहचान

www.kewalsach.com

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

Regd. Office :-
East Ashok, Nagar, House
No.-28/14, Road No.-14,
kankarbagh, Patna- 8000 20
(Bihar) Mob.-09431073769
E-mail :- kewalsach@gmail.com

Corporate Office:-
Vaishnavi Enclave,
Second Floor, Flat No. 2B,
Near-firing range,
Bariatu Road, Ranchi- 834001
E-mail :- editor.kstimes@rediffmail.com

Delhi Office :-
Sanjay Kumar Sinha,
A-68, 1st Floor, Nageshwar Talla
Shastri Nagar, New Delhi - 110052
Mob.- 09868700991,
09955077308
E-mail:- kewalsach_times@rediffmail.com

Kolkata Office :-
Ajeet Kumar Dube,
131 Chitranjan Avenue,
Near- md. Ali Park,
Kolkata- 700073
(West Bengal)
Mob.- 09433567880
09339740757

Advertisement Rates Per Issue

COLOUR

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE	Qr. PAGE
Cover Page	5,00,000/-	N/A	N/A
Back Page	1,60,000/-	N/A	N/A
Back Inside	1, 00000/-	60,000/-	35000
Back Inner	90,000/-	50,000/-	30000
Middle	1,50,000/-	N/A	N/A
Front Inside	1, 00000/-	60,000/-	40000
Front Inner	90,000/-	50,000/-	30000

B & W

AREA	FULL PAGE	HALF PAGE
Inner Page	60,000/-	35,000/-

1. एक साल के नियमित विज्ञापन पर पत्रिका के वेवसाइट **www.kewalsach.com** के फ्रंट पर भी विज्ञापन निःशुल्क तथा आपका वेवसाइट से सीधा लिंक हो सकता है।
2. एक साल के नियमित विज्ञापन पर 10 प्रतिशत की रियायत।
3. आपके प्रोडक्ट या संगठन के प्रचार-प्रसार हेतु आलेख को उचित स्थान।
4. पत्रिका द्वारा सामाजिक कार्य में आपके संगठन/प्रोडक्ट का बैनर/फ्लैक्स को उचित स्थान देकर आपके संगठन का व्यापक प्रचार-प्रसार।
5. विज्ञापन का भुगतान चेक या आर.टी.जी.एस. से ही मान्य होगा।

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

2024 में नहीं नरेन्द्र मोदी का विकल्प

अपनी प्रतिक्रिया हमारे ई-मेल पर दें:- editor.kstimes@rediffmail.com

2024 लोकसभा चुनाव का पारा सातवें आसमान पर है और देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियां खुद विजयी होने के बजाय 2014 से लगातार प्रधानमंत्री रहने वाले नरेन्द्र मोदी को हराने के लिए प्रयत्न कर रही हैं लेकिन किस प्रकार का विपक्ष ने वातावरण बनाया है उससे तो साफ हो चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनकर हैट्रिक की उपाधि से नवाजे जायेंगे। 2014 में प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने के बाद नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ने देश के भीतर वह सब कर दिखाया है जिसकी आवश्यकता कई सदी से थी और वादे के अनुसार जनता के मिजाज के अनुसार देशहित में कई ऐसे फैसले लिए गये तथा कानून बनाये गये जिसकी वजह से 85 फिसदी जनता के दिल में मोदी ने अपनी पैठ बना ली है। बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार पर उंगली उठाने वाले पर जब ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है तो विपक्ष का चिलाना लाजमी है लेकिन 2024 में 400 का पार आंकड़ा पार करे या नहीं लेकिन मोदी को प्रधानमंत्री के पद पर हैट्रिक लगाने से कोई नहीं रोक सकता। विपक्ष खुद ऐसी राजनीति कर रहा है जिसकी वजह से नरेन्द्र मोदी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। श्रीराम मंदिर के निर्माण के बाद सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले और उनकी युवा पीढ़ी ने यह मन बना लिया है कि वर्त्तमान समय में मोदी का विकल्प विपक्ष के पास नहीं है और विश्व के पटल पर भारत देश का सीना गर्व एवं सुरक्षा से चौड़ा रखने के लिए 56 ईंच का सीना बहुत जरूरी है और वह नरेन्द्र मोदी के ही पास है।

मोदी-मोदी का नारा न सिर्फ गुजरात बल्कि भारत के सभी राज्यों में लगने लगा है और उनके व्यक्तित्व और प्रभाव को देखते हुए भारत के अलावा अन्य देशों में भी मोदी-मोदी के नारे से भारत विश्वगुरू बनने की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ खामियों को नजरअंदाज कर देने पर 10 वर्ष के शासन के बाद भी 2024 में नरेन्द्र मोदी का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष में रहते हुए कुछेक राजनेता विकल्प के रूप में भूमिका निभा सकते थे लेकिन सत्ता की लोलुप्ता और जेल जाने की भय की वजह से अपने पार्टी के सिद्धान्त का आत्महत्या करके महागठबंधन बनाकर पहले ही हार स्वीकार कर चुके हैं। बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकास का ऐसा मॉडल बनाया की आजादी के बाद कांग्रेस की नींद हीं हराम हो गयी और 2014 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनते ही कांग्रेस की हार तय हो चुकी थी क्योंकि मोदी के हाइटेक प्रचार और कांग्रेस से तीखे सवाल ने देश का मिजाज बदल दिया था जिसकी वजह से पहली बार भाजपा अपने बूते 273 का आंकड़ा पार करके सरकार बनाने में सफल हुई। 2014 से 2019 का प्रथम काल में बतौर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के भीतर ऐसा माहौल बनाया कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चारो तरफ भगवा रंग दिखने लगा। विपक्ष यह आरोप लगाते नहीं थकता कि जहां भाजपा चुनाव भी हारती है वहां भी अमित शाह सरकार बना लेते हैं की राजनीति करते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी के प्रयास एवं विकास की रफ्तार के साथ विपक्ष की लापरवाही एवं गलत बयानबाजी की वजह से भाजपा को इतना शक्तिशाली बना दिया की वह अकेले 303 सीट पर विजयी हुई और कांग्रेस लाचार से बीमार हो गयी। एनडीए का बढ़ता जनाधार एवं सनातन धर्म, कथावाचकों का प्रयास विभिन्न प्रकार के कानून देशहित में बनाये तथा धारा 370 जैसा काला कानून के हटाकर, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत ने विश्व के पटल पर अपनी शक्ति का एहसास करा दिया है की वह घरेलू मामले में बहारी का हस्तक्षेप बर्दास्त नहीं करेगा। भारत के हिन्दी राज्यों में विपक्ष का जीना हराम कर दिया तथा पार्टी के भीतर भी जिन्होंने आंख दिखाने की कोशिश की उनको उनकी औकात बताये हुए शांतकर दिया गया चाहे वह फिल्मी कलाकार हों या फिर भारतीय क्रिकेटर। गठबंधन में भी शामिल लोगों को इस बात का भान हो गया है कि हिन्दुओं को आंख दिखाना भारत में अब आसान नहीं रहा और विपक्ष के राजनेता भी मोदी को शिकस्त देने के लिए मंदिर-मंदिर घूमने लगे और तो और जनेउ तक धारण करने लगे परन्तु हिन्दुओं के सम्राट बनने में विफल रहे। आतंकवाद हो या फिर भ्रष्टाचारी उनको पकड़कर जेल भेजने में सरकार अब विलम्ब नहीं करती और वर्त्तमान समय में झारखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव 2024 में जेल की काल-कोठरी में बंद हैं। आमजनता के सुविधाओं का ख्याल रखते हुए एक से बढ़कर एक योजना लागू करके उनका विश्वास को जीता है। सभी वर्णों को वाजिब हक दिलाने की वजह से सभी जाति एवं धर्मों के बीच भी मोदी की लोकप्रियता कायम है और तीन तलाक के मुद्दे ने तो मुस्लिम महिलाओं को मोदी का समर्थन करने पर विवश कर दिया है। 400 सीट जीतकर मोदी आते हैं तो देश के भीतर सविधान से लेकर वह तमाम विषयों को सुधार लिया जायेगा तो भारत देश के लिए नासूर है और यही कारण है कि देश के भीतर क्षेत्रीय राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टियां यह नहीं चाहती है कि मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री का पद तो तय है आंकड़ा 400 के पार करके भारत को विश्वगुरू बनने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। साधु - संत, कथावाचक, कलाकार, पत्रकार, सकरात्मक सोच वाले मोदी के भीतर की कुछ कमियों को नजरअंदाज करके देशहित में मोदी की आवश्यकता है की दुहाई देकर 400 का आंकड़ा पार कराने की जुगत में लगे हुए हैं। न खाउंगा और न खाने दूंगा की विचार को आगे बढ़ाते हुए परिवारवाद एवं जातिवाद के मिथ्या को भी तोड़ने वाले हैं। कांग्रेस और त्रिमूल कांग्रेस के अलावा देश के भीतर तीसरी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिनका दो अंको में सांसद सदन पहुंच सकें। पूरे विश्व में तृतीय विश्वयुद्ध की तरफ बढ़ रहा है लेकिन मोदी की कूटनीति ने सभी देशों में भारत की साख एवं विश्वसनीयता को कायम करके यह भी साबित कर दिया है कि भारत सबका साथ-सबका विकास में भरोसा रखता है। दल और गठबंधन के नाराज नेताओं को कैसे अपनी ओर मोड़ना है यह मोदी से अधिक भला कौन कर सकता है और इन्हीं कारणों की वजह से दूसरे देल के बड़े नेता भी मोदी की लोकप्रियता के कायल हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस के आचार्य प्रमोदी को भी खुले मंच से मोदी का तारिफ करना पड़ा, भले ही कांग्रेस ने उनको अपने दल से बाहर का रास्ता दिखाया गया। कांग्रेस एवं अन्य दलों के नेताओं का जिस प्रकार पलायन हो रहा है और उनका विलय भाजपा में हो रहा है उससे तो यह स्पष्ट हो गया है कि 2024 में मोदी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

मार्च 2024

आपको केवल सच पत्रिका कैसी लगी तथा इसमें कौन-कौन सी खामियाँ हैं, अपने सुझाव के साथ हमारा मार्गदर्शन करें। आपका पत्र ही हमारा बल है। हम आपके सलाह को संजीवनी बूटी समझेंगे।

केवल सच

हमारा पता है :-

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
द्वारा:- ब्रजेश मिश्र
पूर्वी अशोक नगर, रोड़ नं.- 14, मकान संख्या- 14/28
कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार)
फोन:- 9431073769/ 8340360961/ 9955077308

हमारा ई-मेल
kewalsach@gmail.com, editor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

लोकसभा चुनाव 2024

संपादक जी,

केवल सच, पत्रिका का मार्च 2024 अंक में लोकसभा चुनाव 2024 की सटीक खबर को अमित कुमार ने पूरे विस्तार से लिखा है। बिहार एवं देश के भीतर लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा पर भी सटीक विवेचना की गई है। बिहार में नीतीश कुमार एवं एनडीए के अन्य घटक दलों की राजनीति एवं कूटनीति के सभी बिन्दुओं को भी प्रकाश में लाने का काम अमित कुमार ने बखूबी किया है। केवल सच पत्रिका समाज का दर्पण बन चुका है।

✦ **संजय पटवा, मानपुर बाजार, गया (बिहार)**

मरीज की सुरक्षा

ब्रजेश जी,

आपकी लेखनी को मैं सलाम करता हूं क्योंकि आपने सदैव जनहित की समस्याओं को बिना डरे मजबूती से उठाया है। मार्च 2024 अंक का आपका संपादकीय ''**मरीज की सुरक्षा के लिए भी बने कानून**'' में आपने वर्त्तमान समय की चिकित्सा पद्धति पर सही प्रहार किया है। चिकित्सक और अस्पताल में चल रहे कालाबाजारी के सच को उजागर किया है लेकिन इनका आतंक और संगठन इतना बड़ा है कि सरकार एवं कानून भी इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। ज्वलंत समस्या है, इसपर विचार अवश्य हो।

✦ **बिनोद मिश्र, कचहरी रोड, गया, बिहार**

किशनगंज और नवादा

मिश्रा जी,

किशनगंज में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर काफी खासम-खास बना हुआ है और किस प्रकार की स्थिति है उसपर बेहतीरन प्रकाश डालने का काम पत्रकार धर्मेन्द्र सिंह ने किया है तो नवादा लोकसभा के मद्दे नजर मिथिलेश कुमार ने ''नवादा लोकसभा क्षेत्र में बदलती रही राजनीतिक परिदृश्य'' में पूर्व से लेकर वर्त्तमान उम्मीदवारों की जानकारी के साथ 2024 में किस प्रकार जनता का मूड है उसकी सकरात्मक समीक्षा की गयी है। पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों का विकास कार्य की भी समीक्षात्मक खबरों को भी उचित स्थान देना चाहिए।

✦ **रेश्मी चटर्जी, बाबू बाजार, कोलकात्ता, प.बं.**

नेताओं के मिजाज

मिश्रा जी,

केवल सच, पत्रिका का मार्च अंक में लोकसभा चुनाव 202 के मद्देनजर एक पर एक खबर को स्थान दिया गया है। संजय सिन्हा की खबर ''टीकट नहीं मिलने पर नेताओं के मिजाज बदले'' में कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा, क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू, सहित प्रमोद कृष्णन, जयंत सिन्हा और भी कद्दावर नेताओं को जब टिकट कटता है तो बौखलाहट क्या होती है उसपर बढ़िया खबर श्री सिन्हा ने पाठकों के समक्ष रखा है। किस प्रकार सांसद बनने के लिए सबकुछ जानने के बाद भी अंजान बनने का ढ़ोंग रचा जाता है। सभी राज्यों की खबरो को भी दें।

✦ **रविन्द्र वर्णवाल, यूसूफ सराय, नई दिल्ली**

झारखंड की खबर

संपादक जी,

केवल सच, पत्रिका का मार्च 2024 अंक में झारखंड की राजधानी राँची की कई खबरें जानकारीप्रद के साथ-साथ पत्रकार ओम प्रकाश ने बेबाकी के साथ लिखा है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने पत्नी के साथ शिव पूजा किया की खबर भी सटीक लगा। पुलिस विभाग पर जमकर खबरें हैं इसी प्रकार राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को भी प्राथमिकता दिया जाये ताकि झारखंड की राजनीतिक गतिविधियों की भी पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके जैसे बिहार की राजनीति की छोटी बड़ी जानकारी पढ़ने को मिल रहा है। ओम प्रकाश जी की खबरों के लिए धन्यवाद।

✦ **पंकज कुमार राय, खेलगाँव, राँची, झा०**

दाग अच्छे लगते हैं

संपादक जी,

बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार की खबरों को पूरी गंभीरता के साथ केवल सच प्रकाशित करता है। मार्च 2024 अंक में शशि रंजन सिंह एवं राजीव शुक्ला की खबर ''स्वास्थ्य विभाग को दाग अच्छे लगते हैं'' में विभाग के मंत्री, प्रधान सचिव सहित अन्य पदाधिकारी/कर्मचारी के साथ वहां के क्रिया-कलाप को पूर्ण बेबाकी के साथ प्रकाशित किया है और नियमित रूप से खबर को लिखने की वजह से सरकार एवं विभाग को कार्रवाई करने पर विवश होना पड़ता है। अन्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार को भी उजागर करना चाहिए।

✦ **मनोज उरांव, करमटोली चौक, राँची, झा०**

अन्दर के पन्नों में

10

27

37

77

RNI No.- BIHHIN/2006/18181, DAVP No.- 129888

समृद्ध भारत खुशहाल भारत

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष:- 18, | अंक:- 215, | माह:- अप्रैल 2024, | मूल्य:- 20/- रू

फाउंडर

स्व० गोपाल मिश्र

स्व० सुषमा मिश्र

संपादक

ब्रजेश मिश्र

9431073769 8340360961

editor.kstimes@rediffmail.com

kewalsach@gmail.com

प्रधान संपादक

अरूण कुमार बंका 7782053204

सुरजीत तिवारी 9431222619

निलेन्दु कुमार झा 9431810505/8210878854

सच्चिदानन्द मिश्र 9934899917

रामानंद राय 9905250798

डॉ० शशि कुमार 9507773579

संपादकीय सलाहकार

अमिताभ रंजन मिश्र 9430888060, 8873004350

अमोद कुमार 9431075402

महाप्रबंधक

त्रिलोकी नाथ प्रसाद 9308815605, 9122003000

triloki.kewalsach@gmail.com

महाप्रबंधक (विज्ञापन)

पूनम जयसवाल 9430000482, 9798874154

मनीष कुमार कमलिया 9934964551, 8809888819

उप-संपादक

अरबिन्द मिश्रा 9934227532, 8603069137

प्रसुन्न पुष्कर 9430826922, 7004808186

ब्रजेश सहाय 7488696914

ललन कुमार 7979909054, 9334813587

आलोक कुमार सिंह 8409746883

संयुक्त संपादक

अमित कुमार 'गुड्डू' 9905244479, 7979075212

राजीव कुमार शुक्ला 9430049782, 7488290565

कृष्ण कुमार सिंह 6209194719, 7909077239

काशीनाथ गिरी 9905048751, 9431644829

सहायक संपादक

शशि रंजन सिंह 8210772610, 9431253179

मिथिलेश कुमार 9934021022, 9431410833

नवेन्दु कुमार मिश्र 9570029800, 9199732994

कामोद कुमार कंचन 8971844318

समाचार प्रबंधक

सुधीर कुमार मिश्र 9608010907

ब्यूरो-इन-चीफ

संकेत कुमार झा 9386901616, 7762089203

बिनय भूषण झा 9473035808, 8229070426.

.

विधि सलाहकार

शिवानन्द गिरि 9308454485

रवि कुमार पाण्डेय 9507712014

चीफ क्राइम ब्यूरो

आनन्द प्रकाश 9508451204, 8409462970

साज-सज्जा प्रबंधक

अमित कुमार 9905244479

amit.kewalsach@gmail.com

कार्यालय संवाददाता

सोनू यादव 8002647553, 9060359115

प्रसार प्रतिनिधि

कुणाल कुमार 9905203164

बिहार प्रदेश जिला ब्यूरो

पटना (श०)	:-	श्रीधर पाण्डेय	9470709185
(म०)	:-	गौरव कुमार	9472400626
(ग्रा०)	:-		
बाढ़	:-		
भोजपुर	:-	गुड्डू कुमार सिंह	8789291547
बक्सर	:-	बिन्ध्याचल सिंह	8935909034
कैमूर	:-		
रोहतास	:-	अशोक कुमार सिंह	7739706506
	:-		
गया (श०)	:-	सुमित कुमार मिश्र	7667482916
(ग्रा०)	:-		
औरंगाबाद	:-		
जहानाबाद	:-	नवीन कुमार रौशन	9934039939
अरवल	:-	संतोष कुमार मिश्रा	9934248543
नालन्दा	:-		
	:-		
नवादा	:-	अमित कुमार	9934706928
	:-		
मुंगेर	:-		
लखीसराय	:-		
शेखपुरा	:-		
बेगूसराय	:-	निलेश कुमार	9113384406
	:-		
खगड़िया	:-		
समस्तीपुर	:-		
जमुई	:-	अजय कुमार	09430030594
वैशाली	:-		
	:-		
छपरा	:-		
सिवान	:-		
	:-		
गोपालगंज	:-		
	:-		
मुजफ्फरपुर	:-	.	
	:-		
सीतामढ़ी	:-		
शिवहर	:-		
बेतिया	:-	रवि रंजन मिश्रा	9801447649
बगहा	:-		
मोतिहारी	:-	संजीव रंजन तिवारी	9430915909
दरभंगा	:-		
	:-		
मधुबनी	:-	सुरेश प्रसाद गुप्ता	9939817141
	:-	प्रशांत कुमार गुप्ता	6299028442
सहरसा	:-		
मधेपुरा	:-		
सुपौल	:-		
किशनगंज	:-		
	:-		
अररिया	:-	अब्दुल कय्यूम	9934276870
पूर्णिया	:-		
कटिहार	:-		
भागलपुर,	:-		
(ग्रा०)	:-	रवि पाण्डेय	7033040570
नवगछिया	:-		

दिल्ली कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- संजय कुमार सिन्हा
A-68, 1st Floor,
नागेश्वर तल्ला, शास्त्रीनगर, न्यू
दिल्ली-110052
संजय कुमार सिन्हा, स्टेट हेड
मो०- 9868700991, 9431073769

उत्तरप्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
9308815605

पश्चिम बंगाल कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
द्वारा- अजीत कुमार दुबे
131 चितरंजन एवेन्यू,
कोलकात्ता, पश्चिम बंगाल- 700073
अजीत कुमार दुबे, स्टेट हेड
मो०- 9433567880, 9308815605

मध्य प्रदेश कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
हाउस नं.-28, हरसिद्धि कैम्पस
खुशीपुर, चांबड़
भोपाल, मध्य प्रदेश- 462010
अभिषेक कुमार पाठक, स्टेट हेड
मो०- 8109932505,

झारखंड कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,
वैष्णवी इंक्लेव,
द्वितीय तल, फ्लैट नं- 2बी
नियर- फायरिंग रेंज
बरियातु रोड, राँची- 834001

छत्तीसगढ़ कार्यालय

केवल सच, हिन्दी मासिक पत्रिका,

....., स्टेट हेड

सम्पर्क करें
8340360961

संपादकीय व प्रधान कार्यालयः-

☞ पूर्वी अशोक नगर, रोड नं:-14, मकान संख्याः- 14/28, कंकड़बाग, पटना-800020 (बिहार) मो०- 9431073769, 9955077308

☞ e-mail:- kewalsach@gmail.com, e ditor.kstimes@rediffmail.com
kewalsach_times@rediffmail.com

☞ स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक ब्रजेश मिश्र द्वारा सांध्य प्रवक्ता खबर वर्क्स, ए- 17, वाटिका विहार (आनन्द विहार), अम्बेडकर पथ, पटना 8000 14(बिहार) एवं पूर्वी अशोक नगर, रोड नं. 14, कंकड़बाग पटना-800020 से प्रकाशित, संपादक- ब्रजेश मिश्र। RNI NO.-BIHHIN/2006/18181

☞ पत्रिका में प्रकाशित समाचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

☞ सभी प्रकार के वाद-विवादों का निपटारा पटना न्यायालय के अधीन होगा।

☞ आलेख पर कोई आपत्ति हो तो एक महीने के भीतर खंडन करें।

☞ किसी भी लेख के लिए रचनाकार/लेखक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

☞ सभी पद अवैतनिक हैं।

☞ फोटो-समाचार साभार भी (माध्यम- इंटरनेट एवं अन्य स्त्रोत)

☞ कोई भी शिकायत हमारे पते पर लिखकर भेजें।

☞ **विज्ञापन का भुगतान चेक या ड्राफ्ट एवं RTGS से ही मान्य होगा।**

☞ भुगतान Kewal Sach को ही करें। प्रतिनिधियों को नगद न दें।

☞ A/C No. :- 0600050004768
BANK :- Punjab National Bank
IFSC Code :- PUNB0060020
PAN No. :- AAJFK0065A

प्रधान संपादक
.....
.....

झारखण्ड स्टेट ब्यूरो
.....
.....

झारखण्ड सहायक संपादक
ब्रजेश कुमार मिश्र 9431950636, 9631490205
ब्रजेश मिश्र 7654122344-7979769647
अभिजीत दीप 7004274675-9430192929

उप संपादक
.....
.....

संयुक्त संपादक
अनंत मोहन यादव 9546624444, 7909076894
.....

विशेष प्रतिनिधि
भारती मिश्रा 8210023343-8863893672
.....
.....

झारखण्ड प्रदेश जिला ब्यूरो
राँची :- अभिषेक मिश्र 7903856569
:- ओम प्रकाश 9708005900
साहेबगंज :-
खूँटी :-
जमशेदपुर :- तारकेश्वर प्रसाद गुप्ता 9304824724
हजारीबाग :-
जामताड़ा :-
दुमका :-
देवघर :-
धनबाद :-
बोकारो :-
रामगढ़ :-
चाईबासा :-
कोडरमा :-
गिरीडीह :-
चतरा :- धीरज कुमार 9939149331
लातेहार :-
गोड्डा :-
गुमला :-
पलामू :-
गढ़वा :-
पाकुड़ :-
सरायकेला :-
सिमडेगा :-
लोहरदगा :-

श्री चन्द्र प्रकाश सिंह

प्रधान संरक्षक सह प्रबंध संपादक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
राष्ट्रीय संगठन मंत्री, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक)
पूर्व निदेशक सदस्य, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
09431016951, 09334110654

डॉ. सुनील कुमार

शिशु रोग विशेषज्ञ सह मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका
एवं 'केवल सच टाइम्स'
एन.सी.- 115, एसबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना- 800020
फोन- 0612/3504251

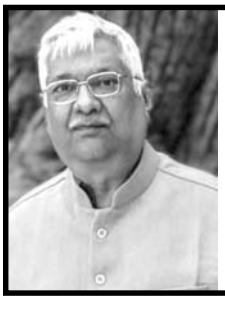

श्री सज्जन कुमार सुरेका

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
डी- 402 राजेन्द्र विहार, फॉरेस्ट पार्क
भुवनेश्वर- 751009 मो-09437029875

सुधीर कुमार

मुख्य संरक्षक सह निदेशक ''**मगध इंटरनेशनल स्कूल**'' टेकारी
'' **केवल सच** '' पत्रिका **एवं** '' **केवल सच टाइम्स** ''
9060148110
sudhir4s14@gmail.com

कैलाश कुमार मौर्य

मुख्य संरक्षक
'केवल सच' पत्रिका **एवं 'केवल सच टाइम्स'**
व्यवसायी
पटना, बिहार
7360955555

बिहार राज्य प्रमंडल ब्यूरो

पटना		
मगध		
सारण		
तिरहुत		
पूर्णिया	**धर्मेन्द्र सिंह**	9430230000 7004119966
भागलपुर		
मुंगेर		
दरभंगा		
कोशी		

विशेष प्रतिनिधि

आशुतोष कुमार	9430202335, 9304441800
सुमित राज यादव	9472110940, 8987123161
बेंकटेश कुमार	8521308428, 9572796847
राजीव नयन	9973120511, 9430255401
मणिभूषण तिवारी	9693498852
दीपनारायण सिंह	9934292882
आनन्द प्रकाश पाण्डेय	9931202352, 7808496247
विनित कुमार	8210591866, 8969722700
रामजीवन साहू	9430279411, 7250065417

छायाकार

त्रिलोकी नाथ प्रसाद	9122003000, 9431096964
मुकेश कुमार	9835054762, 9304377779
जय प्रसाद	9386899670,
कृष्णा प्रसाद	9608084774, 9835829947

प्रथम चरण के चुनाव में चार सीटों पर खिलेगा कमल या जलेगी लालटेन?

मतदान प्रतिशत में गिरावट सरकार बदलने की आहट ।
नवादा लोकसभा क्षेत्र में राजद और एनडीए के बीच घमासान में नहीं चला मोदी मैजिक और योगी का बुलडोजर ।
मतदान प्रतिशत में गिरावट से बदलती रही है सरकार ।

● **मिथिलेश कुमार**

पिछले 12 में से 5 चुनावों में मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिले है. जब-जब मतदान प्रतिशत में कमी हुई है 4 बार सरकार बदल गयी है. वहीं एक बार सत्ताधारी दल की वापसी हुई है. 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई और जनता पार्टी की सरकार सत्ता से हट गयी. जनता पार्टी की जगह कांग्रेस की सरकार बन गयी. वहीं 1989 में एक बार फिर मत प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गयी और कांग्रेस की सरकार चली गयी. विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी. 1991 में एक बार फिर मतदान में गिरावट हुई और केंद्र में कांग्रेस की वापसी हो गयी. 1999 में मतदान में गिरावट हुई लेकिन सत्ता में परिवर्तन नहीं हुआ. वहीं 2004 में एक बार फिर मतदान में गिरावट का फायदा विपक्षी दलों को मिला.

☞ **छिटपुट घटनाओं के बीच देश में शांतिपूर्ण हुआ मतदान** :- लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर शुक्रवार को शाम सात बजे तक 60.03 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. इस दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा की कुछ छिटपुट घटनाएं सामने आई, वहीं छत्तीसगढ़ में एक ग्रेनेड लांचर के गोले में दुर्घटनावश विस्फोट होने से सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई. निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि मतदान का आंकड़ा अभी केवल अनुमान आधारित है और मतदान शांतिपूर्ण एवं निर्बाध तरीके से हुआ. अगर हम बिहार में पहले चरण में होने वाले चुनाव की बात करें तो चार सीटों पर होने वाले चुनाव जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा एवं सुरक्षित सीट जमुई शामिल है. इन चार सीटों पर आमने - सामने की लड़ाई है एनडीए एवं इण्डिया गठबंधन अपने प्रत्याशियों की जीत को सुनिश्चित करने की फिराक में थी लेकिन बिहार में विपक्षी पार्टियों में मतदाताओं पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने वाली राजद ने सीट बटवारें को लेकर तय की गयी रणनीति एनडीए की राह में रोड़ा बन रही है सबसे पहले हम औरंगाबाद लोकसभा की बात करते हैं एनडीए वहाँ सुशील कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है जो लगातार सांसद हैं और क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ है वहीं राजद ने वहाँ से जदयू छोड़ कर राजद में घरवापसी करने वाले टेकारी विधान सभा के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा को टिकट दिया है. गया लोक सभा से एनडीए प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हम पार्टी से ताल ठोक रहें हैं.वहीं इण्डिया गठबंधन से

कुमार सर्वजीत राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहें हैं नवादा लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है. क्योंकि पिछले तीन बार से यहाँ भाजपा या उसके समर्थित प्रत्याशी ही चुनाव जीतते आये हैं लेकिन इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने राजद से श्रवण कुशवाहा को टिकट देकर यहाँ का समीकरण बिगाड़ दिया है यहाँ तक की नवादा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा को प्रधानमंत्री समेत दर्जनों केंद्रीय मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी सहारा लेना पड़ा हैं. जमुई लोकसभा की बात करें तो वहाँ से लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को टिकट दिया हैं वहीं राजद ने अर्चना रविदास को अपना प्रत्याशी बनाया हैं अब चार लोकसभा सीटों का समीकरण की ताजा स्थिति में इण्डिया गठबंधन का पलड़ा भारी दीखता हैं.

☞ **चार लोकसभा क्षेत्र की भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति :-** बिहार-झारखंड की सीमा पर स्थित औरंगाबाद को मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। यह सीट हमेशा सुर्खियों में रही है। अदरी नदी के तट पर स्थित इस शहर को पहले नौरंगा कहा जाता था। बाद में इसका नाम औरंगाबाद हो गया। 26 जनवरी 1973 को औरंगाबाद मगध प्रमंडल के गया जिले से हटकर स्ववतंत्र जिला बना। जीटी रोड एवं औरंगाबाद-पटना रोड जिले की लाइफलाइन मानी जाती हैं। औरंगाबाद जिले में दो अनुमंडल-औरंगाबाद सदर एवं दाउदनगर है। इस जिले में 11 प्रखंड हैं। यहां की 70 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है। हालांकि यहां सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो सकी है। औरंगाबाद की सियासत में कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहां की राजनीति बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह के परिवार के इर्द-गिर्द घूमती रही है। यहां के पहले सांसद सत्येंद्र नारायण सिंह थे। कांग्रेस पार्टी यहां से नौ बार विजयी रही है। पहली बार 1989 में सत्येंद्र नारायण सिन्हा के परिवार को हार का सामना करना पड़ा था, तब रामनरेश सिंह ने जनता दल के टिकट पर जीत दर्ज की थी। 2014 में इस सीट पर पहली बार भाजपा का खाता खुला और सुशील कुमार सिंह सांसद बने। 2019 में भी सुशील कुमार सिंह ने यहां से भाजपा को विजय दिलाई। विधानसभा सीटें और विकास औरंगाबाद लोकसभा सीट के तहत कुटुंबा,रफीगंज, इमामगंज, गुरुआ, टिकारी विधानसभा सीटें आती हैं। औरंगाबाद जिला नक्सल प्रभावित है। यहां 1987 से 2000 तक कई नरसंहार हुए। यहां की सिंचाई व्यवस्था अब भी अधूरी है। 1970 के दशक के शुरू सेउत्तर कोयल नहर परियोजना अब तक अधूरी है। हड़ियाही परियोजना का भी यही हाल है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की भी यही हालत है। औरंगाबाद रेल सेवा से अब तक नहीं जुड़ा है। प्रमुख घटनाएं और मुद्दे 2016 में नक्प्सलियों से मुठभेड़में सीआरपीएफ के दस जवान शहीद हो गए थे। 2019 में भाजपा विधान पार्षद के घर पर नक्सलियों की हत्या, दर्जन भर वाहन फूंके गए और उनके चाचा की हत्ध्या की गई। औरंगाबाद-गया सीमा पर नक्प्सली हमले में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए। यहां के प्रमुख मुद्दों में उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना एवं हड़ियाही सिंचाई परियोजना हैं। इनके अलावा पर्यटन स्थल देव को सूर्य सर्किट में शामिल करना, हड़ियाही सिंचाई परियोजना को पूर्ण करना,उमगा एवं पवई पहाड़ का सौंदर्यीकरण, नक्सलवाद, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, औरंगाबाद को रेलमार्ग से जोड़ना आदि भी यहां के प्रमुख मुद्दे हैं। हालांकि उत्तर कोयल परियोजना का प्रधानमंत्री ने इसी साल शिलान्यास कर दिया है। यहां कुल मतदाताओं की संख्या-13,76,323, जिले की कुल जनसंख्या-25,40,073 और साक्षरता दर 70.32 प्रतिशत है। औरंगाबाद की खास बातें औरंगाबाद बिहार का महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। प्राचीन काल में औरंगाबाद, मगध राज्य का हिस्सा था। इस क्षेत्र के उमगा में एक वैष्णव मंदिर है। इसे उमगा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहां सूर्य देव मंदिर धार्मिक रूप से महत्व्वपूर्ण है। औरंगबाद में विद्युत उत्पादन के लिए एनटीपीसी का बड़ा प्लांट भी है। यहां सीमेंट उत्पादन, कालीन और कंबल बनाने के कारखाने भी हैं। यह क्षेत्र प्रदेश की राजधानी पटना से करीब 148 किलोमीटर दूर है।

जमुई लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा क्षेत्र हैं. जिनमें जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटें- जमुई, सिकंदरा, झाझा और चकाई हैं जबकि एक तारापुर विधानसभा सीट मुंगेर जिले में है और शेखपुरा विधानसभा सीट शेखपुरा जिले में है. इन 6 विधानसभा सीटों में 4 पर छवा का कब्जा है जबकि दो सीटों पर आरजेडी काबिज है।

☞ **1941 बूथों पर हुई वोटिंग :-** जमुई लोकसभा सीट पर वोटिंग के लिए कुल 1941 मतदान केंद्र बनाए गये थे. मतदान केंद्रों पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए

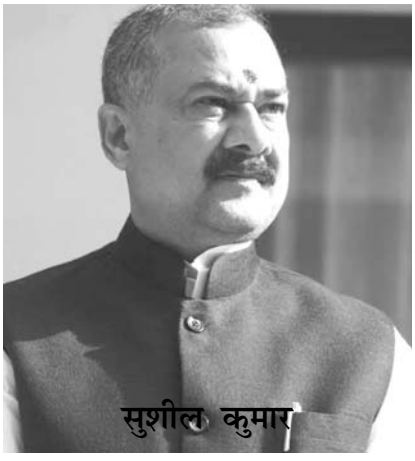
सुशील कुमार

सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गये थे. इसके लिए सुरक्षाबलों की 35 कंपनियां तैनात की गयी थीं. जिनमें पैरा मिलिट्री फोर्स और एंटी नक्सल फोर्स भी शामिल थीं.

☞ **जमुई लोकसभा सीट पर कितने मतदाता ? :-** जमुई लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 19 लाख 7 हजार 126 है. इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9 लाख 97 हजार 209 है जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 9 लाख 9 हजार 866 है. इसके अलावा थर्ड जेंडर के भी 51 मतदाता हैं.2019 में चिराग पासवान को मिली थी जीत: 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो एलजेपी के चिराग पासवान ने आरएलएसपी के भूदेव चौधरी को करीब ढाई लाख वोट के अंतर से हराया था. इस चुनाव के दौरान एलजेपी को 55.76 फीसदी वोट मिले थे जबकि आरएलएसपी को 30.34 फीसदी वोट मिले थे. इसके अलावा अन्य उम्मीदवारों को 9. 74 फीसदी और नोटा में 4.16 फीसदी वोट पड़े थे.जमुई लोकसभा क्षेत्र जंगल और पहाड़ के साथ साथ नक्सली प्रभावित इलाका भी है. नवादा लोकसभा क्षेत्र में छ: विधान सभा क्षेत्र है जिसमें नवादा, रजौली, हिसुआ, गोविंदपुर, वारिसलीगंज एवं बरबीघा विधान सभा क्षेत्र है.

☞ **नवादा लोकसभा क्षेत्र में बदलती रही राजनैतिक परिदृश्य :-** हालांकि परिणाम की बात करें तों नवादा संसदीय क्षेत्र में महागठबंधन के घटक दलों एवं एनडीए में सीधी भिड़ंत होने की संभावना बन रही हैं लेकिन राजद से पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव को सिंबल नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी बनने पर राजद को नुकसान पहुंच सकती हैं जिसका फायदा एनडीए को मिल सकता हैं. बिहार झारखंड सीमा का नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र राजनीति का प्रयोग शाला रहा है। चुनाव के दौरान जातीय समीकरण के हावी रहने से विकास का मुद्दा गौण हो जाता है।

बिहार का कश्मीर के नाम से प्रचलित ककोलत जलप्रपात इसी क्षेत्र में है। नवादा संसदीय क्षेत्र कौआकोल का रानीगदर मानव सभ्यता का उदय स्थल रहा है। यह सप्तऋषियों की तपोभूमि रही है। रामायण और महाभारत काल के कई प्रसंग यहां की जनश्रुतियों में आज भी कही-सुनी जाती

अभय कुशवाहा

हैं। महावीर व बुद्ध ने इस धरती से विश्व को अंहिसा और शांति का संदेश दिया है। मौर्य साम्राज्य का अंश रही नवादा नगरी राजनीति की प्रयोगशाला रही है। आजादी के बाद वर्ष 1951 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में नवादा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रजेश्वर प्रसाद व रामधनी दास संयुक्त रूप से सांसद रहे। अगले चुनाव में ही नवादा से पहली महिला सत्यभामा देवी संसद की सीढियां चढ़कर सदन तक पहुंची। डेढ़ दशक तक इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा रहा। लेकिन वर्ष 1967 में पकरीबरावां क्षेत्र के बुधौली मठ के महंथ सूर्य प्रकाश नारायण पुरी स्वतंत्र रूप से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वापसी की और पार्टी के सुखदेव प्रसाद वर्मा चुनाव जीता। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में यहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और 1977 के आम चुनाव में भारतीय लोक दल के नथुनी राम सांसद रहे।

1980 में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस सांसद कुंवर राम को जीत मिली और वे 1989 तक सांसद रहे। इसके बाद से आज तक नवादा सीट पर कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकी

अर्चना रविदास

अरूण भारती

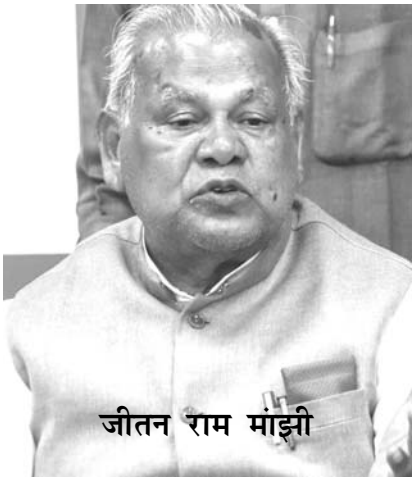
जीतन राम मांझी

। लोकसभा चुनाव 1989 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेम प्रदीप विजयी रहे। पहली बार भारतीय जनता पार्टी प्रमुख दल के रूप में उभरी। हालांकि पार्टी के कामेश्वर पासवान चुनाव हार गए और दूसरे स्थान पर रहे। वर्ष 1991 में माकपा से प्रेमचंद राम जीते। 1996 में भाजपा के कामेश्वर पासवान ने जीत दर्ज की। लेकिन 1998 में हुए मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार मालती देवी ने इन्हें हरा दिया। 1999 के चुनाव में यह फिर भाजपा की सीट रही। नए सहस्राब्दी के साल 2004 में हुए पहले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के वीरचन्द पासवान संसद पहुंचे। इसके बाद से नवादा संसदीय सीट पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का कब्जा है। 2009 में भोला सिंह और 2014 में गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे। जबकि 2019 में राजग की सहयोगी पार्टी लोकजन शक्ति के चंदन कुमार सांसद रहे।

☞ **आजादी के बाद कई बार बदला है नवादा संसदीय क्षेत्र :-** आजादी के बाद पहले आम चुनाव से लेकर अबतक इसकी सीमाओं में काफी परिवर्तन हुआ है। वर्ष 1957 से पहले यह गया पूर्वी संसदीय सीट का हिस्सा था। इसके बाद नए परिसीमन के तहत संसदीय क्षेत्र संख्या-34 के रूप में इसका गठन हुआ। अगले लोकसभा चुनाव के पूर्व साल 1962 में यह बदलकर संसदीय क्षेत्र संख्या-42(सुरक्षित) के रूप में अस्तित्व में आया, जो करीब चार दशक तक अपने स्वरूप में रहा। इस दौरान गया जिले का अतरी विधानसभा क्षेत्र इसका हिस्सा हुआ करता था। नए सहस्राब्दी के प्रारम्भ में वर्ष 2004 में फिर से इसका परिसीमन बदला और यह संसदीय क्षेत्र संख्या-39 के नए कलेवर में सामने आया। वर्तमान में रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविन्दपुर, वारिसलीगंज और शेखपुरा जिले का बरबीघा विधानसभा क्षेत्र इसमें शामिल है।

श्रवण कुशवाहा

☞ **जातीय समीकरण और स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा है हावी :-** नवादा लोकसभा सीट लंबे समय तक जातीय हिंसा और नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। प्रत्येक चुनाव में विकास के मुद्दे

गौण ,कास्ट फैक्टर हावी रहता है। भूमिहार और यादव बहुल इस क्षेत्र में राजनीति की धूरी इन दो जातियों के इर्द-गिर्द घूमती है। हालांकि कुशवाहा और वैश्य समाज के अलावा मुस्लिम वोटर भी जीत-हार के बड़े फैक्टर है। वर्ष 2009 में परिसीमन बदलने के बाद यह सामान्य सीट हो गई। जिसके बाद राजग ने इस सीट से भूमिहार प्रत्याशियों के लिए दरवाजा खोल दिया। परिणाम भी दिखे । इस बार के चुनाव में स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा भी हावी रहेगा।

☞ **प्रत्याशियों की जीत-हार में महिलाएं दिखा रहीं दम-खम :-** पिछले कुछ चुनावों से महिलाओं की भागीदारी अव्वल रही है। पुरुषों की अपेक्षा उनका मतदान प्रतिशत कहीं अधिक है। लोकसभा चुनाव 2019 में नवादा जिले के 48.76 फीसदी पुरुषों ने मतदान किया, तो 49.

कुमार सर्वजीत

76 फीसदी महिला मतदाताओं ने अपना वोट डाला। पुरूषों से महिलाएं दो कदम आगे ही रही। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी पुरुषों की अपेक्षा 3.36 फीसदी अधिक महिला वोटरों ने मताधिकार का प्रयोग किया था। गांव-नगर की सरकार हो या संसद की। महिलाएं प्रत्याशियों के जीत-हार में अपना दम-खम दिखा रही है।

☞ **समीकरण के आधार पर राजद ने बनाया पकड़ :-** सिर्फ मोदी लहर और कोर वोटरों पर निर्भर रहना भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर को कहीं महंगा न पड़ जाय. पहले चरण में हुए मतदान ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है. भाजपा को नवादा सीट पर कड़ी टक्कर मिली है. इसके पीछे की कई वजहें हैं, जिनमें नवादा में बाहरी प्रत्याशी को उतारना भाजपा के लिए गले की फांस साबित होते हुई दिख रही है. इसके साथ हीं भीतरघात की भी खबर है. कोर वोटरों में भाजपा प्रत्याशी को लेकर कोई उत्सुकता नहीं रही. लिहाजा भाजपा के परंपरागत वोटर मतदान कराने को लेकर सक्रिय नहीं दिखे. असर यह हुआ कि पोलिंग प्रतिशत काफी कम रहा. साथ

विवेक ठाकुर

नवादा संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सांसद व पार्टी

1952	ब्रजेश्वर प्रसाद	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (गया-पूर्व-एससी के रूप में)
1952	राम धनी दास	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (गया-पूर्व-एससी)
1957	सत्यभामा देवी	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1957	राम धनी दास	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1962	राम धनी दास	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1967	सूर्य प्रकाश पुरी	स्वतंत्र
1971	सुखदेव प्रसाद वर्मा	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1977	नथुनी राम	भारतीय लोक दल
1980	कुंवर राम	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1984	कुंवर राम	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
1989	प्रेम प्रदीप	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
1991	प्रेम चंद राम	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
1996	कामेश्वर पासवान	भारतीय जनता पार्टी
1998	मालती देवी	राष्ट्रीय जनता दल
1999	डॉ. संजय पासवान	भारतीय जनता पार्टी
2004	वीरचंद पासवान	राष्ट्रीय जनता दल
2009	डॉ. भोला सिंह	भारतीय जनता पार्टी
2014	गिरिराज सिंह	भारतीय जनता पार्टी
2019	चन्दन सिंह	लोक जनशक्ति पार्टी

नवादा संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या (15.03.2024 के अनुसार)

विधानसभा	पुरुष	महिला	थर्ड जेंडर	कुल
रजौली	174535	162476	19	337030
हिसुआ	201003	184822	49	385874
नवादा	188757	174828	14	363599
गोविन्दपुर	168984	155804	34	324822
वारिसलीगंज	186911	171527	33	358471
नवादा जिला	920190	849457	149	1769796
बरबीघा	122122	111585	1	233708

ही सहयोगी दल जेडीयू का भी भरपूर साथ नहीं मिला. लव-कुश समाज के वोटरों ने भी भाजपा प्रत्याशी को गच्चा दिया. लव-कुश समाज के वोटरों ने फूल की बजाय कुल(जाति) को पसंद किया है. कुल मिलाकर कहें तो नवाद सीट पर भाजपा संकट में है.

पहले चरण में हीं नवादा में मतदान संपन्न हो गया है. मतदान के बाद अब हार-जीत की चर्चा शुरू हो गई है. कौन प्रत्याशी हार रहा और किन्हें जीत मिल रही, इस पर चर्चा शुरू है. भीतरघात की भी खूब चर्चा हो रही. भाजपा के कोर वोटरों की नाराजगी पर भी बात हो रही है. नवादा में भाजपा ने राज्य सभा सांसद विवेक ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा. विवेक ठाकुर नवादा संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक नहीं रखते हैं. बाहरी को टिकट दिए जाने के बाद भाजपा के अंदर ही भारी नाराजगी देखने को मिली थी. इस सीट पर भाजपा के कई स्थानीय और मजबूत दावेदार थे. लेकिन बीजेपी ने बाहरी विवेक ठाकुर को प्रत्याशी बना दिया. इससे अंदर ही अंदर कई नेता नाराज हो गए. कहा जाने लगा कि नेतृत्व ने हम पर बाहरी उम्मीदवार जबरन थोप दिया है,जिसे हम मंजूर नहीं करेंगे. हालांकि नेतृत्व ने नाराज नेताओं को मना लिया. इसके बाद नाराज नेता विवेक ठाकुर के पक्ष में बेमन से प्रचार करने लगे. इनकी उम्मीदवारी को न सिर्फ नेता बल्कि नवादा के लोग भी पचा नहीं पाए. खबर है कि अंदर ही अंदर भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ जमकर भीतरघात हुआ है. कोर वोटरों ने भी विवेक ठाकुर को बेमन से स्वीकार किया. इसका प्रभाव वोटिंग पर भी पड़ा. कोर वोटर घरों से निकले नहीं या अनमने ढंग से वोट किया. लिहाजा वोट प्रतिशत काफी कम रहा. इसका नुकसान भाजपा प्रत्याशी को सीधे तौर पर होते दिख रहा है.

☞ **वारिसलीगंज में सीएम की चुनावी सभा में ही खुल गई थी पोल :-** वोटिंग से पहले भी चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी को लेकर

लोगों में कोई उत्साह नहीं दिखा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वारिसलीगंज में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे. चुनावी सभा में भीड़ देकर उसी दिन अनुमान लग गया था कि कैंडिडेट के पक्ष में कोई लहर नहीं है. कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की सभा पांच-छह सौ लोग ही पहुंचे थे. मंच से स्थानीय विधायक अरूणा देवी ने इसे स्वीकार किया था. सभा को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक ने लोगों की कम संख्या पर सफाई दी थी और कहा था कि टाइमिंग सही नहीं होने की वजह से कम भीड़ है. दोपहर 11 बजे के बाद काफी गर्मी हो जा रही है. इसी वजह से लोग नहीं आये . जानकार बताते हैं कि भाजपा के स्थानीय नेता-कार्यकर्ता ही अपने प्रत्याशी को पचा नहीं पा रहे थे. नेता-कार्यकर्ता सिर्फ शरीर से भाजपा प्रत्याशी के साथ थे, मन से नहीं. नतीजा हुआ कि विवेक ठाकुर के पक्ष में माहौल नहीं बन पाया.

☞ **भाजपा के समीकरण वाला वोट राजद के पक्ष में चला गया :-** जानकार बताते हैं कि रही-सही कसर कसर जेडीयू से जुड़े वोटरों ने पूरी कर दी. बताया जाता है कि नवादा संसदीय क्षेत्र में कुशवाहा वोटरों की पहली पसंद राजद बन गया. राजद ने इस सीट से श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था. इसका लाभ भी मिलते दिखा. बताया जाता है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में अधिकांश कुशवाहा वोटरों ने राजद के पक्ष में मतदान किया है. वहीं कहीं-कहीं कुर्मी वोटरों का झुकाव भी राजद के पक्ष में रहा. खबर है कि इस बार अशोक महतो फैक्टर भी काम किया है. जिस वजह से अशोक महतो के प्रभाव क्षेत्र वाले इलाके में कुर्मी वोटरों ने राजद के पक्ष में मतदान कर दिया. नीतीश कुमार के गठबंधन की वजह से भाजपा जिस वोट को अपना बता रही थी वह भी राजद के पाले में जाते दिखा. विवेक ठाकुर से नाराज भाजपा के कोर वोटरों ने निर्दलीय प्रत्याशी गुंजन सिंह के पक्ष में वोटिंग किया है. बरबीघा, वारिसलीगंज समेत कई अन्य

इलाकों में नौजवान वोटरों ने निर्दलीय गुंजन सिंह के पक्ष में मतदान किया है.ऐसी खबर आ रही है.

☞ **भाजपा प्रत्याशी को मोदी लहर और निर्दलीय प्रत्याशी विनोद यादव पर ही भरोसा :-** भाजपा को अब सिर्फ पीएम दी मोदी लहर और निर्दलीय विनोद यादव पर ही भरोसा है. विनोद यादव कद्दावर नेता राजवल्लभ यादव के भाई है. राजद से बगावत कर विनोद यादव नवादा सीट से चुनावी मैदान में हैं. वे अपने आप को राजद का असली नेता बताकर वोट मांगा है. लेकिन इस बार के चुनाव में राजवल्लभ परिवार का जादू चलते हुई नहीं दिखा. नवादा आसापास के क्षेत्र के छोड़ दें तो यादव वोटरों में बड़ी सेंध लगाने में विनोद यादव सफल नहीं हो सके हैं. खबर है कि विनोद यादव अपनी जाति का तीस फीसदी वोट से ज्यादा काटने में कामयाब नहीं हुए हैं.

बहरहाल प्रथम चरण के चुनाव में जातिगत समीकरण एवं क्षेत्रवाद के साथ साथ गठबंधन धर्म में घटक दलों की प्रतिष्ठा भी दाव पर लगी है नीतीजे भी आश्चर्यचकित करने वाले हों सकते है खासकर औरंगावाद एवं नवादा की सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है नवादा लोकसभा में जीत का मार्जिन कम हो सकता है जिसे दोनों दलों के प्रत्याशी समझ रहें है लेकिन सबों की नजर चार जून पर टिकी है. फल्गु नदी के तट पर बसा गया कई छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरा है। इसे मोक्ष और ज्ञान की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि फल्गु में तर्पण-अर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोधगया वह भूमि है, जहां ज्ञान पाकर राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बने। यहां बड़े कल-कारखाने नहीं हैं। यहां की पटवा टोली में बुनकरों की बड़ी तादाद है, जहां कपड़े तैयार किए जाते हैं। सैकड़ों लोग कुटीर उद्योग से जुड़े हैं। गया संसदीय क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। झारखंड की सीमा से सटा यह क्षेत्र नक्सल प्रभावित भी है। जिले के 24 प्रखंडों में शहर को छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में नक्सल समस्या व्याप्त है। नक्सालियों पर नकेल के लिए सीआरपीएफ की स्थायी बटालियन भी तैनात है। यहां सेना की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। गया संसदीय सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। गया जिले में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें छह विधानसभा क्षेत्र गया संसदीय क्षेत्र में आते हैं। गया संसदीय क्षेत्र में गया, बोधगया, बेलागंज, शेरघाटी, बाराचट्टी और वजीरगंज विस क्षेत्र शामिल है। इतिहास और बड़ी घटनाएं 1952 से 2014 तक यहां से छह बार कांग्रेस, एक बार प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी, एक बार जनसंघ, एक बार जनता पार्टी, चार बार जनता दल, एक बार राजद और चार बार भाजपा विजयी रही है। गया में कुल मतदाताओं की संख्या 28,62,060 है। यह देश के अति पिछड़े जिलों में शामिल है, जिसके लिए विशेष योजनाएं दी गई हैं। जिले की कुल जनसंख्या0 43,91,418 है और साक्षरता दर 52.38 फीसद है। गया की खास बातें गया बिहार के 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्रों को समाहित किया गया है। फाल्गुनी नदी के तट पर बसा यह शहर झारखंड की सीमा से जुड़ता है। ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से यह बिहार का सबसे महत्वपूर्ण नगर है। पितृपक्ष पर हजारों लोग पिंडदान के लिए यहां जुटते हैं। इस क्षेत्र से कुछ दूरी पर बोधगया स्थित है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहां का विष्णुपद मंदिर पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। इस क्षेत्र का उल्लेख महाकाव्य रामायण में भी मिलता है। गया मौर्य काल में एक महत्वपूर्ण नगर था। मध्यकाल में यह शहर मुगल सम्राटों के अधीन था। यहाँ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत आमने सामने है चुनाव के बाद की स्थिति में महागठबंधन प्रत्याशी आगे है।●

दो चरणों पर संपन्न चुनाव
किसकी प्रतिष्ठा दांव पर?

लोकसभा निर्वाचन चुनाव में द्वितीय चरण के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है.प्रथम चरण चुनाव के अनुपात में दूसरे चरण के चुनाव में वोट का प्रतिशत बढ़ने एवं सियासी हलकों में राजद के टिकट देने में जातीय समीकरण ने एनडीए गठबंधन को पानी पीने पर मजबूर कर दिया है प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री अमित शाह का लगातार बिहार दौरा इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि 2019 में हुए लोकसभा के चुनाव का लहर एनडीए के पक्ष में नहीं दिख रहा है। भाजपा के राष्ट्रबाद, हिंदुत्व, राम मंदिर निर्माण, कश्मीर में धारा 370 को हटाने, तीन तलाक आदि मुद्दों को भुनाने की जो विसात बिछाई थी उसमें मतदाता रूचि नहीं ले रहें हैं. इण्डिया गठबंधन खासकर बिहार में एनडीए के प्रत्याशियों को रात की नींद और दिन का चौन छीन लिया है. भाजपा नेताओं के द्वारा आपने चुनावी जनसभा में लगातार लालू राबड़ी के कार्यकाल पर हमला एवं कांग्रेस के 70 सालों का कार्यकाल के नाकामियों पर प्रहार करना यह सब पुरानी बात हो गयी है. दूसरे तरफ राजद के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री पर सीधे हमले कर उनकी बेचौनी बढ़ा रहें हैं. देखने वाली बात यह है यह की बिहार में न तो मोदी मैजिक काम कर रहा हैं नहीं नीतीश कुमार का न्याय के साथ विकास बाली कहानी काम कर रही हैं. दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव की समीक्षा करें तो एनडीए को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. लोकसभा के दूसरे फेज के पांच लोकसभा सीटों पर संम्पन्न हुए चुनाव पर प्रस्तुत है सहायक सम्पादक **मिथिलेश कुमार** की समीक्षात्मक रिपोर्ट :-

लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी प्रेस कॉन्फेंस कर विपक्ष पर निशाना साधा है। शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया एलाइंस पूरी तरह चुनाव हार रहे हैं, लेकिन वह इस चुनाव में ही देश की जनता को डराना चाहते हैं, कांग्रेस की नजर भारत के लोगों की संपत्ति पर है और यही वजह है कि आज से पहले भी उन्होंने घोषणा पत्र में संपत्ति के सर्वे की बात की, स्त्री धन और गुप्त धन जो होता है उसकी बात की, यह पूरी तरह अर्बन नक्सल के प्रभाव में है। कांग्रेस अर्बन नक्सल जिस तरह से देश के लोगों की संपत्ति लूटकर बांट देना चाहते हैं देश में। जो उनके भाषण का पार्ट होता था आज वही पार्ट यूपीए का हो गया है। उन्होंने कहा कि, इस बात पर विवाद था ही कि जो देश की संपत्ति है उसको सर्वे करके, सोना के बारे में सर्वे करके, उसको लोगों के बीच में बाटेंगे, लेकिन कांग्रेस बैक फुट पर नजर आ रही थी। कांग्रेस पार्टी बैक फुट पर थी, लेकिन सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस की इस हरकत को जग जाहिर कर दिया और अब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिस तरह अमेरिका में 55% जो संपत्ति होती है विरासत की वह सरकारी खजाने में चली जाती है तो यह लोगों की जीवन भर की कमाई को सरकारी खजाने में डालना चाहते हैं और उसका फिर बंटवारा करना चाहते हैं। इनका जो मकसद था वह यूपीए काल में भी उनकी प्राथमिकता यही थी । शाहनवाज हसैन ने कहा कि हम लोगों ने

कहा है कि भारत की संपत्ति पर भारत के लोगों का अधिकार है, किसी घुसपैठियों का नहीं। भारत में हर जात धर्म के लोग रहते हैं । बहुत गरीब हैं जब अनाज हम देते हैं लोगों को तो उनके लिए देते हैं। आयुष्मान भारत का कार्ड देते हैं तो कोई भेदभाव के भी ना देते हैं। अकाउंट में पैसा डालते हैं, तब भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस की नजर और उनके साथियों की नजर अब विरासत पर भी है। कांग्रेस पार्टी को तुरंत देश से माफी मांगना चाहिए और सर्वे की बात जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कही है । उस पंक्ति को वापस लेना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीब का है, दलित का है, आदिवासी का है, पिछडों का है। जब हम गरीब कहते हैं तो इसमें कोई जात धर्म नहीं आती। हम सबके लिए करते हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की सियासत कर रही है। जिसको हम कहीं से भी स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं पिछले 10 साल में हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने गांव गरीब दलित वंचित शोषित महिला युवाओं और किसानों के लिए काम किया है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में 90% गांव को जोड़ा है। डेढ़ लाख पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का काम किया। इस तरह प्रधानमंत्री अन्य योजना में 5 किलो चावल गेहूं और 1 किलो दाल 80 करोड़ लोगों को मिला है। इसी तरह जल जीवन मिशन में हमने पहुंचाने का काम किया है और 11 करोड़ 88 लाख लोगों को हर चौथे महीने 2000 अकाउंट में भी डाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में किसान सम्मान निधि और गरीब कल्याण योजना चलाई जो जारी रहेगी। देश के आर्थिक स्थिति में देश आगे बढ़ रहा है। 2014 में जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत 11 स्थान पर था। आज वह पांचवा स्थान पर अर्थव्यवस्था आ चुकी है और फिर से मौका मिलेगा तो तीसरे स्थान पर इसको पहुंचाएंगे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो। 2 वर्षों में ही तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुंच जाएगी, इसलिए यह मौका देश की जनता खोना नहीं चाहती। आज ऑटोमोबाइल में हमने जापान को भी पछाड़ कर तीसरे स्थान पर आए हैं। एप्पल का मोबाइल अब भारत में बन रहा है। हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी 55 करोड़ गरीब लोगों को 500000 हर साल उसके इलाज के लिए दे रहे हैं। आज हम लोगों ने सब समाज की चिंता की है यहां तक के किन्नर समाज को

भी इसमें शामिल किया है। अभी हम लोगों ने घोषणा पत्र में कहा है कि जो 70 साल के बुजुर्ग है उनको भी चाहे वह आर्थिक रूप से ठीक नहीं है उनकी चिंता नरेंद्र मोदी करेंगे।

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हमने पूरे देश के अंदर आज ऐसी स्थिति बनाई है कि जो सामने घमंडीया गठबंधन है जो आधे तो जेल में है आधे बेल पर है। वह इस तरह की बातें करते रहते हैं लेकिन उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग कांग्रेस से यह मांग करते हैं कि कांग्रेस वालों ऐसा काम ना करो। घुसपैठयों की खातिर देश की संपत्ति का बंटवारा करने का इरादा मत करो। जब हम घुसपैठयों की बात करते हैं तो उसको किसी मजहब का नाम धर्म का नाम हमारे नेता ने कभी लिया नहीं। शाहनवाज ने कहा कि बिहार में फर्स्ट फेज में हम सारी की सारी सीट जीत रहे हैं। सेकंड फेस के अंदर भी पांचों सीट पर हम जीत का परचम लहराएंगे। जिसमें भागलपुर बांका, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया यह जो सीमांचल का क्षेत्र है यहां पर भी पिछली बार भी परचम लहराया था, इस बार भी रिकॉर्ड वोटो से भागलपुर बांका पूर्णिया किशनगंज कटिहार यह हम लोग जीतने वाले हैं। दूसरे तरफ विपक्ष बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पांच किलो मुफ्त अनाज के बदले रोजगार के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खडी कर रही है. बिहार के 39 सांसद के द्वारा किये गए योगदान एवं केंद्र के दस बर्षों के शाशन काल की उपलब्धियों के साथ बिहार को बिशेष राज्य का दर्जा देने जैसे कई मुद्दों को प्रधानमंत्री की चुप्पी पर हमलावर है। ऐसे में अब तक दो फेज में बिहार के 9 लोकसभा सीटों पर चुनाव मतदान संपन्न हो चुके हैं। दूसरे फेज यानि 26 अप्रैल को पांच सीटों को लेकर हुए मतदान और उस क्षेत्र के राजनीतिक मंथन को जानते हैं। शुरूआत हम बांका लोकसभा सीट से करेंगे।

बांका बिहार राज्य का एक जिला और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है. इस जिले का मुख्यालय भी यहीं है. यह जिला बिहार राज्य के सुदूर दक्षिण-पूर्व में स्थित है. जिले की पूर्वी और दक्षिणी सीमा झारखंड राज्य के गोड्डा जिले के साथ मिलती है. यह बिहार के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक है. बांका संसदीय क्षेत्र में कुल छह विधानसभा सीटें हैं, जिनमें सुल्तानगंज, अमरपुर, धोरैया, बांका, कटोरिया और बेलहर विधानसभा सीटें आती हैं. धोरैया विधानसभा सीट अनुसूचित जाति (एससी) और कटोरिया विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सुरक्षित है. बिहार के बांका जिले में एसटी की आबादी 75 हजार से ज्यादा है. बांका संसदीय इलाका 3,020 वर्ग किमी के दायरे में फैला हुआ है. यहां 11 प्रखंड और 2 नगर निगम हैं. इस क्षेत्र में 2 हजार गांव आते हैं और साक्षरता 58.17 प्रतिशत है.मंदार हिल के कारण बांका शहर ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है जहां हिंदू रीति-रिवाजों से समुद्र मंथन हुआ था. महाकाव्यों और पुराणों में संरक्षित परंपराओं के अनुसार, मनु के प्रपौत्र अनु के वंशजों ने पूर्व में अनाव साम्राज्य की स्थापना की. बाद में, यह राज्य राजा बलि के पांच पुत्रों में विभाजित हो गया. अंग के राजाओं और अयोध्या के राजा दशरथ के मित्र थे. उनका परपोता चंपा था जिसके बाद अंग की राजधानी का नाम बदलकर चंपा कर दिया गया. अंग, मगध के साथ, सबसे पहले वैदिक साहित्य में अथर्ववेद संहिता में इनका उल्लेख मिलता है जो बौद्ध धर्मग्रंथों में उत्तरी भारत के विभिन्न राज्यों में अंग का उल्लेख है. जो अब बांका जिले का इतिहास बन गया है. बांका जिले का गठन 21 फरवरी 1991 को हुआ था.यहां के पर्यटक स्थलों में जेस्थ गौर मठ, पापरनी, लक्षदीप मंदिर प्रमुख है.साल 2011 की जनगणना के अनुसार बांका संसदीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या 20 लाख 34 हजार 763 है. इसका प्रशासनिक प्रभाग भागलपुर मंडल में आता है. 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बांका लोकसभा सीट से कुल 20 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे. जेडीयू से गिरिधारी यादव, आरजेडी से जय प्रकाश नारायण यादव, मैदान में थे, तो

जयप्रकाश नारायण यादव

गिरधारी यादव

वहीं पूर्व सांसद पुतुल कुमारी निर्दलीय उम्मीदवार थी. बांका लोकसभा सीट पर 58% मतदान दर्ज किया गया था.इस सीट पर जदयू के गिरिधारी यादव ने जीत दर्ज की, उन्हें 4,77,788 वोट मिले थे. तो वहीं आरजेडी के जय प्रकाश नारायण 2,77,256 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे और निर्दलीय उम्मीदवार पुतुल कुमारी 1,03,729 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर थे.

☞ **बांका लोकसभा :-**

☞ **2014 का जनादेश :-** बांका लोकसभा सीट से 2014 के चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी जय प्रकाश नारायण यादव को जीत मिली थी. उन्होंने 2 लाख 85 हजार 150 वोट हासिल किए थे और करीबी प्रत्याशी पुतुल कुमारी को हराया था. पुतुल कुमारी ने यह चुनाव तो निर्दलीय लड़ा था, लेकिन बाद में बीजेपी ज्वॉइन कर ली थी. इस चुनाव में पुतुल कुमारी को 2 लाख 75 हजार 6 वोट प्राप्त हुए थे. पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 57.48 फीसदी मतदान हुआ था. वहीं, जयप्रकाश नारायण यादव को 31.71 फीसदी और पुतुल कुमारी को 30.58 प्रतिशत वोट मिले थे. पुतुल कुमारी पूर्व मंत्री स्व. दिग्विजय सिंह की धर्मपत्नी हैं. इस चुनाव में 9 हजार 7 सौ 53 लोगों ने नोटा बटन दबाया था. इस बार भी जदयू कोटे से गिरधारी यादव मैदान में हैं वहीं इण्डिया गठबंधन से राजद प्रत्याशी सुरेन्द्र प्रसाद यादव हैं. अगर 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें गिरधारी यादव की भी छवि आम मतदाताओं को लुभाने लायक नहीं रही हैं जनता गिरधारी यादव से भी मुंह फेरने की फिराक में हैं लेकिन उसके पास विकल्प में कुछ नहीं है जातीय समीकरण में जहां एनडीए प्रत्याशी को यादव, कुशवाहा, सवर्ण एवं अन्य पिछडी जातियों का वोट के साथ साथ अनुसूचित जाति का भी वोट मिलने की संभावना है लेकिन अगर राजद प्रत्याशी की बात करें तो यादवों का वोट का बटवारा के साथ अन्य जातियों का वोट कितना समेट पाते हैं उस पर निर्भर करता है. राजनितिकारों का कहना हैं की राजद ने सीट बटवारें में

जो समीकरण का इस्तमाल किया है उसका सीधा असर सभी लोकसभा सीटों पर है. अगर राजद बांका से यादव को छोड़कर किसी अन्य जाति से प्रत्याशी बनाता तो निश्चित तौर पर उलट फेर होने की आशंका थी बाबजूद तेजस्वी यादव की चुनावी जनसभा में उमड़े जनसैलाब की बात करें तो एनडीए प्रत्याशी भी सकते में हैं. राजद के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव ने अपनी सभी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई मुद्दों पर घेरा है. जिसका जबाब भाजपाई भी ढूंढने में लगे हैं वही एनडीए गठबंधन के प्रचारक बिहार में लालू राबड़ी के कार्यकाल पर हमलावर होते हैं और कांग्रेस को कोसते नजर आते हैं. बहरहाल बांका में जदयू का तीर निशाने पर है लालटेन जलने की उम्मीद कम बची हुई है.

☞ **पूर्णिया लोकसभा :-** पूर्णिया पूर्वोत्तर बिहार का सबसे बड़ा शहर है, जहां से नेपाल और पूर्वोत्तर भारत की ओर जाने का रास्ता गुजरता है. वर्तमान में पूर्णिया प्रमंडलीय मुख्यालय है, जिसके अंतर्गत अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिले आते हैं. पूर्णिया सौरा नदी के पूर्वी किनारे पर बसा है.पूर्णिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र के दायरे में 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें कस्बा, बनमखनी, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया और कोरहा विधानसभा सीटें शामिल हैं. साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन 6 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें बीजेपी, 2 सीटें जेडीयू और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थीं. पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में वोटरों कुल वोटरों की संख्या 13 लाख 5 हजार 396 है, जिनमें से 6 लाख 88 हजार 182 पुरुष वोटर हैं, जबकि 6 लाख 17 हजार 214 महिला मतदाता हैं. अगर पूर्णिया लोकसभा सीट के चुनावी इतिहास पर नजर दौड़ाएं, तो साफ होता कि यहां के वोटर समय समय पर अपना प्रतिनिधि बदलते रहे हैं. साल 1957 में इस सीट से कांग्रेस

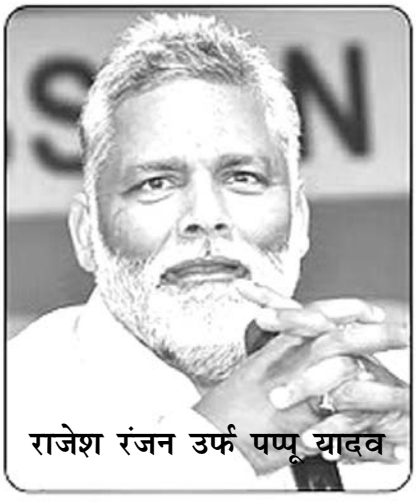
राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव

बीमा भारती

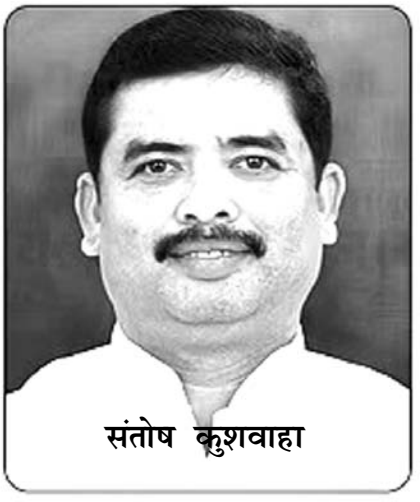
संतोष कुशवाहा

के टिकट पर फनी गोपाल सेन गुप्ता ने जीत दर्ज की थी. इसके बाद 1962 और 1967 के चुनाव में भी उन्हीं को ही जीत मिली. 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट से जद(यू) प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाह ने जीत दर्ज की, उन्हें 6,32,924 वोट मिले थे. वहीं कांग्रेस के उदय सिंह 3,69,463 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और आईएनडी के शुभाष कुमार ठाकुर 31,795 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे. पूर्णिया लोकसभा संसदीय सीट पर 64.5 फीसदी मतदान हुआ था.

☞ **2014 का जनादेश** :- इससे पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से जेडीयू के संतोश कुमार कुशवाहा ने बीजेपी के उदय सिंह को शिकस्त दी थी. संतोष कुमार को 4 लाख 18 हजार 826 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार उदय सिंह के खाते में 3 लाख 2 हजार 157 वोट आए थे. इसके अलावा कांग्रेस के उम्मीदवार अमरनाथ तिवारी को एक लाख 24 हजार 344 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे. यहां पर 2014 में 64.31 फीसदी मतदान हुआ था. दूसरे चरण का मतदान जिन सीटों पर मतदान हुआ है उनमें बिहार का पांच सीटें भी शामिल हैं.ये सीटें हैं किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका. इस दौर में बिहार की जिस सीट की चर्चा है, वह है पूर्णिया इस सीट

के मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं बाहुबली छवि वाले नेता राजेश रंजन ऊर्फ पप्पू यादव.आइए जानते हैं कि पूर्णिया सीट कैसी है और कैसा रहा है इतिहास. पूर्णिया लोकसभा सीट में विधानसभा क्षेत्र बनमनखी, धमदाहा, कस्बा, कोरहा, पूर्णिया , रूपौली विधानसभा क्षेत्र आते हैं. आजादी के बाद 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव में इस सीट को पूर्णिया सेंट्रल, पूर्णिया-संथाल और पूर्णिया उत्तर-पूर्व के रूप में बंटा हुआ था. इसके बाद से हुए लोकसभा चुनाव में इसका नाम पूर्णिया कर दिया गया.

☞ **पूर्णिया लोकसभा सीट का इतिहास** :- आजादी के बाद से लेकर 1984 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा. बीच में आपातकाल के बाद कराए गए चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस को हार को सामना करना पड़ा था. उस चुनाव में यह सीट भारतीय लोक दल ने जीत ली थी. लेकिन 1984 के बाद से कांग्रेस इस सीट पर कभी नहीं जीत पाई. बिहार में सरकार चला रहे एनडीए गठबंधन ने पांच बार इस सीट से जीत दर्ज की है. इनमें से तीन बार (1998, 2004 और 2009) में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी. वहीं जयदू ने दो बार इस सीट पर जीत दर्ज की है. जदयू ने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले के दम पर लड़ा था.

उस दौर में चली बीजेपी की आंधी में भी जदयू ने इस सीट पर कब्जा जमाया था. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जदयू एक साथ आ गए थे. इस गठबंधन का प्रभाव लोकसभा चुनाव में भी नजर आया था. जदयू ने 2019 में भी इस सीट पर कब्जा जमा लिया था.

☞ **पूर्णिया सीट की लड़ाई :-** साल 2019 के चुनाव में जदयू के चुनाव में छह लाख 32 हजार से अधिक वोट लेकर जीत दर्ज की थी. वहीं उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को को करीब तीन लाख 80 हजार वोट मिले थे.अगर इस वोट फिसदी की बात करें तो जदयू ने 54.85 फीसदी और कांग्रेस ने 32.02 फीसद वोट हासिल किए थे. पूर्णिया लोकसभा सीट पर करीब 18 लाख मतदाता हैं. पूर्णिया सीट के मतदाताओं में करीब 60 फीसदी हिंदू और करीब 40 फीसदी मुसलमान हैं. पूर्णिया में ओबीसी और दलित मतदाताओं की संख्या पांच लाख से ऊपर बताई जाती हैं.

☞ **पूर्णिया की लड़ाई को दिलचस्प बना रहे हैं पप्पू यादव :-** इस वजह से पूर्णिया का मुकाबला दिलचस्प हो गया है. राजद ने इस सीट को अपनी नाक का सवाल बना लिया है.तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में प्रचार करते हुए पप्पू यादव को बीजेपी का एजेंट भी बता चुके हैं. वो यहां तक कह चुके हैं कि अगर आप राजद को वोट नहीं दे सकते हैं तो जदयू को वोट दे दीजिए.जदयू ने अपने सांसद संतोष कुमार को ही टिकट दिया है. इस बार के चुनाव को यहां से तीन बार

सांसद चुने गए राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव दिलचस्प बना रहे हैं. दरअसल पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का चुनाव से पहले ही कांग्रेस में विलय कर दिया था. उन्हें उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के खाते में आ जाएगी. लेकिन जिद करके लालू प्रसाद यादव की राजद ने पूर्णिया सीट अपने पास रख ली. पार्टी ने वहां से रूपौली की विधायत बीमा भारती को अपना टिकट भी दे दिया है. वो जदयू छोड़कर राजद में आई हैं. पप्पू यादव ने काफी पहले ही चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था. चुनाव प्रचार के दौरान वो लोगों से काफी घुलते मिलते नजर आए.वहीं सांसद होने की वजह से संतोष कुमार की भी पकड़ इलाके में अच्छी मानी जा रही है. पूर्णिया के लिए बीमा भारती भी बाहरी नहीं हैं, वो भी जिले की रूपौली विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं.इसलिए पूर्णिया का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है. इस मुकाबले में भारी कौन पड़ता है, इसका पता तो चार जून को ही चल पाएगा, जब नतीजे आएंगे.

☞ **किशनगंज लोकसभा :-** बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य है. यहां के मुस्लिम वोटर ही किसी उम्मीदवार की हार और जीत तय करते हैं. कांग्रेस के मोहम्मद जावेद 2019 में यहां से सांसद बने. कांग्रेस नेता ने जेडीयू के उम्मीदवार सय्यद मोहम्मद अशरफ को 2019 के लोकसभा चुनाव में हराया था. इस सीट से कांग्रेस ने लगातार तीन बार जीत दर्ज की है. साल 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता असरारुल हक ने लगातार दो बार जीते थे. इसके बाद यहां से कांग्रेस के ही नेता मोहम्मद जावेद ने यह सीट पार्टी के झोली में डाली है. 2019 के चुनाव परिणाम की बात करे तो कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जावेद को 3,67,017 वोट मिले हुए थे. जेडीयू के उम्मीदवार सय्यद मोहम्मद अशरफ को इस सीट पर 3,32,551 वोट ही प्राप्त हुए थे. एआईएमआईएम के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान को 2,95,029 वोट मिले थे. कांग्रेस उम्मदीवार ने 34,461 वोटों से जीत दर्ज की थी. इस सीट पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के लिए जमकर प्रचार प्रसार किया था. इस वजह से उनकी पार्टी के उम्मीदवार को भी इस सीट पर करीब 3 लाख वोट मिले हैं. 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां से मोहम्मद असरारुल हक ने जीत दर्ज की थी. असरारुल हक को इस सीट पर 4,93,461 वोट मिले हुए थे. बीजेपी उम्मीदवार दिलीप कुमार जायसवाल को 2,98,849 वोट मिले थे. जेडीयू से अख्तरुल ईमान ने 55,822 वोट अपनी झोली में किए थे. कांग्रेस नेता असरारुल हक ने करीब 2 लाख वोटों से बीजेपी उम्मीदवार को हराया था.

किशनगंज लोकसभा सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं. 1. बहादुर गंज विध

अख्तरूल इमान

मो० जावेद

मुजाहिद आलम

इनसभा सीट से आरजेडी के विधायक हैं. 2. ठाकुरगंज विधानसभा सीट से सऊद आलम विधायक हैं. 3. किशनगंज विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं. 4. कोचाधामन विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक हैं. 5. अमौर विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के अख्तरौल ईमान विधायक हैं. बैसी विधानसभा सीट से आरजेडी के विधायक हैं. किशनगंज, बिहार के 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। यह जिला मुख्यालय होने के कारण, सभी प्रमुख सरकारी विभागों के कार्यालय यहां हैं। कृष्णाकुंज के नाम से भी जाना जाने वाला यह क्षेत्र, बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश की सीमाओं से सटा हुआ है। यहां का खगरा मेला पूरे देश में प्रसिद्ध है। नेहरु शांति पार्क और चुर्ली किला, लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। पानीघाट, गंगटोक, कलिंगपोंग, दार्जिलिंग जैसे पर्यटन स्थल भी यहां से कुछ ही दूरी पर स्थित हैं। यहां का खेल स्टेडियम भी एक प्रमुख जगह है। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी के राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट का आयोजन यहां पर किया जाता है।

☞ **किशनगंज के कुछ प्रमुख आकर्षण :-**

☞ **खगरा मेला :-** यह मेला हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित होता है और लाखों लोगों को आकर्षित करता है।

☞ **नेहरु शांति पार्क :-** यह पार्क भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में बनाया गया है।

☞ **चुर्ली किला :-** यह किला 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है।

☞ **खेल स्टेडियम :-** यह स्टेडियम राष्ट्रीय स्तर के खेल टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए जाना जाता है।

किशनगंज, अपनी समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और खेल भावना के लिए जाना जाता है। यह एक आकर्षक पर्यटन स्थल है और पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र यही एक सीट पर

अजय मंडल

अजीत शर्मा

कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज किया था बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों का सूपड़ा साफ हो गया था. 2024 का लोकसभा चुनाव में भी यहाँ से इण्डिया गठबंधन के प्रत्याशी के सर पर ताजपोषी होने की उम्मीद जताई जा रही है. एनडीए प्रत्याशी के लाख प्रयासों के बाबजूद यहाँ से जीत दर्ज करना मुश्किल ही नहीं मुमकिन दिख रहा हैं.

☞ **भागलपुर लोकसभा :-** भागलपुर बिहार का जिला और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं. यह क्षेत्र गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है. यह बिहार का तीसरा सबसे बड़ा शहर है. भागलपुर डिवीजन का मुख्यालय भी यहीं है. यह एक प्रमुख शैक्षिक, वाणिज्यिक और राजनीतिक केंद्र है. इस जिले का क्षेत्रफल 2,569 वर्ग किलोमीटर है. 2011 जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक भागलपुर की जनसंख्या 30.38 लाख थी. इस जिले की 63.14 फीसदी जनसंख्या साक्षर है. इनमें पुरुष 70.30 फीसदी और महिलाओं की साक्षरता दर 54.89 फीसदी है. गंगा नदी के किनारे बसा होने के कारण शहर के आसपास का मैदान बहुत उपजाऊ हैं. क्षेत्र की मुख्य फसलों में चावल, गेहूं, मक्का, जौ और तिलहन शामिल हैं. विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंच्युरी शहर के पास स्थापित है. मनसा पूजा और काली पूजा इस शहर के महत्वपूर्ण त्योहारों में से हैं. विक्रमशिला के खंडहर, श्री चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र, महर्षि मेही आश्रम, कुप्पाघाट और तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर जिले का प्रमुख पर्यटक स्थल है. चुनाव आयोग के मुताबिक भागलपुर में करीब 14 लाख 33 हजार 346 वोटर हैं. भागलपुर संसदीय क्षेत्र की कुल आबादी 30 लाख 32 हजार 226 है. यहां पहली बार साल 1951 में लोकसभा चुनाव हुए

थे. उस समय दरभंगा और भागलपुर एक सीट ही थी. हालांकि बाद में परिसीमन में दोनों अलग-अलग हो गए. इसमें से कुछ पुराने क्षेत्र बाहर हो गए, तो कुछ नए क्षेत्र जुड़ गए. नया भागलपुर संसदीय क्षेत्र बना उसमें बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर और नाथनगर विधानसभा सीटें शामिल हो गई और सुलतानगंज व धोरैया विधानसभा सीटों को निकाल दिया गया. इन दोनों विधानसभा सीटों को बांका संसदीय क्षेत्र में डाल दिया गया. साथ ही बिहपुर और गोपालपुर नए विधानसभा इलाकों को भागलपुर के तहत लाया गया. ये दोनों विधानसभा क्षेत्र पहले खगड़िया संसदीय क्षेत्र का हिस्सा थे.

☞ **2019 का जनादेश :-** भागलपुर लोकसभा सीट पर जनता दल युनाइटेड ने अजय कुमार मंडल, बहुजन समाज पार्टी ने मोहम्मद आशिक इब्राहिमी, राष्ट्रीय जनता दल ने शैलेश कुमार, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट ने दीपक कुमार, आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र कुमार और भारतीय

दलित पार्टी ने सुशील कुमार दास को चुनाव मैदान में उतारा था. इसके अलावा अभिषेक प्रियदर्शी, नुरुल्लाह और सुनील कुमार बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे. 2019 लोकसभा चुनाव में इस सीट से जेडी(यू) के अजय कुमार मंडल ने जीत हासिल की, उन्हें 6,18,254 वोट मिले थे. तो वहीं आरजेडी के शैलेश कुमार 3,40,624 वोटों से दूसरे नंबर पर रहे और 31,567 जनता ने नोटा के बटन को दबाकर तीसरे नंबर पर रखा.

☞ **2014 का जनादेश :-** साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी के शाहनवाज हुसैन और आरजेडी के प्रत्याशी शैलेष कुमार मंडल के बीच सीधी टक्कर थी. इस चुनाव में 3 लाख 67 हजार 623 वोटों के साथ शैलेष कुमार मंडल विजयी घोषित किए गए थे. वहीं, शाहनवाज हुसैन को 3 लाख 58 हजार 138 वोट मिले थे और वो इस कड़े मुकाबले में हार गए थे. इस चुनाव में मंडल को 37.74 प्रतिशत वोट मिले थे, जबकि शाहनवाज हुसैन को 36.76 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे. दरअसल, 1989 के दंगे बाद कांग्रेस इस सीट पर मजबूती के साथ अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भागलपुर प्रमुख शैक्षिक, वाणिज्यिक और राजनीतिक केंद्र है। इस जिले का क्षेत्रफल की बात करें तो 22,569 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।

दुलारचंद्र गोस्वामी

☞ **23 लाख वोटर तय करेंगे भागलपुर के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला :-** भागलपुर लोकसभा सीट पर पहली बार साल 1951 में चुनाव हुआ था। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर और नाथनगर विधानसभा सीटें शामिल हैं. 2019 में 31 हजार नोटा बटन दबना प्रत्याशियों के लिए टेंशन रहा।

लोकसभा चुनाव 2024 में भागलपुर सीट से कुल 23 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। जिसमें कुल 10 प्रत्याशियों की स्क्रूटनी में नाम छठ गया तो एक निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस कर लिया था। इस बार भागलपुर लोकसभा सीट पर कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। उम्मीदवारों के नाम इस प्रकार हैं- जेडीयू से अजय कुमार मंडल और कांग्रेस से अजीत शर्मा चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा उम्मीदवार दीपक कुमार सिंह, उमेश प्रसाद यादव, दीपक कुमार, छोटे लाल कुमार, मुकेश कुमार, हरेराम यादव, दयाराम मंडल, ओमप्रकश पोद्दार, पूनम सिंह और रमेश टुडू बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। बहरहाल यहाँ भी इण्डिया गठबंधन मजबूत स्थिति में हैं.

☞ **कटिहार लोकसभा :-** भारतीय मानचित्र पर कटिहार लोकसभा का अपना एक अलग ही महत्व रखता है. यह जिला गंगा, महानंदा, कोसी, बरंडी, कारी कोसी समेत आधे दर्जन से अधिक नदियों से घिरा हुआ है. कटिहार जिला जो कभी उधोगनगरी के रूप में जाना जाता था अब उद्योगविहीन बन चुका है. कटिहार जिले में दो-दो जुट मिल, दो फ्लावर मिल, दियासलाई की फैक्ट्री, कांटी फैक्ट्री समेत दर्जनों ऐसे कल कारखाने थे जो कटिहार के लिये गर्व हुआ करता था लेकिन धीरे-धीरे एक-एक कर उद्योग बंद हो गए. इसलिए विस्थापन और पलायन यहां की प्रमुख समस्या बन चुकी है. जिले का कुल क्षेत्रफल 3,056 वर्ग किलोमीटर है. 2011 की जनगणना के मुताबिक कटिहार जिले की आबादी 30,68,149 है. इसमें 41 फीसदी मुस्लिम, 11 फीसदी यादव, 8 फीसदी सवर्ण, 16 फीसदी वैश्य, 18 फीसदी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा 06 फीसदी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं. जिले में करीब 52 प्रतिशत लोग साक्षर हैं. करीब 1,40,000 लोग यहां खेती पर निर्भर करते हैं. कटिहार जिले में कुल सात विधानसभा क्षेत्र है जबकि कटिहार लोकसभा क्षेत्र के तहत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं. जबकि जिले का कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है. जिले में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 21 लाख 04 हजार 409 है, जिसमें 09 लाख 39 हजार 260 मतदाता पुरुष हैं वहीं 08 लाख 65 हजार 305 मतदाता महिला जबकि 102 थर्ड जेंडर हैं. कटिहार लोकसभा क्षेत्र में धार्मिक धरोहर के रूप में गोरखनाथ धाम मंदिर, शहर के राजहाता स्थित काली मंदिर, सार्वजनिक श्री दुर्गा मंदिर और मनिहारी स्थित पीर मजार व मंगल बाजार

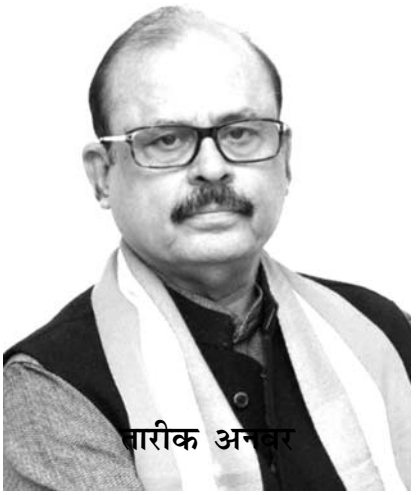

तारीक अनवर

स्थित जामा मस्जिद और बारसोई स्थित खानकाह पीर मजार का काफी महत्व है. कटिहार लोकसभा का चुनाव काफी दिलचस्प रहा है. कटिहार लोकसभा क्षेत्र सीमांचल के सबसे चर्चित लोकसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता सीताराम केसरी जैसे व्यक्तित्व कटिहार लोकसभा क्षेत्र से 1967 से 1977 तक का नेतृत्व कर चुके हैं. साथ ही. कांग्रेस के कद्दावर नेता तारिक अनवर, बीजेपी के प्रखर नेता निखिल कुमार चौधरी , समाजवादी नेता युवराज सिंह, यूनुस सलीम जैसे बड़े बड़े नेता भी यहां से अपना नेतृत्व कर देश के मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं. यहां का चुनाव जातीय अंकगणित और धर्म से ऊपर आज भी नहीं उठ पाया है. इसलिए यह नगरी पहले की तुलना में आज भी पिछड़ापन का शिकार बना हुआ है.

☞ **2019 का जनादेश :-** कटिहार लोकसभा सीट पर कुल 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने तारिक अनवर, जनता दल (यूनाइटेड) ने दुलाल चंद्र गोस्वामी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने मुहम्मद शाकुर, बहुजन समाज पार्टी ने शिवनंदन मंडल, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) ने अब्दुर रहमान, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी ने गंगा केबट, भारतीय बहुजन कांग्रेस ने बसुकीनाथ साह और बहुजन मुक्ति पार्टी ने मारंग हंसडा को चुनाव रण में उतारा है. इस बार बीजेपी यहां से चुनाव नहीं लड़ रही. यह सीट एनडीए में बीजेपी की सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) के खाते में चली गई है. 2019 चुनाव में कटिहार सीट से जेडीयू के नेता दुलार चंद गोस्वामी ने जीत हासिल की. उन्हें 5,59,423 वोट मिले थे. वहीं कांग्रेस के तारिक अनवर को 5,02,220 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और एनसीपी के उम्मीदवार मोहम्मद शकुर 9,248 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. इस संसदीय सीट पर 68.52 फीसदी मतदान हुआ था.

☞ **2014 का जनादेश :-** 2014 चुनाव में इस सीट पर एनसीपी के प्रत्याशी तारिक अनवर ने जीत हासिल करते हुए 4,31,292 वोट प्रप्त किए. तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी निखिल कुमार चौधरी 3,16,552 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर थे. जनता दल (यूनाइटेड) के डॉ. राम प्रकाश महतो 1,00,765 वोट प्राप्त कर तीसरे नंबर पर रहे. जबकि जेएमएम के बालेश्वर मरांडी 33,593 वोटों से संतोष करना पड़ा था. कटिहार बिहार के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। राज्य में 40 संसदीय सीटें हैं। कटिहार सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं जिनमें कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी (एसटी), बरारी शामिल हैं। यह निर्वाचन क्षेत्र एक सामान्य सीट है। जद (यू), कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्र में मुख्य दल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में, जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी ने 57,203 वोटों के अंतर से सीट जीती। दुलाल चंद्र गोस्वामी को 50.00% वोट शेयर के साथ 559,423 वोट मिले और उन्होंने कांग्रेस के तारिक अनवर को हराया, जिन्हें 502,220 वोट (44.91%) मिले। 2014 के लोकसभा चुनावों में, एनसीपी के तारिक अनवर ने सीट जीती और उन्हें 44.11% वोट शेयर के साथ 431,292 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार निखिल कुमार चौधरी को 316,552 वोट (32.37%) मिले और वह उपविजेता रहे। तारिक अनवर ने निखिल कुमार चौधरी को 114,740 वोटों के अंतर से हराया। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खालिद मुबारक तथा ज्ञानेश्वर सोरेन अपनी किस्मत आजमा रहे हैं.

☞ **कटिहार लोकसभा सीट :-** कटिहार की लोकसभा सीट हो या फिर यहां की विधानसभा सीटें, कभी किसी दल का एकछत्र राज नहीं रहा है. वैसे इस सीट ने देश को कई दिग्गज नेता दिए

हैं. यहां छह विधानसभा सीट कटिहार, कड़वा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी और बरारी हैं. इनमें कटिहार और प्राणपुर में बीजेपी, कड़वा और मनिहारी में कांग्रेस, बरारी में जेडीयू और बलरामपुर में सीपीआईएमएल का विधायक है. लोकसभा सीट की बात करें तो 1957 के चुनाव में यहां से कांग्रेस ने खाता खोला था. उसके बाद 1962 में यहां प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की प्रिया गुप्ता ने जीत हासिल की. 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सीताराम येचुरी विजयी हुए. इसके बाद 1971 में भारतीय जनसंघ के टिकट पर गंगेश्वर प्रसाद यादव ने जीत हासिल की. 1980 के चुनाव में कांग्रेस की ओर से तारिक अनवर की यहां एंट्री हुई. उन्होंने 1984 का चुनाव भी जीता. 1989 और 1991 के चुनाव यह सीट जनता दल की झोली में चली गई. 1996 में तारिक अनवर ने फिर से कब्जा किया. 1998 में भी वही चुने गए. 1999, 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में यहां से बीजेपी के निखिल कुमार चौधरी लगातार तीन बार सांसद बने. 2014 में तारिक अनवर ने शरद पवार वाली एनसीपी के टिकट पर जीत हासिल की. लेकिन 2019 के चुनाव में जनता दल-यू के दुलाल चंद्र गोस्वामी के हाथों हार का सामना करना पड़ा.

☞ **दुलाल चंद्र गोस्वामी :-** जेडीयू सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी छात्र जीवन से ही राजनीति में हैं. वे एक बार बीजेपी के टिकट पर और एक बार निर्दलीय विधायक रह चुके हैं. निर्दलीय विधायक चुने जाने के बाद दुलाल चंद्र बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री रहे. 2019 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर को 57 हजार वोटों से हराया था.

☞ **तारिक अनवर :-** कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं. कटिहार सीट से वे पांच बार चुनाव जीत चुके हैं. अब छक्का लगाने के लिए मैदान में उतरे हैं. इससे पहले तारिक अनवर महाराष्ट्र से राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं. वे कृषि और खाद्य प्रसंस्करण केंद्रीय मंत्री थे. कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी के बेहद करीबी रहे तारिक अनवर पढ़ाई के दौरान ही राजनीति में एंट्री कर ली थी. वे 1988 से 1989 तक बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे. बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए. शरद पवार ने उन्हें महाराष्ट्र से 2004 में राज्य सभा का सदस्य बना दिया. यह राज्यसभा में उनका दूसरा कार्यकाल था. राफेल डील पर शरद पवार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पक्ष लिए जाने से नाराज होने पर उन्होंने एनसीपी छोड़ दी और 2018 में फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए. कांग्रेस ने इस बार भी तारिक अनवर को प्रत्याशी बनाया है वही जदयू ने सांसद दुलालचंद गोस्वामी पर भरोसा जताया है लेकिन देखने वाली बात होंगी की कटिहार से तारिक अनवर का अपना इतिहास रहा हैं क्षेत्र में इनकी अलग पहचान बनी हुई हैं जिसका लाभ इन्हे मिल सकता हैं. बिहार में दूसरे चरण में सम्पन्न हुए लोकसभा की पांच सीटों पर चुनाव के नतीजे चार जून को आएंगे लेकिन समीकरण साफ है एनडीए को कड़ा मुकाबला का सामना करना पड रहा हैं। यहाँ किसी की राह आसान नहीं दिखती है लेकिन मतदाताओं के रुझान बताते हैं की जनादेश बदलाब की ओर अग्रसर हैं।●

अत्याचारी, भ्रष्टाचारी और सिजोफ्रेनिया रोग से ग्रसित हैं

के. के. पाठक

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

बिहार का शिक्षा विभाग आज कल सुर्खियों में है। नीतीश कुमार जिस पदाधिकारी को ईमानदार और कर्त्तव्यनिष्ठ बोलते नहीं थकते हैं, उन्हीं के विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। BPSC शिक्षक के पदस्थापन में जिस तरह से रेन्डमाईजेशन के नाम पर जिस तरह से वसुली हुई यह जग जाहिर है। अभी स्कूल में हुई मेज की आपूर्ति, थाली की आपूर्ति और किताबों की आपूर्ति जिस तरह से घटिया तरीके से किया गया है, उसमें साफ पता चलता है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाला बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड बिहार वित्त नियमावली 2005 के नियम 131 का उल्लंघन कर बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार को आयाम दे रहा है।

बिहार वित्त नियमावली के नियम 131ज(V)और 131H(V) के तहत टेडर बोली समर्पित की न्यूनतम अवधि सामान्यत: निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि अथवा बोल दस्तावेज बिक्री हेतु उपलब्ध होने की तिथि से भी बाद में से तीन सप्ताह की होनी चाहिए, लेकिन बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड बिहार वित्त नियमावली का उल्लंघन कर मात्र 9 (नौ) दिनों का रखता है, क्योंकि ऐसा करने से अल्प समय में कोई बढ़िया ठिकेदार निविदा में भाग नहीं ले पाये और निगम अपने चहेते जिस संवेदक के साथ मिलकर निविदा तैयार की जाती है, उसे निविदा में भाग लेने के लिए कोई मजबूत कम्पिटिटर नहीं मिल सके। बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड की पूरी निविदा अपारदर्शी है। निविदा पूरी तरह से फेब्रिकेटेड रहती है। कुल मिलाकर निविदा को सोर्स ऑफ क्रप्शन कहा जा सकता है।

के. के. पाठक के सिजोफ्रेनिया रोग से ग्रसित रहने के कारण शिक्षा विभाग को रोज नये आदेश जारी करने के कारण शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षक और छात्र असमंजस में रहते हैं। इनके सनक के कारण होली, ईद और कई पर्व-त्यौहारों में भी शिक्षक का प्रशिक्षण एवं अन्य कई तरह के कार्य करने पड़ रहे हैं। महामहिम राज्यपाल से इनका टकराव जग जाहिर है। आज विश्वविद्यालय के सत्र से लेकर विकास कार्यों पर भी इनके सनक का असर है। अब लोग इन्हें बिहार का तानाशाह किम जोंग भी कहने लगे हैं।

आई.एम.ए. के पूर्व अधिकारी डॉ० अजय और अपने कनीय अधिकारी सहित बिहारवासियों को के. के. पाठक ने खुलेआम गाली दिया, यह बात किसी से भी नहीं छुपी है। आये दिन अधिकारियों को गाली देना, मुख्यमंत्री के विधानसभा में दिये वक्तव्य को नहीं मानना,

www.kewalsach.com

निर्भीकता हमारी पहचान

केवल सच

हिन्दी मासिक पत्रिका

प्रधान कार्यालय

9431073769, 9955077308, 8340360961, 9308727077

ई-मेल आईडी

kewalsach@gmail.com / editor.kstimes@rediffmail.com

पत्रांक :- 25/Kewsch/2023 दिनांक :- 17/08/23

सेवा में,

माननीय मुख्य सचिव महोदय

बिहार सरकार पटना।

विषय - बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता ओमप्रकाश सिंह द्वारा निविदा संख्या -12/2023-2024 में बिहार वित्त नियमावली 2005 का उल्लंघन कर भ्रष्टाचार के मकसद से निविदा प्रकाशित किए जाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध मे कहना है कि बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता के द्वारा अखबार मे निविदा संख्या 12 वर्ष 23-24 निकाला जाता है जिसमें बिहार के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल मे फर्नीचर के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। अखबार में प्रकाशित निविदा के अनुसार बीड पत्र बिक्री की तिथि 27/07/2023 से 04/08/2023 दिन के 3:00 बजे तक होता है, और अंतिम तिथि 05/0823 होता है मतलब सिर्फ 9 दिनो का समय था, लेकिन तय समय यानी 27 को निविदा www.eproc2.bihar.gov.in इन पर अपलोड नही की जाती है, और फिर बिना अखबार मे प्रकाशित किए एक को Corrigendum निकाला जाता है जिसमे जिसमे बीड अपलोड /डाउनलोड की तिथि बढ़ाकर 07/08/2023 से 15/08/2023 दिन के 3:00 बजे कर दी जाती है, निविदा की अंतिम तिथि 16 मार्च 2023 है यानी मात्र सिर्फ 9 दिन की होती है।

बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निकाली गई निविदा संख्या 12 वर्ष 2023-2024 मे निविदा 70 करोड़ के लिए निकाली गई थी, बिहार वित्त नियमावली (BFR) के रूल 131 के तहत 25 लाख से ऊपर विज्ञापित निविदा निकाली जाती है। बिहार स्टेट एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निकाली गई निविदा भी विज्ञापित निविदा है, इसलिए BFR के रूल 131(H) के नियम के तहत कम से (कम 3 सप्ताह) 21 दिनों का समय होना चाहिए।

Total No of Page (09)

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD

(A Govt. of Bihar Undertaking)

ISO 9001:14001; OHSAS 18001

Shiksha Bhawan, Bihar Rashtrabhasha Parishad Campus, Acharya Shivpujan Sahay Path, Saidpur, Patna - 800 004

Tel. No. : 0612 - 2660850 • Fax No. : 0612 - 2660256

E-mail : bseidc@gmail.com • Website : http://www.bseidc.in • CIN : U80301BR2010SGC015859

पत्रांकः–BSEIDC/TECH/1855/2024- पटना, दिनांकः–

प्रेषक,

मुख्य अभियंता
BSEIDC, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, (मु०)
BSEIDC, पटना।

विषयः–लंबे समय तक भूखण्ड की अनुपलब्धता तथा भूमि विवाद के कारण लंबित परियोजनाओं को बन्द करने के संबंध में।

प्रसंगः–निदेशक (मा०शि०), शिक्षा विभाग का पत्रांक–310, दिनांक–02.02.2024

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि भूमि अनुपलब्धता एवं भूमि विवाद के कारण बड़ी संख्याओं में परियोजनाएँ लंबित है। कालान्तर में जबतक भूमि उपलब्ध हुई या विवाद का समाधान हुआ तबतक संवेदक द्वारा पुराने दर पर/एकरारनामा के दर पर कार्य करने में असहमति व्यक्त की गयी।

निदेशक (मा०शि०), शिक्षा विभाग का पत्रांक–310, दिनांक–02.02.2024 से भूखण्ड की अनुपलब्धता वाली योजनाओं को बन्द करने पर सहमति दी गयी है, जिसके आलोक में संलग्न सूची के अनुसार भूमि अनुपलब्धता वाली योजनाओं के एकरारनामा/L.O.A/I.O.A-Cum-work Order को रद्द करते हुए योजनाओं को बन्द किया जाता है।

इसपर प्रबंध निदेशक का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–
मुख्य अभियंता
BSEIDC, पटना।

ज्ञापांकः– BSEIDC/TECH/1855/2024- दिनांकः–

प्रतिलिपिः–वरीय लेखा पदाधिकारी, BSEIDC, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
मुख्य अभियंता
BSEIDC, पटना।

ज्ञापांकः– BSEIDC/TECH/1855/2024- 3418 दिनांकः– 19/04/24

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता (मु०)/संबंधित कार्यपालक अभियंता/उप प्रबंधक तकनीकी (असैनिक), क्षेत्रीय, BSEIDC/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु श्री अरविंद कुमार, परामर्शी (आई०सी०टी०), BSEIDC, को सूचनार्थ प्रेषित।

19-4-2024

मुख्य अभियंता
BSEIDC, पटना।

मंत्री की बात को नहीं मानना, उसके बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करना, यह जाँच का विषय है। मुख्यमंत्री कहीं न कहीं के. के. पाठक से ब्लैकमेल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई ईमानदार, असरदार भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री महोदय क्यों के. के. पाठक के सनक का शिकार हो रहे हैं? यह खुद मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं।

शिक्षा विभाग मे कई ऐसी समस्याएं हैं, जिनका शिक्षा के आधारभूत विकास के लिए समाधान होना बहुत जरूरी है, लेकिन के. के. पाठक साहब को तो सिर्फ लाइम–लाईट में रहना हैं। बिहार में भूमि उपलब्ध नहीं रहने या विवादित रहने के कारण 78 जगहों पर निर्माण कार्य नहीं हो सका और प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। कई उत्क्रमित

Education Department
Directorate of Mid Day Meal,
Education Department

Govt. of Bihar

E-mail ID : mdmsbihar@gmail.com Phone no. 0612-2231005

NIT No. 2013/23-24

E-Tender Notice

Directorate of Mid Day Meal, Bihar (Also, now known as PM POSHAN DIRECTORATE) invites proposals from reputed and experienced manufacturer/ companies to participate in online competitive bidding process of e-tender "For Procurement of Stainless-Steel Lunch Plate for Schools in Bihar state".

1. Work Detail's

Sl NO	scope of Work	Cost of Tender Document (in Rupees, Non-Refundable) to be paid through e-payment mode (i.e., NEFT/RTGS/ Credit Card/Debit Card (in Rupees)	Tender Processing Fee (Non-Refundable) Inclusive of GST@18.00% to be paid through e-payment mode (i.e NEFT/RTGS/Credit Card/Debit Card (in Rupees)	Earnest Money Deposit (in Rupees)
1	2	3	4	5
1	Selection of Contractor for procurement of Stainless-Steel Lunch Plate for 70,699 Schools under Mid Day Meal Scheme, Bihar	Rs. 50000-/	Rs.5900	2,00,00,000/-

2. e-Tender Schedule/Programs:-

Sl.NO.	Activity	Date/Time
1	Online Sale/Download date of Tender Documents.	From 15.9.2023 to 5.10.2023 upto 17.00 Hrs. IST
2	Pre-bid meeting.	On 25.9. 2023 in the office of Director Mid Day Meal, Bihar, Patna at 15.30 Hrs. IST
3	Last Date for submission of Bid (Online only)	6.10. 2023 at 17.00 Hrs. IST
4	Date/ Time for opening of Technical Bid.	7.10.2023 at 15.00 Hrs. IST in office of Director, Mid Day Meal, Bihar, Patna.
5	Financial Bid Opening Date and Time	To be informe d
6	Contact Person For Queries:	Baleshwar Prasad Yadav, Mob; -9470288076

This information is available on state.bihar.gov.in/prdbihar also

(Mithilesh Mishra)
Director
Mid Day Meal Sheme
Bihar, Patna

PR- 008745 (Ni Ni) 2023-24

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है

विद्यालयों में खेल मैदान नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने अपने आदेश में कहा है कि खेल मैदान के बिना स्कूल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिहार के बहुतायत सी.बी.एस.सी. से निबंधित विद्यालयों में खेल मैदान हैं, लेकिन बिहार सरकार के हजारों विद्यालयों में खेल मैदान नहीं है। कई स्कूल की जमीन अतिक्रमित है या भू–माफियाओं ने कब्जा कर लिया है, लेकिन इस दिशा में के. के. पाठक ने गौर करना भी मुनासिब नहीं समझा।

बिहार के 71 हजार प्रारंभिक विद्यालयों में पहली से आठवी कक्षा के बच्चों को निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी किताबों के कागज बहुत ही घटिया स्तर के हैं। इसके लिए के. के. पाठक ने जाँच समिति का गठन भी कर दिया, लेकिन बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा खुलेआम बिहार वित्त नियमावली का

कार्यालय–जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल
(पी० एम० पोषण योजना)

NIC
07 DEC 2023
DISTRICT ... SUPAUL

सुपौल जिलान्तर्गत प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में स्टील थाली क्रय हेतु फर्म/एजेन्सी को सूचिबद्ध करने के संबंध में विज्ञापन :–

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना के पत्रांक 2558 दिनांक 21.11.2023 के आलोक में मध्याह्न भोजन योजना से आच्छादित प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में स्टील थाली की आपूर्ति किया जाना है। उल्लेखनीय है कि अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना द्वारा वी०सी० में दिए गए निदेश के आलोक में थाली क्रय हेतु इच्छुक फर्म/एजेन्सी को सूचिबद्ध (Empanelment) किया जाना है।

अतः इस सूचना के माध्यम से वैसे इच्छुक फर्म/एजेन्सी जो निबंधित हो, जिसके पास जी० एस० टी०, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पिछले तीन साल का आई० टी० आर०, एजेन्सी की काली सूची में सम्मिलित नहीं होने से संबंधी स्व–घोषणा पत्र, किसी भी सरकारी क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र एवं विभागीय नियमानुसार थाली का नमूना के साथ वे अपना आवेदन दिनांक 11.12.2023 को अपराह्न 04:00 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, सुपौल (प्रशाखा, पी० एम० पोषण योजना), सुपौल उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुपौल (विलियम्स हाई स्कूल, सुपौल) में हाथों–हाथ अथवा कार्यालय के ई–मेल mdmssupaul@gmail.com पर उपलब्ध कराया जाय। तदुपरांत उन्हें विद्यालयों में आवश्यकतानुसार निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त तथा विभागीय मापदंड के अनुरूप थाली उपलब्ध कराने हेतु आदेश दिया जाएगा।

स्टील थाली की विशिष्टियाँ एवं अधिकतम दर का निर्धारण विभागीय पत्रांक 2558 दिनांक 21.11.2023 अन्तर्गत किया गया है। उक्त पत्र को विभागीय website अथवा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर अवलोकन किया जा सकता है।

विभागीय निर्धारित प्रति स्टील थाली की अनुशंसित विवरणी निम्नवत् है:–

वर्ग	लम्बाई	चौड़ाई	गहराई	गेज स्टील चादर की मोटाई	वजन	प्रति स्टील थाली अधिकतम दर
1 से 5	24 cm – 27 cm	24 cm – 27 cm	2.5 to 3.5 cm	25-22 0.5 mm to 0.7 mm	250 gm – 270 gm	120.00 रूपये
6 से 8	27 cm – 30 cm	24 cm – 27 cm	2.5 to 3.5 cm	25-22 0.5 mm to 0.7 mm	270 gm – 300 gm	140.00 रूपये

ह०
जिला शिक्षा पदाधिकारी
सुपौल।

ज्ञापांक 856 /सुपौल दिनांक 07 / 12 /2023

प्रतिलिपि:– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, NIC, Supaul को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे जिले के NIC के website पर Upload करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि:– जिला पदाधिकारी, सुपौल की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:– निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह० 07/12/23
जिला शिक्षा पदाधिकारी
सुपौल।

["D:\Account work\Socouse Letter MK.docx"] Page 166

Supplying & Installation of Furniture at Different School Buildings in all district of Bihar under head of Primary Education, Education Department, Bihar

बिहारराज्य शैक्षणिकआधारभूतसंरचनाविकासनिगमलिमिटेड
BIHAR STATE EDUCATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION LTD
(A Govt. of Bihar Undertaking)
ISO 9001:14001 OHSAS 18001

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–12 वर्ष 2023–24

Sl No.	Name of Work	BOQ Amount (in crore)	EMD (In Crore)	Cost of BOQ (In Rs.)	Bid Processing Fee	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Supply and installation of Furniture at Different School Buildings in all district of Bihar under Head of Primary Education, education Department, Bihar	30.00	0.60	5,000/-	As appeared on e-tendering website	6 Month	SBD
2	Supply and installation of Furniture at Different School Buildings in all district of Bihar under Head of Secondary Education, education Department, Bihar	20.00	0.30	10,000/	As appeared on e-tendering website	6 Month	SBD

(ii) वेबसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर [illegible]

(1) [illegible] – दिनांक–27.07.2023 से 04.08.2023, 15:00 बजे तक।

(2) प्री बिड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि – दिनांक–31.07.2023, 16:00 घंटा तक [illegible] बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना।

(3) [illegible] – दिनांक–05.08.2023 [illegible], समय– 16:00 बजे तक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना।

(4) टेक्निकल बिड खोलने की तिथि एवं समय – दिनांक–05.08.2023, 16:30 बजे।

(5) [illegible] – तकनीकी मूल्यांकन के बाद।

(6) निविदा खोलने का स्थान – वेबसाईट–www.eproc2.bihar.gov.in पर

(7) निविदा की वैधता की अवधि – 120 दिन

[illegible] (user ID) [illegible] (Password) [illegible] (Digital Signature) [illegible] www.eproc2.bihar.gov.in [illegible]

[illegible] www.eproc2.bihar.gov.in [illegible]

(10) (क) Bid Processing Fee as appeared on the e-tendering website www.eproc2.bihar.gov.in & BOQ cost as mentioned is mandatory to be paid through e-payment mode i.e. Internet payment gateway, (Credit/Debit card), Net Banking, NEFT/RTGS" Bids along with necessary online payments must be submitted through e-procurement portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specific in the NIT/Corrigendum. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non submission of Tender/ Non Reconciliation of Online payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/ Holidays or any other reason.

(ख) EMD Can be paid through e-Payment mode i.e. "Internet payment gateway (Credit/Debit Card), Net banking, NEFT/RTGS" या Bank Guarantee [illegible] Valid for 45 days beyond Bid Validity Period) [illegible]

(ग) [illegible] Bank Demand Draft मान्य नहीं होगा।

Page 4 of 29

उल्लंघन कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद भी के. के. पाठक जाँच नहीं करवा रहे हैं। यह कहीं न कहीं के. के. पाठक के ईमानदारी पर भी सवाल उठाता है।

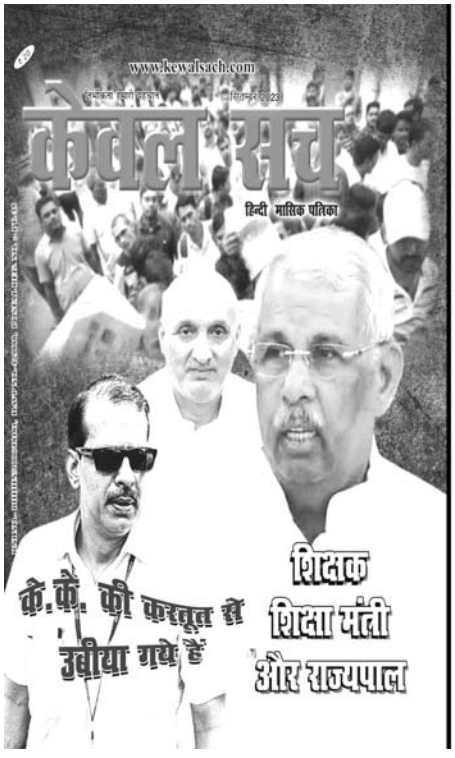

आज स्कूल में बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा बिहार के स्कूलों में घटिया बेंच–डेस्क की आपूर्ति हुई है। केवल सच ने पहले ही राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर बेंच–डेस्क की निविदा में भ्रष्टाचार से अवगत कराया था। मुख्य सचिव ने भी अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग को इसकी जाँच का आदेश दिया था, लेकिन मुख्य सचिव के पत्र के बावजूद भी अपर मुख्य सचिव द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया। आज इस निविदा में इतनी खामी है कि महीने–दो–महीने में ही बेंच और डेस्क टूटने लगे हैं। बेंच डेस्क में लकड़ी के जगह घटिया स्तर के बोर्ड का इस्तेमाल हुआ है। अपने आपको ईमानदारी का तगमा पहने अधिकारी को पूर्व से सूचना होने के बावजूद भी क्या कारण है कि भ्रष्टाचार को रोका नहीं गया। बिहार राज्य

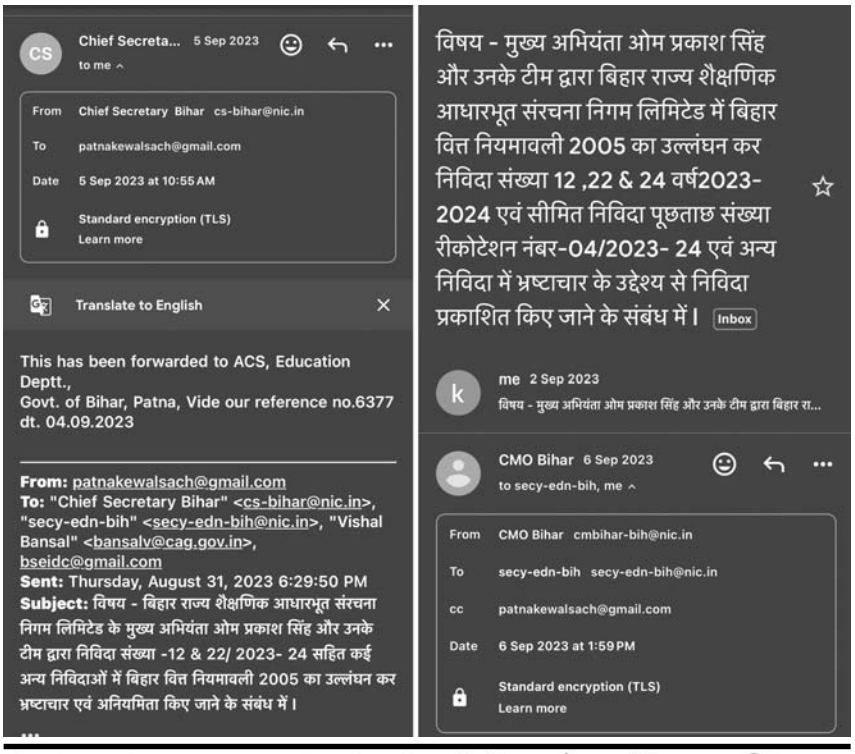

Chief Secreta... 5 Sep 2023
to me

From Chief Secretary Bihar cs-bihar@nic.in
To patnakewalsach@gmail.com
Date 5 Sep 2023 at 10:55 AM
Standard encryption (TLS)
Learn more

Translate to English

This has been forwarded to ACS, Education Deptt.,
Govt. of Bihar, Patna, Vide our reference no.6377 dt. 04.09.2023

From: patnakewalsach@gmail.com
To: "Chief Secretary Bihar" <cs-bihar@nic.in>, "secy-edn-bih" <secy-edn-bih@nic.in>, "Vishal Bansal" <bansalv@cag.gov.in>, bseidc@gmail.com
Sent: Thursday, August 31, 2023 6:29:50 PM
Subject: विषय - बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता ओम प्रकाश सिंह और उनके टीम द्वारा निविदा संख्या -12 & 22/ 2023- 24 सहित कई अन्य निविदाओं में बिहार वित्त नियमावली 2005 का उल्लंघन कर भ्रष्टाचार एवं अनियमिता किए जाने के संबंध में।

विषय - मुख्य अभियंता ओम प्रकाश सिंह और उनके टीम द्वारा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड में बिहार वित्त नियमावली 2005 का उल्लंघन कर निविदा संख्या 12 ,22 & 24 वर्ष2023-2024 एवं सीमित निविदा पूछताछ संख्या रीकोटेशन नंबर-04/2023- 24 एवं अन्य निविदा में भ्रष्टाचार के उद्देश्य से निविदा प्रकाशित किए जाने के संबंध में। Inbox

me 2 Sep 2023
विषय - मुख्य अभियंता ओम प्रकाश सिंह और उनके टीम द्वारा बिहार रा...

CMO Bihar 6 Sep 2023
to secy-edn-bih, me

From CMO Bihar cmbihar-bih@nic.in
To secy-edn-bih secy-edn-bih@nic.in
cc patnakewalsach@gmail.com
Date 6 Sep 2023 at 1:59 PM
Standard encryption (TLS)
Learn more

बैठते ही टूट जा रहीं स्कूलों की नई बेंच, हैरत में छात्र-शिक्षक

रवि कुमार • पटना

राजकीयकृत चिरैयाटांड उच्च माध्यमिक स्कूल में टूटी नई बेंच-डेस्क • जागरण

स्कूल में फेंका मिला डेस्क का हिस्सा।

स्कूलों में नई बेंच-डेस्क आने से विद्यार्थियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें प्रसन्नता थी कि अब जर्जर बेंच पर नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन यह क्या, बेंच पर बैठते ही बीच से टूट जा रही हैं। यह विद्यार्थियों को ही नहीं, बल्कि शिक्षकों और विभागीय अधिकारियों को भी हैरत में डाल रहा है कि नई बेंच डेस्क की हालत ऐसी कैसे हो सकती है। यह हाल राजकीयकृत चिरैयाटांड उच्च माध्यमिक स्कूल का है। वहां इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा जा सकता है।

बेंच के किनारे बैठने के निर्देश : स्कूल को 50 बेंच-डेस्क मुहैया कराए गए हैं। ये लकड़ी के बजाय कुन्नी (लकड़ी के बुरादे) व फेविकोल से तैयार पटरे से बनाए गए हैं। नतीजा, बेंच इतनी कमजोर हैं कि तीन बच्चों के बैठते ही टूट जा रही है। भार देने से डेस्क का भी बुरा हाल हो जा रहा है। यह हालत देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने बेंच पर तीन की जगह दोनों किनारों पर एक-एक छात्र को बिठाने का निर्देश दिया है। बीच के ज्यादा कमजोर व बिना लोहे के सपोर्ट वाले हिस्से को खाली रखना है। बताते चलें कि शिक्षा विभाग ने एक एजेंसी को जिले में स्कूलों की मांग के अनुसार कुल 67 हजार बेंच-डेस्क पहुंचाने का ठेका दिया है।

डीईओ ने एजेंसी बदलने का दिया निर्देश : जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) को जब इसकी सूचना मिली तो उन्होंने चिरैयाटांड स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात की। प्रधानाध्यापक ने डीईओ को बताया कि बेंच-डेस्क की गुणवत्ता बहुत खराब है। लकड़ी की कुन्नी से बेंच-डेस्क बनाए गए हैं। प्रधानाध्यापक ने भी शिकायत की कि बेंच-डेस्क में लगे लोहे के फ्रेम भी कमजोर हैं। शिकायत मिलने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने संबंधित एजेंसी को बेंच-डेस्क बदलने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि बेंच-डेस्क के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने वाली एजेंसी को काली सूची में डाला जाएगा। नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। डीईओ ने कहा कि अन्य स्कूलों को मिली बेंच-डेस्क की जांच कराई जाएगी।

गुणवत्ता की जांच करेंगे डीईओ

डीईओ संजय कुमार ने कहा कि वे स्कूलों में जाकर बेंच-डेस्क की गुणवत्ता की जांच करेंगे। जांच के लिए प्रखंड स्तर पर अभियंताओं की टीम थी। सभी को 30 मार्च तक रिपोर्ट देनी थी। जांच टीम को संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षर भी कराना था। जिले में 130 स्कूलों ने बेंच की मांग की थी। इनमें 45 स्कूल पटना शहर के थे। मांग के अनुसार, 67 हजार बेंच डेस्क तैयार किए गए थे। दोषियों पर कार्रवाई होगी।

सरकारी स्कूलों में भ्रष्टाचार की थाली

बाजार में उपलब्ध 59 रुपए की थाली का बिल बनाया जा रहा है 120 रुपए

विभाग बना है अंजान, डीपीओ बोले- गुणवत्ता की जांच के लिए थाली के दो नमूने मांगे गए हैं

ये हैं मानक और हकीकत

लोकल स्टील थाली की आपूर्ति हो रही

बिल भुगतान के लिए बनाया जा रहा दबाव

नामांकन की 30% थाली क्रय का आदेश

वेंडर पर होगी कार्रवाई

अमृता हत्याकांड का खुलासा • 30 मार्च को बहियार फसल रखवाली को गई थी 8 वर्ष की बच्ची

पुलिस के सामने मां ने कबूला-मैंने ही की थी छोटी बेटी की हत्या; बड़ी को पकड़ना चाहा तो भाग गई, गिरफ्तार

बक्सर : पत्नी के सामने पति को ट्रैक्टर से रौंदा, हुई मौत

शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा संवेदक के साथ मिलकर निविदा की शर्त और नियम तैयार किया जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में फर्निचर के लिए निकाली गई निविदा संख्या-12/2023-24 में बिहार वित्त नियमावली 2005 का उल्लंघन कर भ्रष्टाचार किया गया है। निदेशक, मिड डे मिल द्वारा निविदा संख्या-2013/23-24 के द्वारा बिहार के 70,699 स्कूलों में खाने का स्टेनलेस स्टील प्लेट की निविदा प्रकाशित की गई, लेकिन यह निविदा भी भ्रष्टाचार के भेट चढ़ गया। उसके बाद जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा थाली आपूर्ति के लिए निविदा प्रकाशित किया गया, इसमें तो बिहार वित्त नियमावली का घोर उल्लंघन किया गया। बिहार राज्य वित्त नियमावली के अनुसार कोटेशन निविदा (सीमित निविदा) के लिए न्यूनतम अवधि सात दिनों की होती है, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मात्र 5 दिनों की दी गई। शिक्षा निगम के तहत पहले से ही संवेदकों का चयन कर निविदा के माध्यम से सिर्फ खानापूर्ती की गयी है, जिसका परिणाम है सारे जिलों में घटिया स्तर कि थाली आपूर्ति की गयी।

यही नहीं बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के द्वारा 71 हजार प्रारंभिक विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक की आपूर्ति की गई, जिसका कागज अवमानक स्तर का है। पन्ना पलटते ही पन्ना फट जा रहा है। मामला प्रकाश में आने पर कमिटि बनाई गई, लेकिन नतीजा ढ़ाक के तीन पात वाली हो गई है, क्योंकि पैसों का बंदरबांट ईमानदारीपूर्वक किया गया है। यही नहीं दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी गई। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के प्रबंध निदेशक सन्नी सिन्हा को भागलपुर जिले में किताबों की गुणवत्ता की जाँच की जिम्मेदारी दी गई है।

अब प्रश्न है कि विधान सभा में सुशासन के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी कहते है कि के. के. पाठक ईमानदार पदाधिकारी है, इसलिए लोग उन्हें तंग करते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री को बताना होगा कि थाली, फर्निचर और किताब में घोटाले करने वाला पदाधिकारी ईमानदार कैसे हो सकता है। क्या राज्यपाल, मंत्री, विधायक और जनता के साथ दुर्व्यवहार करने से कोई ईमानदार हो जाता है या हिन्दू-मुस्लिम के धार्मिक भावनाओं से खेलने के कारण अधिकारी ईमानदार हो जाता है। लगता है कि नीतीश कुमार ने ईमानदारी की नई परिभाषा गढ़ी है! ●

अवैध अस्पताल और लैब की भरमार

आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा खिलवाड़

स्वास्थ्य विभाग का है यही हाल, सब गोलमाल है भाई सब गोलमाल...!

● शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला

बिहार में पिछले 18 वर्षो से डबल इंजन की सरकार चल रही है जो बीच के कुछ वर्षो को छोड़ दे तो बाकी कार्यकाल सुशासन बाबू की सरकार जिसमें भाजपा गठजोड़ की रही है। डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार पर सबसे ज्यादा बोलने का ठेका भाजपा ने अपने सिर माथे रखा है, जिसके जिम्मे स्वास्थ्य विभाग रहा है। मंगल पाण्डेय जैसे मुँहजोड़ आदमी को स्वास्थ्य विभाग जैसे बड़े विभाग को सौप नीतीश कुमार की सोच कहे या मजबूरी समझ से पड़े है चूंकि मंगल पाण्डेय के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग का सबसे अधिक निविदा को निकाल भाजपा ने अपनी फेस को चमकाने में कोई कोर कसर नही छोड़ा तब बिहार भाजपा के सबसे मजबूत प्रदेश अध्यक्ष की नामो में शुमार पाण्डेय की गाड़ी चल पड़ी थी, जिसकी कॉपी वर्तमान में सम्राट चौधरी करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से एक अंश भाग यूपी वाले की नकल करते हैं जो अब तक सफल होते दिख नही रहा है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ ज्यादा बेहतर करने की सोच एवं सुधार के साथ सरकार ने वर्ष 2010 में क्लिनिकल स्टेबलिशमेंट एक्ट के जरीय पूरे भारत में एक साथ नियम का पालन कर आमलोगों से जुड़े समस्या को निजात दिलाने तथा अस्पताल के संचालको के मनमानी तरीको को समाप्त करने, उस पर अंकुश लगाने को लाया गया बिल आज पूरे भारत में लागू है, जो बिहार ने वर्ष 2013 में इसे स्वीकार कर लागू किया, तब से अबतक हजारों अवैध रूप से संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम, जाँच घर, क्लिनिक के ऊपर शिकंजा कसा गया है। बाबजूद जिले में स्वास्थ्य माफियाओ के आगे सरकार विवश है। सिस्टम दम तोड़ रही है, आँखों के सामने बिना मानको का पालन किये अस्पताल की भरमार है जिसके अंदर अल्ट्रासॉउन्ड, जाँच घर, दवाखाना जो बिना अनुमति के संचालित किये जा रहे हैं, जिसके कारण प्रतिदिन कुछ न कुछ घटनाये होती रहती है। वैसी घटनाये जिसकी जानकारी को छिपाने में ही भला समझने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है, जो थाना-पुलिस जाने में कतराते हैं, किन्तु फिर भी जो सामने अखबारों की सुर्खियां बटोरती है, उसकी संख्या भी हजारों मे है।

पटना जैसे जिले में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक, नर्सिंग होम, पैथोलोजी की संख्या लगभग बीस हजार से ऊपर है जो मात्र एक हजार के लगभग निबंधित किये जाने के आंकड़े हैं बाकी उन्नीस हजार मंझोले अस्पताल, नर्सिंग होम, जाँच घर, क्लिनिक अवैध संचालित किये जा रहे हैं। वही वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, जमुई, मुंगेर, अरवल, भोजपुर में निबंधित संस्थान जिसमें अस्पताल, नर्सिंग होम, अल्ट्रासॉउन्ड, जाँच घर, क्लिनिक का निबंधन मात्र न्यूनतम 150 से 180 तक है, जबकि इन जिलों में कम से कम चार हजार से अधिक ऐसे संस्थान/प्रतिष्ठान है, जो बिना निबंधन करवाये अवैध रुप संचलित किये जा रहे हैं। आश्चर्य की

बात जरूर लगता होगा कि जब सरकारी रेफरल अस्पताल गेट के आगे अवैध रूप से ऐसे संस्थान का संचालन किया जाता देखते हैं किन्तु यह आश्चर्य की बात नहीं, यह सब कुछ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की सहमति से चलती है। जिस निजी संस्थान में स्वयं एक सरकारी चिकित्सक निजी संस्थान के संचालको से कमीशन में मोटी राशि यानी जाँच के आधा हिस्सा स्वयं वसूलते हैं, चाहे जाँच गलत क्यों न हो। जो मरीजों को जाँच के लिए भेजते हैं, यह सब जानते हुये की संस्थान में मानको का अनुपालन नही किया गया है, जिसकी जाँच रिपोर्ट गलत हो सकती है, जिसका ऑपरेट एक तकनीशियन करता है, जो बिना पैथोलॉजी सीट रखे फर्जी हस्ताक्षर कर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिससे मरीजों की जान अक्सर चली जाती है, जो सुर्खियां बटोरती रही है। यानी बिहार राज्य में एक गणना के अनुमानित हिसाब से कम से कम दो लाख संस्थान/अस्पताल/क्लिनिक/नर्सिंग होम संचालित किये जा रहे हैं, जिसमें मात्र आठ हजार के आसपास निबंधित है, शेष एक लाख बानबे हजार अवैध है, जिससे प्रति वर्ष करोड़ों रूपये का सरकारी राजस्व की चोरी कर भ्रष्टाचार करवाने में सरकारी चिकित्सक शामिल हैं।

बिहार ने देश में जीरो टोरलेंस की डबल इंजन वाली सरकार से प्रसद्धि पायी है तब इसके लिए खूब तड़का लगा कर परोसा गया, कही गयी उक्ति आज बिहार से बाहर निकलकर देश के कोने-कोने में यह शब्दावली अपनी पहचान बना चूकि है, किन्तु इंजन सीसी की क्षमता नही बढ़ने से गाड़ी की स्पीड कम हो रही है। लोड की वजह से डबल इंजन को सर्विस देना होगा। भूमिका महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि दर्जनों बार करोड़ो रूपये खर्च करके अप्रवासी भारतीयों का ग्लोबल मिट किया गया, इसके परिणाम तो कुछ निकला नही किन्तु मिट को कराने वालो कि किस्मत चमक गयी, शायद उनके लिए यही उपलब्धि होंगी कि चलो कम से कम NRI को बुलाकर एक चुनाव तो देख लिया। आज कि चुनावी सभाओं में बिहार के मुख्यमंत्री पेट पर हाथ घुमाकर जब मंच से बोलते है, विपक्षी सरकार जो 2005 के पहले थी उसकी कार्यशैली पर तीखे हमला कर आमलोंगो को समझाने कि कोशिश करते हैं, विधि-व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल खड़े कर अपने को ऊपर बताते हैं किन्तु बीस वर्षों के भीतर आज तक बिहार में कितने उद्योग स्थापित हुये इसकी जानकारी नहीं देते। जो सरकार बीस वर्षों के कार्यालय में उद्योग नहीं लगा सकी, उसके लिए और कितना समय चाहिए, जबकि डबल इंजन कि सरकार एक दशक से साथ में है, जो समझ से पड़े है। ये सियासी बखेरा कि द्वन्द में राज्य कि जनता को ऊपर उठाना होगा, तब 2005 से पहले कि पूर्ववर्ती सरकार फेल थी माना जायेगा। नई सरकार को जनता ने मौका दिया तो फिर आज नीतीश कुमार को कौन सी शक्ति चाहिए जिससे बिहार में औद्योगिक क्रांति आये। साहब आप एक पीएम मटेरियल है, समझिये अपने को और शेष बचे दिनों के भीतर कीजिए कमाल। चूकि बिहार लाचार और बीमार नहीं रहा। अब जिसमें डबल इंजन लग चुका है, जिसके साथ सरकार के एक आगे दूसरे पीछे से दो-दो उपमुख्यमंत्री लगे हो, तब किस बात कि चिंता। कर दीजिये कमाल, ला दीजिये रामराज्य!

मुद्दों पर वापसी करना चाहता हूं जहाँ पूरा का पूरा स्वास्थ्य महकमा भ्रष्टाचार कि चपेट मे है। सरकारी चिकित्सक के ऊपर सरकार के निर्देश का कोई असर नहीं दिखता। सरकारी अस्पताल में कार्य कर रहे डॉक्टर, जो रेजिडेंट डॉक्टर को आगे कर हाजिरी बना कर अपने निजी हॉस्पिटल, नर्सिंग में चले जाते हैं। कोई ऐसा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी नहीं है, जिनके पास अपना हॉस्पिटल नही चल रहा है। एक छोड़िये, एक के अलावे कई हॉस्पिटल/नर्सिंग होम के स्वामित्व है। कुछ अपने नाम पर तो कुछ के साथ पार्टनरशिप पर संस्थान को संचालित किया जा रहा है। सरकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जिनके भरोसे सरकार अरबों रूपये खर्च कर मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल कि सुविधा दे रही है, उसमे बैठकर सरकारी चिकित्सक बाहर के ऐरा-गैरा जाँच घर से जाँच करवाने कि सलाह देता है। जिस जाँच घर में तकनीशियन रखकर डॉक्टर का फर्जी हस्ताक्षर कर जाँच रिपोर्ट मरीज को देता है, तब भला उस मरीज का क्या होगा, उनके जिंदगी का क्या होगा? इससे अधिक उस सरकार का क्या? मतलब जिनके भरोसे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हो। जो सरकार आम लोगों के इलाज पर अरबों खर्च कर लोगों कि बीमारी से मुक्ति चाहती है, जहाँ बीमारी को नहीं बीमार को खत्म

करने कि साजिश हो रही है। सरकारी चिकित्सक निजी संस्थान के मालिकों से मिलकर पचास फीसदी कमीशन पर जाँच लिखते हैं। माना कि माननीय मुख्यमंत्री को इसकी जनकारी का अभाव होगा किन्तु विभागीय मंत्री मंगल पाण्डेय को जानकारी नहीं है क्या!

राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानो /अस्पताल में शुमार जयप्रभा मेदांता सुपरस्पेशलिटी अस्पताल, जो पटना के कंकड़बाग में अवस्थित है और जिसे बिहार सरकार ने 25% उन गरीब मरीजों के मुफ्त में ईलाज करने कि शर्त पर फ्री में जमीन दे दी, जिसका शुभारंभ 29 अक्टूबर 2021 को किया गया। जिसके भीतर 700 बेड कि क्षमता है, जो पहले चरण यानी शुरू के दिन से 350 बेड के साथ शुरुआत कि गयी थी, जिसका निबंधन क्लिनिकल एक्ट के मुताबिक संस्थान के प्रबंधक द्वारा मात्र 350 बेड कि ली गयी है किन्तु वर्तमान में यह 700 से अधिक बेड लगा कर कार्य कर रहा है। वही सबसे पुराने संस्थान में बेहतर मेटरनिटी के लिए शुमार अस्पताल कुर्जी होली फैमिली का स्थान अव्वल दर्जे पर है जो आज भी कायम है, जो नर्सिंग सुविधा के लिए बेहतर कार्य के रूप में जाना जाता है, जिसके भीतर 500 बेड लगाकर व्यवसयिक गतिविधियां कि जा रही है। यह आंकड़े जिसका हम नही बल्कि संस्थान कि तरफ से जारी गूगल बता रहा है, जिसमें किस बेड का कितना चार्ज रखा गया है। किन्तु फिर भी इस आंकड़े से अलग भी सत्यता कुछ और भी है। ठीक इसके बगल के महावीर अस्पताल जो मैनपुरा में सैकड़ों बेड लगा कर अस्पताल का संचालन कर रही है, जो यह संस्थान मात्र 90 बेड कि अनुमति के साथ निबंधन करवाया गया है। इससे पहले से अस्पताल कार्य कर रही पाटलिपुत्र अवस्थित सहयोग अस्पताल का जो मरीजों को मल्टीस्पेशलिटी कि सुविधा मुहैया करवाती है जिसके द्वारा स्वास्थ्य विभाग से मात्र 50 बेड का रजिस्ट्रेशन करवा कर कार्य कर रहा है, जबकि इसके भीतर कि सत्यता कुछ और भी है। इस संस्थान में 150 बेड कि क्षमता है जो कार्य भी कर रहा है, जिसके लिए मरीजों के देखभाल के लिए रखे गये पैरामेडिकल स्टाफ (नर्स) कि

सुविधा मात्र 18 कि है। यह भी संदेह के घेरे में है जो बिना दस्तावेज, डिग्री प्रमाण पत्र के बिना दस्तावेज जो सूची लिस्टेड कर शपथ पत्र के स्वास्थ्य विभाग को समर्पित किया गया है, वह भ्रामक है। क्योंकि एक हिसाब से कम से कम तीन मरीजों पर एक नर्स कि सुबिधा देते हैं तो इसकी गणना सौ में तैंतीस पार हो जाती है, जो संस्थान के भीतर कि संख्या कुछ और कह रही है। जिसके लिए हर साल संस्थान को निबंधन का नवीनीकरण कराने से पूर्व बायोमेडिकलवेस्ट प्रमाण पत्र, अग्निशमन के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संख्या कि विवरणी के स्थान अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के पश्चात् ही किसी संस्थान का निबंधन किया जाना है। बात इतने से खत्म नही होता। इन सारी प्रक्रिया को करने के पश्चात् निबंधन किये जाने कि अनुशंसा किये जाने पहले असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय से चिकित्सा पदाधिकारी सह निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा संस्थान के अंदर कार्य कर रहे उपकरण, स्टॉफ, चिकित्सा कि दस्तावेजी विवरणी से क्रॉस मिलान करने के पश्चात् निबंधन के लिए अग्रसित किया जाता है जो यह प्रक्रिया हर साल संस्थान के नवीनीकरण के लिए दोहराया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र पाटलिपुत्र अवस्थित सीएनएस अस्पताल कि क्षमता सैकड़ों बेड कि है, किन्तु इनके द्वारा भी मात्र 90 बेड कि ली गयी है। वही हाल रुबन अस्पताल, पाटलिपुत्र अवस्थित संस्थान का है, जो एक अस्पताल पर दो-दो अस्पताल का कार्य चल रहा है, जिसकी क्षमता सैकड़ो बेड कि है जो मात्र 90 से काम चला रहा है। इस तरह से पंजीयन कराने में अनिमियतता के पीछे कारण को समझना

होगा। पटना के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर श्रवण कुमार जो वर्तमान में प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय पूर्णिया में क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के पद पर पदोन्नति देकर पटना से पूर्णिया के लिए विदा किये गए हैं, उनके कार्यकाल में पिछले छह महीने के भीतर लगभग दो सौ अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लिनिक/जाँच घर का नवीनीकरण/नये संस्थानों का पंजीयन करवाया गया है। जिसमें क्लिनिकल एक्ट का अनुपालन में अनिमियतता, लापरवाही कि गयी है। जो संस्थान के संचालको से मोटी राशि लेकर टेबल पर बैठे संस्थान का निरिक्षण किये बगैर इस बात का प्रमाण पत्र दे दिया है कि जो संस्थान के तरफ विवरणी दिया गया है, वह सत्य है। जिसकी सत्यता पर संदेह है, जो सत्य से पड़े है। जो आंकड़े झूठे और मनगढ़ंत है, जिसकी आपत्ति एवं शिकायत वैसे फर्जी डिग्रीधारी चिकित्सक, संस्थान के विरुद्ध लगातार पिछले छह महीने से विभाग में जाँच एवं कार्रवाई के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आरटीआई एक्टिविस्ट सह व्हिसिलब्लोयर त्रिभुवन प्रसाद यादव ने केवल सच पत्रिका से एक औपचारिक बातचीत के दरम्यान कहा कि संस्थान के तरफ से पंजीयन /नवीनीकरण के लिए जो दस्तावेज विभाग को समर्पित किये जा रहे हैं, वह फर्जी है। जो आंकड़े झूठे और मनगढ़ंत हैं, जिसमें कुछ सत्य को छोड़कर खानापूर्ति मात्र है। उन्होंने कहा कि पंजीयन/नवीनीकरण से पूर्व निरीक्षण पदाधिकारी के द्वारा जिन आकड़ों, विवरणी एवं दस्तावेज के आधार पर यह पुष्टि कि गयी है, जिसका जाँच कराना अतिआवश्यक होगा। जिसके वजह से सरकार के नियम के विपरीत कार्य किया गया है, जिससे करोड़ो रुपये के सरकारी राजस्व का क्षति एवं नुकसान किया गया है। जिनसे निजी तौर पर वास्तविक आंकलन कर राजस्व कि वसूली कि जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्षो से जमे पटना जिला में डॉक्टर कामिनी सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी उदाहरण मात्र है। ऐसे पदाधिकारी अन्य जिले में काबिज है, जिसके माध्यम से मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी वसूली कर काली कमाई करते हैं। 13 अप्रैल 2024 का व्हिसिल ब्लोयर श्री त्रिभुवन प्रसाद यादव के द्वारा पटना जिला के सिविल सर्जन कार्यालय में संधारित संस्थानों के संबंधित औपबंधिक दस्तावेजो का अवलोकन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि संस्थान के तरफ से पैरामेडिकल स्टॉफ कि सूची मात्र देकर खानापूर्ति कर दिया गया है, वही सैकड़ो संस्थान ऐसे है, जिनके ड्राफ्ट महीनो से पड़े हैं नवीनीकरण/निबंधन के लिए। क्योंकि उनके पास दस्तावेज पूर्ण प्रक्रिया से भिन्न है, जबकि इससे पहले उसी संस्थान का निबंधन किया जा चुका है जो संस्थान ने वर्षो से नवीनीकरण नही करवाकर संस्थान का संचालन कर रहे हैं। उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, न कि फाइन मात्र लगाकर सिर्फ नवीनीकरण कर लिया जाना चाहिए। सीधी बात है, जो संस्थान नियम का फ्लो वर्षो से नही किया है वह उसे अवैध माना गया है। क्योंकि उसका निबंधन समाप्त होने के पश्चात तुरंत नवीनीकरण करवाना चाहिए, जो कुछ महीनो के लिए गैप के लिए ऑप्शनल प्रतिदिन के हिसाब से सौ रूपये फाईन जोड़ कर नवीनीकरण किया जाना है किन्तु एक्ट ऐसा नही है कि कोई संस्थान वर्षो तक पंजीयन नही कराकर ऐसे ही संचालित करते रहे।

भोजपुर जिले के तत्कालीन असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर के. एन. सिन्हा जो पद पर रहते सदर अस्पताल आरा के बगल में वर्षो से आनंद हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का संचालन कर रहे थे, जिसकी शिकायत विभाग एवं जिला प्रशासन से कि गयी थी। किन्तु इनके ऊपर कार्रवाई करने में परेशानी हो रही है, जो जिला प्रशासन भोजपुर के द्वारा कहा गया है। चूकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सर्वोच्च न्यायलय में अस्पतालो के निबंधन किये जाने से संबंधित रूलिंग पता बातचीत चल रही है। इस कारण से हमने अपने संस्थान का निबंधन नहीं करवाया है। इस कार्य में इनके डॉक्टर पुत्र सागर आनंद भी शामिल हैं। सिविल सर्जन से पूर्व भोजपुर जिले में वर्षो से पदस्थापित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अगिआव, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर के पद पर रहते इनके द्वारा अपने नजदीकी, संगे-संबंधी को बिना लाइसेंस का संस्थान चलाने कि छूट प्रदान कि गयी, जिस कृत में स्वयं डॉक्टर के. एन. सिन्हा शामिल हैं, जो एक राष्ट्रीय चिकित्सा रत्न से सम्मानित चिकित्सक हैं और इनके द्वारा वित्तीय भ्रष्टाचार किया गया तथा संस्थानों के संचालक से मिलकर वित्तीय भ्रष्टाचार करवाया गया है। जिनके विरुद्ध वर्ष 2011-12 में स्वास्थ्य विभाग ने कार्य में लापरवाही को लेकर चेतावनी देते हुये भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करने, कार्य में लापरवाही नहीं करने कि चेतावनी देकर राहत दी थी। बावजूद आदतन इन्होंने भ्रष्टाचार किया और अन्य से भी करवाया है। जिनके विरुद्ध त्रिभुवन प्रसाद यादव ने विभाग से शिकायत दर्ज करवाया है। भोजपुर के आरा सदर में वर्षो से संचालित शिशु प्रजनन के लिए जाने-माने चिकित्सक सुनीति प्रसाद जो पटना के कुर्जी होली फैमिली अस्पताल में अपनी सेवा दी हैं, जो भोजपुर में मेटरनिटी सेंटर के नाम

से बड़े संस्थान का संचालन करती हैं। जिनके डॉक्टर पति फ्रेक्चर क्लिनिक का अवैध संचालन करते हैं और सिविल सर्जन डॉक्टर के. एन. सिन्हा के करीबी हैं। जिनके विरुद्ध लगातार शिकायत करने के पश्चात कार्रवाई नहीं की गयी, जो संस्थान के भीतर अल्ट्रासॉउन्ड, जाँच मशीन रखकर निर्भय संचालन कर रहे हैं। वही पटना अल्ट्रासॉउन्ड, इक्को सेंटर, आकस्मिक चिकित्सा केंद्र, ऑर्थोपेडिक सेंटर, शेखर मेमोरियल अर्थोसेंटर, फिजियोथरेपी एंड लकवा सेंटर, कल्याण साई हॉस्पिटल, गणिनाथ हॉस्पिटल, शिवम नर्सिंग होम, डॉक्टर सीडी राय मेमोरियल क्लिनिक, शैलय मेमोरियल एंड मेटरनिटी सेंटर, गजानन हॉस्पिटल, मैक्सो इमरजेंसी हॉस्पिटल, कृष एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, ओम चाइल्ड हॉस्पिटल, मौर्या एक्सरे, सत्यम अल्ट्रासॉउन्ड, महावीर क्लिनिक, बुद्धा हॉस्पिटल, महावीर हेल्थ एंड डिजिटल एक्सरे, ओम हॉस्पिटल, महावीर एमरजेंसी हॉस्पिटल, डॉक्टर के.पी. मेडिकल एंड पेट क्लिनिक, जय बजरंग क्लिनिक, बसु मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, जनता अल्ट्रासॉउन्ड, रमन अल्ट्रासॉउन्ड, उजाला हॉस्पिटल, वेदांता ऑर्थोपेडिक सेंटर, तारा जाँच घर, जन हेल्थ केयर, कुमार अल्ट्रासॉउन्ड, शर्मा हेल्थ केयर जो एक आयुष ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा (एक पंजीयन पर दो क्लिनिक और जिसके भीतर दवाखाना भी है) संचालन किया जा रहा है। ऐसे सैकड़ो जाँच घर, क्लिनिक, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम अवैध रूप से सिर्फ आरा सदर के भीतर में संचालन किया जा रहा है जबकि पंजीयन मात्र 167 संस्थानों कि करवाई गयी है, जिसकी भी कार्रवाई के लिए शिकायत कि गयी है।

रेफरल अस्पताल सोनपुर जिला सारण के मुख्य द्वार के समक्ष दरियापुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर काजल कुंवर एवं पटना के NMCH में कार्यरत इनके डॉक्टर पति के द्वारा ऑर्नेट हॉस्पिटल जिसमें चोरी से अल्ट्रासॉउन्ड, जाँचघर, प्रतिबंधित दवाओं का स्टॉक रखकर संचालित किया जा रहा है, जो हॉस्पिटल के

ठीक पचास मीटर कि दूरी पर डॉक्टर काजल कुंवर के द्वारा अपने आवास पर वर्षो से अवैध रूप से संचालित श्री हरि अल्ट्रासॉउन्ड का संचालन किया जा रहा है, जो सरकारी रेफरल अस्पताल सोनपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कि जानकारी में संचालन किया जा रहा है, जो डॉक्टर काजल कुंवर के द्वारा एक और ऑर्थो एंड ज्ञानो क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है, जिसकी शिकायत कि गयी है। हॉस्पिटल के ठीक बगल में न्यू हरिओम अल्ट्रासॉउन्ड एवं जाँच घर संचालन एक फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर द्वारा अल्ट्रासॉउन्ड का संचालन किया जा रहा है, जो सोनपुर रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा कमीशन लेकर उक्त जाँच घर जाँच करवाने के लिए भेजा जाता है जिससे 50% प्रतिशत कमीशन लेकर मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी भी शिकायत कि गयी है। सवाल से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पीछे नही हट सकते। यह नहीं कह सकते कि अवैध रूप से संचालित जाँच घर, हॉस्पिटल कि जानकारी मुझे नही है, क्योंकि खुद इनके द्वारा सरकारी अस्पताल में गए मरीजों के जाँच के लिए भेजा जा रहा है। जिस संस्थान का पता हाजीपुर वैशाली लिखकर जाँच रिपोर्ट मरीजों को दिया जाता है, वैशाली जिला में भी न्यू अल्ट्रासॉउन्ड के नाम से एक भी संस्थान का निबंधन नही है। जिसका कार्यक्षेत्र सोनपुर, सारण है, जो जिले में कुल संस्थानों का पंजीयन मात्र 141 है। नया गांव अवस्थित खुशी क्लिनिक के नाम पर हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के रोगों का इलाज एवं ऑपरेशन किया जाता है। जिस हॉस्पिटल के अंदर मैक्सिमम ऑपरेशन रात में किया जाता है और मरीज को नशे कि हालत में खून निकालकर मरीज के अभिभावक को खून लाने कि तत्काल

व्यवस्था करने कि बात कही जाती हौ अंत में वही खून मोटे दाम पर उसी मरीज को चढ़ा दिया जाता है, यह गोरख धंधा वर्षो से चल रहा है, जिसकी भी शिकायत कि गयी है। हाजीपुर, वैशाली भी इस कार्य में अव्वल नम्बर पर है। जहाँ अवैध रूप से हजारो संस्थान /प्रतिष्ठानो का निबंधन करवाये बगैर मानक के विपरीत संस्थान का संचालन कर उन डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है जो स्वयं सरकारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं। वैसे डॉक्टर जो बड़े बड़े डिग्री हासिल कर बिना पारामेडिकल स्टाफ को रख अप्रशिक्षित स्टाफ के सहारे मरीजों का ऑपरेशन एवं इलाज कर रहा है। आखिर दूसरे कि जान कि कीमत से क्या मतलब। जिसकी सूची कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन को मुहैया करवाई गयी है उनमे से कुछ महत्वपूर्ण नाम उल्लेखित है :- लकवापोलियो निदान केंद्र, शिवगज, लखनी, विदुपुर, जो आयुष ग्रामीण चिकित्सक बिन्देसर साह द्वारा अंग्रेजी पद्धति से इलाज किया जाता है। जिस मरीज को दवा कि जानकारी तक नहीं दिया जाता जो एक महीने तक इलाज के लिए रखकर नर्सिंग सुविधा प्रदान किया जाता है, जो एक मरीज कम से कम डेढ़ लाख वूसली कर छोड़ दिया जाता है। इंद्रजीत कुमार, राजापाकर रोड (आयुष चिकित्सक) जो बिना लाइसेंस के नर्सिंग व्यवस्था देता है। इलाज अंग्रेजी पद्धति से करते हैं। चंदा मामा अल्ट्रासॉउन्ड, नवनीत डेंटल एंड फेसियल केयर, मिसा चाइल्ड केयर सेंटर, न्यू बी.के. हॉस्पिटल, श्री कृष्णा सेंटर, आरोग्य इमरजेन्सी हॉस्पिटल, हरिओम हॉस्पिटल, नव दृष्टि आई केयर, सूर्या नर्सिंग होम, आरोग्य फिजियोथरेपी, आर्यन अस्पताल, मेट्रीसिटी इमरजेंसी हॉस्पिटल,

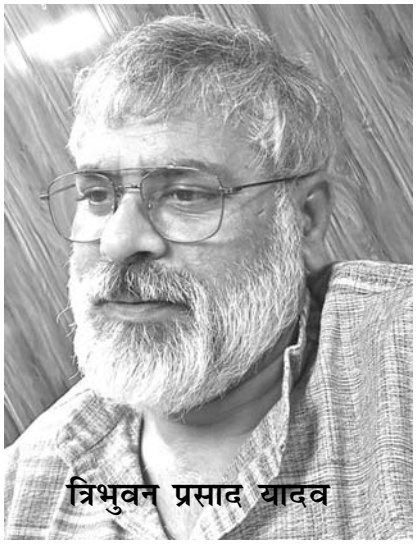
त्रिभुवन प्रसाद यादव

अर्थो वर्ल्ड ट्रामा एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नव दुर्गा हॉस्पिटल, एस.एस. अर्थो हॉस्पिटल, कल्याणी हॉस्पिटल, स्व. कन्हैया लाल शुक्ला सेवा सामाजिक संस्थान, स्वाति हॉस्पिटल, आदया सर्वदृष्टि आई हॉस्पिटल, ग्रीन लाइफ हॉस्पिटल, लॉट्स मैक्स केयर हॉस्पिटल, आरध्या मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, वैशाली नर्सिंग होम, रेज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोलो डेंटल हॉस्पिटल, निरंजन स्वामी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, परमवीर हॉस्पिटल, रॉयल हॉस्पिटल, गणेश लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल, श्री हरि हॉस्पिटल, निधि हॉस्पिटल, रामराज हॉस्पिटल, मेडीजोन हॉस्पिटल, ए.एन. चाइल्ड हॉस्पिटल सभी हाजीपुर सदर अस्पताल के बगल में संचालित किये जा रहे हैं। आयुष ग्रामीण चिकित्सक एम व सिंह जो विदुपुर (RS) वैशाली में क्लिनिक, दवाखना खोलकर मरीजों का इलाज अंग्रेजी पद्धति में करता है, जो बगल के दो मकान में किराए पर रखकर नर्सिंग सुविधा प्रदान करता है। एक मरीजों को कम से एक महीने रखकर इलाज करता है, जिसके द्वारा मरीजों के अभिभावक से सुई, दवा कि विवरण कि जानकारी प्रदान नही किया जाता और दवा से संबंधित कोई पेपर भी नही दिया जाता, जिसकी भी शिकायत कि गयी है। वैशाली में मात्र 180 संस्थानो का पंजीयन करवाया गया है। स्तिथि यह है की जिला मुख्यालय के चंद दूरी पर इसके आसपास अवैध रूप से संचालित संस्थान/हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, जाँच घर, अवैध मेडिकल हॉल जो वर्षो से संचालन किया जा रहा है, जिस पर अब तक जिला जिला प्रशासन कि नजर नहीं पड़ा और नहीं स्वास्थ्य विभाग को कोई जानकारी है, जबकि इसके लिए सरकारी स्तर पर हर महीने मीटिंग में किये गये कार्रवाई से संबंधित जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार-जिला पदाधिकारी कि अध्यक्षता में रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है, जिसके संयोजक सिविल सर्जन होते हैं। वही औषधि पर जाँच एवं नियंत्रण के लिए अलग से सहायक औषधि नियंत्रक, औषधि प्रशासन कर अधीनस्थ क्षेत्रीय औषधि निरीक्षक कार्य करते हैं, जो सिविल सर्जन के अधीनस्थ होते हैं। इस हालात में लापरवाही बरतने, अनिमियतता करवाने में संलिप्त दोषी खुद अधिकारी होते हैं। जिनके विरुद्ध संस्थान एवं संचालको से पहला ऐसे HLVZ अधिकारीयों पर कार्रवाई कि जानी चाहिए, जो विभाग अथवा जिला प्रशासन बचाने में लगी रहती है। जब ऐसा होता रहेगा तो सरकार से न्याय कि उम्मीद नहीं की जा सकती है!●

अभी कलम उठाइये

आपके सामने हो रहे भ्रष्टाचार एवं अपराध की खबर की समीक्षा करें और सरकार सहित पुलिस-प्रशासन तक उसको पहुंचाने के लिए केवल सच पत्रिका के साथ जुड़े। खबर की जानकारी इस नम्बर पर दें

सम्पर्क करें:- 9431073769/9955077308

ई-मेल:- editor.kstimes@rediffmail.com पर भेजें।

भ्रष्टाचार का महासागर है बिहार का स्वास्थ्य विभाग!

डॉक्टर ठाकुर और 102 एंबुलेंस मामले में भ्रष्टाचार और सागर जायसवाल के मामले में अनियमितता का हुआ पर्दाफाश

● **शशि रंजन सिंह/राजीव शुक्ला**

बिहार का स्वास्थ्य विभाग मतलब भ्रष्टाचार, अत्याचार अनियमितता और सत्यानाश! बिहार स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भाजपा के तेज तर्रार नेता हैं और विभागीय प्रमुख मुख्यमंत्री के लाडले अधिकारी बावजूद यहां हर वह सब कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या-3/ड-63, 2023सा0 प्र0-10000, पटना -15 , दिनांक -10/07/2015 और सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक-11899, दिनांक-06/10/2021 (सरकार के प्रधान सचिव चंचल कुमार द्वारा निर्गत पत्र) को कचड़े के डब्बे में फेंकते हुए डॉक्टर आई. एस. ठाकुर को संविदा के आधार पर PMCH का अधीक्षक बना दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री को इतनी जल्दबाजी थी कि मंत्री के नहीं रहने के कारण खुद फाइल पर हस्ताक्षर कर देते हैं। मामला मीडिया और न्यायालय में जाने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या-3/ड-63 2023 सा0 प्र0-10000, पटना-15, दिनांक -10/07/2015 और सामान्य प्रशासन विभाग पत्रांक-11899, दिनांक-06/10/2021 के आदेश के पालन हेतु घटनोत्तर स्वीकृति का प्रयास होता है और हो भी क्यों नहीं जी। भ्रष्टाचारी, फर्जी डिग्री धारी पर

खुद राज्य के मुख्यमंत्री का हाथ जो है। अधीक्षक डॉक्टर आई. एस. ठाकुर पर विभागीय कार्रवाई चलता है तो चलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उसके लिए सारे नियम शिथिल कर दिए जाते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के इस अत्याचार के खिलाफ अनुसूचित जाति की महिला डॉक्टर कुमारी मंजू ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। डॉक्टर कुमारी मंजू ने भारत के संविधान के आर्टिकल-21, सरकार की मनमानी के खिलाफ,

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

CORRIGENDUM-4 (Extension of Schedule of Events)

1. This is with reference to the Notice Inviting Tender (NIT) Reference No.: 01/SHSB/PPP(AMBULANCE)/2022-23 for selection of agency for operationalization and management of fleet of Ambulances & Mortuary Vans through integrated centralized Call Centre in the state of Bihar under Public Private Partnership (PPP) mode, published in leading newspapers [PR-0032 (Ni. Ni.) 2022-23] and uploaded on the website "http://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON" and "statehealthsocietybihar.org".

2. Due to unavoidable circumstances, the schedule of events for the tender stands changed as follows:-

	Sl.	Event Description	Timeline	Sl.	Event Description	Timeline
Page No.:-3, Clause-6, Schedule of Events & Corrigendum-3	6.1	Time of downloading the Tender	Till **06/06/2022 (Monday)** up to 05:00 PM, on the e-Procurement Portal (*https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON*).	6.1	Time of downloading the Tender	Till **15/06/2022 (Wednesday)** up to 05:00 PM, on the e-Procurement Portal (*https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON*).
	6.2	Last date & time for submission (upload) of online bidding document	Till **07/06/2022 (Tuesday)** up to 05:00 PM, on the e-Procurement Portal (*https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON*).	6.2	Last date & time for submission (upload) of online bidding document	Till **16/06/2022 (Thursday)** up to 05:00 PM, on the e-Procurement Portal (*https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON*).
	6.3	Last date & time for submission of EMD and Tender Cost in Hard (Physical) Copies (Offline Mode)	**11/06/2022 (Saturday)** by 01:00 PM, to *"The Executive Director, State Health Society, Bihar, Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014"*	6.3	Last date & time for submission of EMD and Tender Cost in Hard (Physical) Copies (Offline Mode)	**21/06/2022 (Tuesday)** by 01:00 PM, to *"The Executive Director, State Health Society, Bihar, Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014"*
	6.4	Time, Date of opening of Technical Bid	**11/06/2022 (Saturday)** at 03:00 PM, on the e-Procurement Portal *https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON*	6.4	Time, Date of opening of Technical Bid	**21/06/2022 (Tuesday)** at 03:00 PM, on the e-Procurement Portal *https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON*
	6.5	Time, Date of opening of Financial Bid	To be announced later on the e-Procurement Portal (https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON)	6.5	Time, Date of opening of Financial Bid	To be announced later on the e-Procurement Portal (https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON)

3. All changes/ modifications in NIT as above are binding to all bidders.
4. Other terms and conditions of the NIT shall remain the same.

5/6/24

Executive Director,
State Health Society, Bihar

1

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION

CIVIL APPEAL NO. 4975 OF 2024
(Arising out of SLP(C) No.28378/2023)

THE STATE OF BIHAR & ORS. APPELLANT(S)

VERSUS

M/S ZIQITZA HEALTH CARE LTD. & ANR. RESPONDENT(S)

WITH

CIVIL APPEAL Nos. 4976-4977 OF 2024
(Arising out of SLP(C) Nos. 28096-28097/2023)

WITH

CIVIL APPEAL NO. 4978 OF 2024
(Arising out of SLP(C) No.28389/2023)

ORDER

1. Leave granted.

2. Three appeals are before us. The Civil Appeal Nos.4975 of 2024 and 4978 of 2024 are filed by the State whereas the Civil Appeal Nos.4976-4977 of 2024 are filed by M/s. Pashupatinath Distributors Private Limited, questioning the same impugned order by which the High Court after holding that M/s. Pashupatinath Distributors Private Limited is disqualified, also set aside the disqualification of M/s. BVG India Ltd. which is a consortium and remitted back the matter to the State for fresh consideration after excluding M/s. Pashupatinath Distributors Private Limited.

6

India Limited could not have relied upon the purported experience certificate issued in the name of BVG Kshitij Waste Management Services Pvt. Ltd. Other certificates submitted by the Respondent 1 also did not satisfy the eligibility requirement."

64.2 A bidder who submits a bid expressly declaring that it is submitting the same independently and without any partners, consortium or joint venture, cannot rely upon the technical qualifications of any third party for its qualification."

9. Thus, we have no difficulty in upholding the finding of the High Court on this aspect.

10. Having decided the aforesaid two issues, we are inclined to hold that both M/s. BVG India Ltd. and M/s. Pashupatinath Distributors Private Limited are disqualified from participating in the tender concluded. In view of the aforesaid conclusion, the ultimate decision of the High Court in remitting matter back for a fresh consideration by the State is upheld while clarifying that the aforesaid two entities cannot be permitted to participate with the existing disqualification as discussed above, unless they are otherwise qualified in the light of the interpretation of the notice inviting tender. Incidentally, we are inclined to permit M/s. Pashupatinath Distributors Private Limited to continue with their operation till the tender process as directed by the High Court in its

7

impugned order and as modified by the order, is concluded. It is further clarified that the interim order dated 02.01.2024 passed by this Court shall continue till tendering process is concluded.

11. The State is directed to expedite the process of concluding tender process within a period of three months from today.

12. We make it clear that our observations are pertaining to the terms of the tender conditions which are existing as of now and it is well open to the State to formulate any new condition, if so required.

13. The present appeals are disposed of in the above terms.

14. Pending application(s), if any, shall stand disposed of.

....J.
[M.M. SUNDRESH]

....J.
[S.V.N. BHATTI]

NEW DELHI;
APRIL 16, 2024.

आर्टिकल-16 (10) राज्य आदि नौकरियां या पदों के नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों को अवसर की समानता के तहत पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या-CWJC नंबर-5597/2024 की सुनवाई न्याय मूर्ति मोहित शाह के बेंच में हो रही है न्यायालय इस याचिका को स्वीकृत करते हुए सरकार को चार हफ्ता के अंदर जवाबी हल्पनामा देने को कहा है। अब जिसके ऊपर मुख्यमंत्री का हाथ हो, वह क्या नहीं कर सकता।

हुआ यह कि अधीक्षक महोदय ने सर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर एवं यूनिट इंचार्ज डॉक्टर एम. सरफराज के यूनिट से दो मरीजों को एमएलए वार्ड में शिफ्ट करने का आदेश बिना यूनिट इंचार्ज डॉक्टर से पूछे कर दिया। जब डॉक्टर एम. सरफराज ने अपने पेशेंट की खोजबीन की तो पता चला उसे बिना किसी एमएलए के अनुशंसा के एमएलए वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। पीएमसीएच में इस बात को लेकर डॉक्टर एम. सरफराज और अधीक्षक

7 23 7

लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनकी सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में संबंधित विभाग द्वारा अपने अधीन सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा-विस्तार वित्त विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से 65 वर्ष के बाद भी 67 वर्ष तक किया जा सकेगा।

परंतु वैसे पदों, जिनकी सेवा निवृत्ति की आयु ही 65 वर्ष निर्धारित है, पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।

(vi) इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जाएगी और यदि कार्य संतोषजनक नहीं हो तो उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी।

(vii) चयन के लिए आदर्श रोस्टर चलेगा जो बिन्दु एक से प्रारंभ होगा।

(3) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के चयन हेतु निम्न प्रकार से चार स्तर पर चयन समिति गठित की जाएगी :-

(क) राज्यस्तरीय चयन समिति- समूह-'क' के पदों पर निम्नवत् गठित राज्यस्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर संविदा नियोजन किया जा सकेगा-

(i) मुख्य सचिव, बिहार -अध्यक्ष
(ii) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग -सदस्य
(iii) प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग -सदस्य सचिव
(iv) संबंधित प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव जिनके विभाग में संविदा नियोजन प्रस्तावित हो - विशेष आमंत्रित सदस्य
(v) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अ०जा०/अ०ज०जा० के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों -सदस्य
(vi) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक समुदाय के पदाधिकारी, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के हों -सदस्य

(ख) विभाग स्तरीय चयन समिति- समूह-'क' से भिन्न सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के पदों पर संविदा के आधार पर सेवा लेने हेतु सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों का चयन सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन निम्नवत् गठित चयन समिति की अनुशंसा पर किया जा सकेगा-

(i) प्रधान सचिव/सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग -अध्यक्ष
सामान्य प्रशासन विभाग - (ii) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग -सदस्य

4|Page

ज्ञापांक - 3/M-63/2013 सा० प्र० - 10000/पटना - 15
दिनांक - 10.07.2015

306

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा "Selection of Service Provider for establishing Data Management Units (DMUs) for providing data entry, analysis and management services in Government Healthcare Facilities and Health Department Offices in all 38 districts in the state of Bihar" से संबंधित प्रकाशित निविदा के आलोक में प्राप्त ऑनलाईन तकनीकी निविदाओं का मूल्यांकन हेतु दिनांक 31.01.2024 को पूर्वाहन 11:30 बजे सम्पन्न तकनीकी समिति की बैठक की कार्यवाही:-

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ने "Selection of Service Provider for establishing Data Management Units (DMUs) for providing data entry, analysis and management services in Government Healthcare Facilities and Health Department Offices in all 38 districts in the state of Bihar" से संबंधित निविदा Inviting Tender (NIT) Reference No.- 4/SHSB/DMU/2023-24 के द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों एवं वेबसाईट: https://eproc2.bihar.gov.in पर प्रकाशित कर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की गयी थी। ऑनलाइन निविदा समर्पित करने हेतु अंतिम तिथि 23.11.2023 (अपराहन 5:00 बजे तक) तथा तकनीकी निविदा खोलने की तिथि 28.11.2023 (पूर्वाहन 11:00 बजे) निर्धारित थी। तकनीकी निविदा खोलने हेतु निर्धारित तिथि एवं समय को तकनीकी निविदा Bid Opening Committee द्वारा तकनीकी निविदा को तकनीकी समिति के समक्ष https://eproc2.bihar.gov.in पर खोला गया। तकनीकी निविदा खोलने के पश्चात ज्ञात हुआ कि 3 बीडरों द्वारा निविदा की गयी है। तकनीकी समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्राप्त निविदाओं को Download कर Print किया जाय तथा अगली बैठक में निविदा दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जाएगा। उक्त के आलोक में तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 31.01.2024 (बुधवार) को पूर्वाहन 11:30 बजे डॉ० सुनील कुमार झा, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के अध्यक्षता में आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए-

Dr. Sunil Kumar Jha, Director in Chief Health Services, Health Department, GoB	Chairman
Shri Mrityunjay Kumar, Administrative Officer State Health Society, Bihar	Member
Shri Priya Ranjan Raju, OSD-Cum-I/c DMU State Health Society, Bihar	Member
Shri Manoj Kumar Safi, State Account Manager State Health Society, Bihar	Member
Dr. Ravi Shankar Singh, CMO (NFSG), ROHFW, GoI, Patna	Member

2. e-procurement portal (https://eproc2.bihar.gov.in) पर प्राप्त तीन (3) बीडरों (I. ARS Group, 1st Floor, Shekhar Complex, Khoja Imli, Phulwarisharif, Patna 801505, II. M/s URMILA INTERNATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED, 1st Floor, New Incubation, Software Technology Parks of India, New Patliputra Colony, Patna – 800013 & III. M/s WORLD CLASS SERVICES LIMITED, C-221, Kailas Esplanade LBS Marg, Opp Shreyas Cinema, Ghatkopar West Mumbai, MH – 400086) द्वारा निविदा की गयी है, परन्तु 3 में से एक निविदादाता – ARS Group, 1st Floor, Shekhar Complex, Khoja Imli, Phulwarisharif, Patna 801505 द्वारा EMD जमा नहीं किया गया है। प्रकाशित निविदा के Section-II की कंडिका-8.2 में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि- 'It may be noted that no bidder is exempt from deposit of EMD. Tenders submitted without EMD would be summarily rejected'. अतएव तकनीकी समिति ARS Group, 1st Floor, Shekhar Complex, Khoja Imli, Phulwarisharif, Patna 801505 द्वारा समर्पित निविदा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। तकनीकी समिति को अवगत कराया गया कि इसके अतिरिक्त निम्न दो (2) निविदाएँ प्राप्त हुई है-

(i) M/s URMILA INTERNATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED, 1st Floor, New Incubation, Software Technology Parks of India, New Patliputra Colony, Patna – 800013.
(ii) M/s WORLD CLASS SERVICES LIMITED, C-221, Kailas Esplanade LBS Marg, Opp Shreyas Cinema, Ghatkopar West Mumbai, MH – 400086.

3. उपरोक्त दो निविदादाताओं द्वारा e-procurement Portal पर अपलोड किये गये अभिलेखों के जाँचोपरांत तकनीकी समिति द्वारा Comparative Sheet of Technical Bid तैयार किया गया (Annexure-A) एवं पाया गया कि दो (2) निविदा- (i) M/s URMILA INTERNATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED, 1st Floor, New Incubation, Software Technology Parks of India, New Patliputra Colony, Patna – 800013 एवं (ii) M/s WORLD CLASS SERVICES LIMITED, C-221, Kailas Esplanade LBS Marg, Opp Shreyas Cinema, Ghatkopar West Mumbai, MH - 400086 राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा प्रकाशित निविदा के सभी Eligibility Criteria को पूर्ण करती है। विस्तृत विवरणी अनुलग्नित Comprative Chart of Technical Bid (Annexture-A) में प्रदर्शित है।

4. अतः तकनीकी समिति तकनीकी रूप से सफल दो निविदाओं यथा-(i) M/s URMILA INTERNATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED, 1st Floor, New Incubation, Software Technology Parks of India, New Patliputra Colony, Patna – 800013 एवं (ii) M/s WORLD CLASS SERVICES LIMITED, C-221, Kailas Esplanade LBS Marg, Opp Shreyas Cinema, Ghatkopar West Mumbai, MH – 400086 के वित्तीय निविदाओं को Project Appraisal Committee (PAC) के समक्ष खोलने की अनुशंसा करती है।

Ravi Shankar Singh 31/01/2024
Dr. Ravi Shankar Singh, CMO (NFSG), ROHFW, GoI, Patna

Shri Manoj Kumar Safi, State Account Manager State Health Society, Bihar

31/01/24
Shri Priya Ranjan Raju, OSD-Cum-I/c DMU State Health Society, Bihar

Shri Mrityunjay Kumar, Administrative Officer State Health Society, Bihar

Dr. Sunil Kumar Jha, Director in Chief Health Services, Health Department, GoB

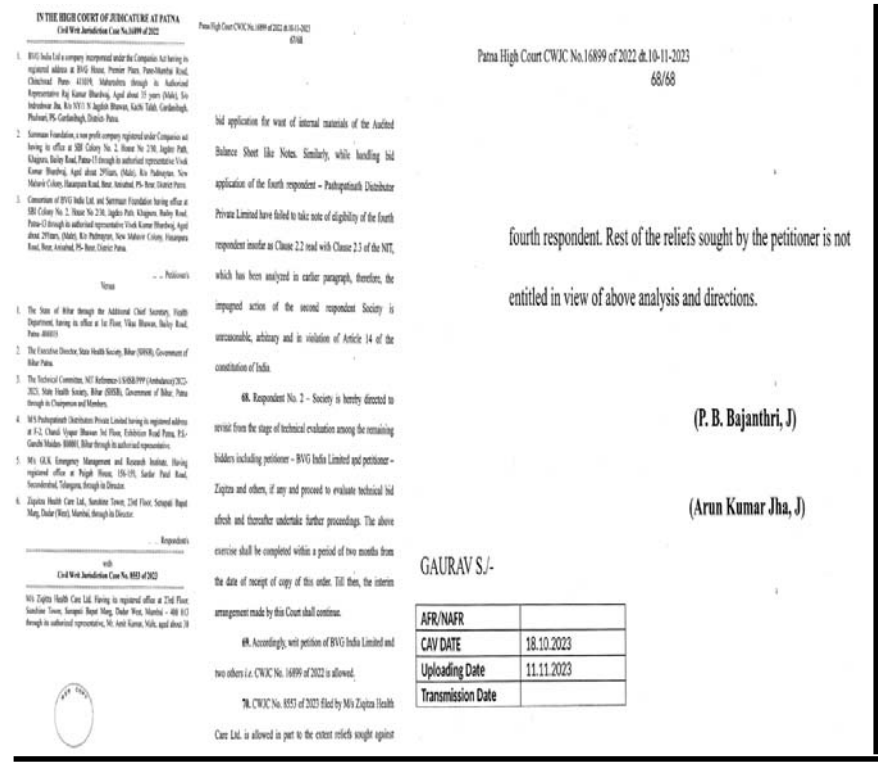

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.16899 of 2022

Patna High Court CWJC No.16899 of 2022 dt.10-11-2023
67/68

bid application for want of internal materials of the Audited Balance Sheet like Notes. Similarly, while handling bid application of the fourth respondent – Pashupatinath Distributor Private Limited have failed to take note of eligibility of the fourth respondent insofar as Clause 2.2 read with Clause 2.3 of the NIT, which has been analyzed in earlier paragraph, therefore, the impugned action of the second respondent Society is unreasonable, arbitrary and in violation of Article 14 of the constitution of India.

68. Respondent No. 2 – Society is hereby directed to revisit from the stage of technical evaluation among the remaining bidders including petitioner – BVG India Limited and petitioner – Ziqitza and others, if any and proceed to evaluate technical bid afresh and thereafter undertake further proceedings. The above exercise shall be completed within a period of two months from the date of receipt of copy of this order. Till then, the interim arrangement made by this Court shall continue.

69. Accordingly, writ petition of BVG India Limited and two others i.e. CWJC No. 16899 of 2022 is allowed.

70. CWJC No. 8553 of 2023 filed by M/s Ziqitza Health Care Ltd. is allowed in part to the extent reliefs sought against

Patna High Court CWJC No.16899 of 2022 dt.10-11-2023
68/68

fourth respondent. Rest of the reliefs sought by the petitioner is not entitled in view of above analysis and directions.

(P. B. Bajanthri, J)

(Arun Kumar Jha, J)

GAURAV S./-

AFR/NAFR	
CAV DATE	18.10.2023
Uploading Date	11.11.2023
Transmission Date	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.5597 of 2024

Dr. Kumari Manju ... ... Petitioner/s

Versus

The State of Bihar ... ... Respondent/s

Appearance :
For the Petitioner/s : Mr.Purushottam Kumar Jha, Advocate
For the Respondent/s : Government Pleader 6

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE MOHIT KUMAR SHAH
ORAL ORDER

2 18-04-2024 Four weeks' time is granted to the Respondents for filing the requisite counter affidavit.

2. List this case after four weeks.

(Mohit Kumar Shah, J)

kanchan/-

U

के बीच जब हंगामा बढ़ा तो मीडिया ने अधीक्षक आई. एस. ठाकुर से सवाल किया कि आपने ऐसा क्यों किया? तो अधीक्षक महोदय ने तड़का जवाब दिया कि हम यहां के मालिक हैं। ''यह बात ऑन रिकॉर्ड है''। अब PMCH सरकारी नहीं निजी संपत्ति कब से हो गई यह तो स्वास्थ्य विभाग और माननीय मुख्यमंत्री ही बता पाएंगे। यही हाल है स्वास्थ्य विभाग के इकाई बीएमएसआईसीएल का। वहां जो जितना बड़ा भ्रष्टाचार करता है, उस अधिकारी को उतना ही बड़ा मलाईदार पद मिलता है। बीएमएसआईसीएल के उप महाप्रबंधक प्रोजेक्ट सागर जायसवाल जो अपनी कंपनी SRVS बनाकर खुद नन शेड्यूल्ड आइटम का काम करता हो और उसका सारा सामान अपने क्षेत्र में बना रहे अस्पतालों में लगाता हो, जिसके कारण मंत्री को विधानसभा में गलत जवाब देना पड़ा। उसे मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा और मधुबनी जैसे बड़े जिले आवंटित कर दिया जाता है। केवल सच द्वारा मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री और बीएमएसआईसीएल को इसकी तथ्य पूर्वक सूचना देने के बावजूद सागर जायसवाल पर कोई

मुख्यमंत्री सचिवालय

CM Secretariat
Bihar

2022039278

दिनांक :- 02-Aug-2022 डायरी संख्या :- 2022039278

नाम :- Vijay Kumar संपर्क सूत्र :- 9931830322

नोट :- यह एक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति रशीद है। इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

संपर्क सूत्र : 4, देशरत्न मार्ग, पटना, बिहार, पिनकोड : 800001
E: cmbihar@nic.in, P: +91 (612) 2215601, 2217289

URL: http://cmsonline.bihar.gov.in

निर्भीकता हमारी पहचान
केवल सच
हिन्दी मासिक पत्रिका

दिनांक :- 18/04/2024

सेवा में,

(1) आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय
बिहार सरकार, पटना।

(2) सम्मानित मुख्य सचिव महोदय
बिहार सरकार, पटना।

विषय- बीएमएसआईसीएल के उप महाप्रबंधक परियोजना सागर जायसवाल के द्वारा अपनी कंपनी SARVS के माध्यम से अस्पताल निर्माण में घटिया स्तर के नॉन शेड्यूल्ड आइटम लगाए जाने के संबंध में।

महाशय,

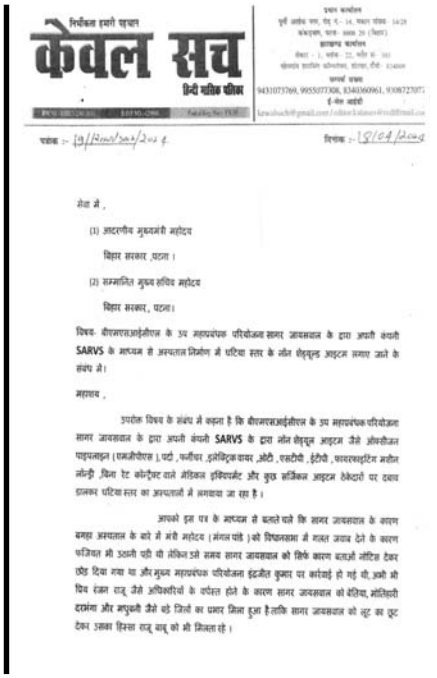

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि बीएमएसआईसीएल के उप महाप्रबंधक परियोजना सागर जायसवाल के द्वारा अपनी कंपनी SARVS के द्वारा नॉन शेड्यूल आइटम जैसे ऑक्सीजन पाइपलाइन (एमजीपीएस), पर्दा, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक वायर, ओटी, एसटीपी, ईटीपी, फायरफाइटिंग मशीन लॉन्ड्री, बिना रेट कॉन्ट्रैक्ट वाले मेडिकल इक्विपमेंट और कुछ सर्जिकल आइटम ठेकेदारों पर दबाव डालकर घटिया स्तर का अस्पतालों में लगवाया जा रहा है।

आपको इस पत्र के माध्यम से बताते चले कि सागर जायसवाल के कारण बगहा अस्पताल के बारे में मंत्री महोदय (मंगल पांडे) को विधानसभा में गलत जवाब देने के कारण फजीहत भी उठानी पड़ी थी लेकिन उसी समय सागर जायसवाल को सिर्फ कारण बताओ नोटिस देकर छोड़ दिया गया था और मुख्य महाप्रबंधक परियोजना इंद्रजीत कुमार पर कार्रवाई हो गई थी, अभी भी प्रिय रंजन राजू जैसे अधिकारियों के वरदहस्त होने के कारण सागर जायसवाल को बेतिया, मोतिहारी दरभंगा और मधुबनी जैसे बड़े जिलों का प्रभार मिला हुआ है ताकि सागर जायसवाल को लूट का छूट देकर उसका हिस्सा राजू बाबू को भी मिलता रहे।

मरीज को विधायक वार्ड में रखने पर मांगा गया जवाब

पटना। पीएमसीएच में यूनिट इंचार्ज से पूछे बगैर दो मरीजों को विधायक वार्ड में स्थानांतरित करने का मामला दिनभर सुर्खियों में रहा। पीएमसीएच सर्जरी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर व यूनिट इंचार्ज डॉ.एम सरफराज आलम ने एमएलए वार्ड के सिस्टर इंचार्ज से जवाब तलब किया है।

उन्होंने लिखा है कि उन्हें पीजी छात्रों व रेजिडेंट डॉक्टरों द्वारा सूचित किया गया कि उनके वार्ड में भर्ती दो मरीज अरुण कुमार व शुभम सौरव को एमएलए वार्ड में रखा गया है। जबकि उनके द्वारा अनुशंसा पर रखने के लिए अग्रसरित नहीं किया गया है।

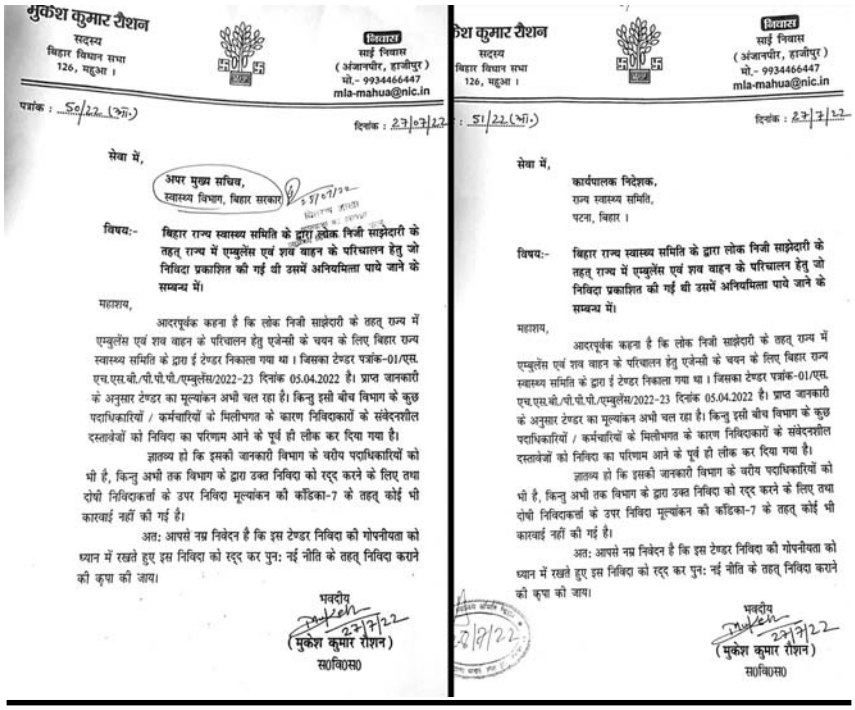

कार्रवाई नहीं होना यह दिखाता है कि स्वास्थ्य विभाग के बुनियाद में ही भ्रष्टाचार है। आपको बताते चले की बीएमएसआइसीएल के महाप्रबंधक प्रशासन प्रिय रंजन राजू को सागर जायसवाल के कमाई का अंश मिल रहा है इसलिए उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

स्वास्थ्य विभाग की इकाई राज्य स्वास्थ्य समिति ने NIT रेफरेंस नंबर-01/SHSB/PPP (एंबुलेंस) 2022-23 से एंबुलेंस और MORTARY के लिए केंद्रीकृत संचालन के लिए निविदा आमंत्रित किया। यह निविदा भी भ्रष्टाचार और अनियमितता के मकसद से किया गया। निविदा में 6 बार कोरिजेन्डम लाकर इसके नियमों में हेर-फेर किया गया, ताकि सत्ताधारी पार्टी के सांसद की कंपनी पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड का सेलेक्शन किया जा सके। यही नहीं पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड (पीडीपीएल) का सिलेक्शन करने के लिए कंपनी ने कई जाली और फर्जी सर्टिफिकेट को बिना सत्यापित करे राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारी ने इसे तकनीकी रूप से योग्य घोषित कर दिया और BVG इंडिया लिमिटेड को

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

NOTICE INVITING TENDER

e-tender (NIT) Reference No.: - 01/SHSB/PPP(AMBULANCE)/2022-23

1. The State Health Society, Bihar (SHSB), Patna intends to select agency via e-tendering for operationalization and management of fleet of Ambulances & Mortuary Vans through integrated centralized Call Centre in the state of Bihar under Public Private Partnership (PPP) Mode, for the period of 5 years from the date of agreement.
2. The State Health Society, Bihar (SHSB) invites bids from eligible business entities, in providing the services as mentioned in this tender document.
(Note: For the purpose of this tender, the terms, agency/ bidder/ service provider/ tenderer/ applicant shall all denote the same, if not stated otherwise.)
3. The selected bidder/agency shall be responsible for providing round the clock (24x7) free Emergency Medical Transport Services to the patients across all 38 districts in the state of Bihar through establishing, operating and managing the centralised Call Centre as per the terms and conditions defined in this tender document.
4. The contract agreement with the successful agency/bidder will be signed with SHSB, and on behalf of the SHSB, the day-to-day execution of the contract will be done by the District Health Society (DHS) of the concerned districts.
5. To participate in the e-tendering process, the bidder/agency are required to get themselves registered with Bihar Government Centralized e-Procurement portal, i.e., https:// www.eproc.bihar.gov.in /BELTRON, shall contact the helpdesk at the following address, "e-Procurement HELP DESK, 1st Floor, M/22, Bank of India Building, Road No. 25, Shree Krishna Nagar, Patna- 800001, Phone No. 0612 – 2523006, Mob. No 7542028164 (*Timings: Every Day from 08:00 AM to 08:00 PM*) or may visit the link "Vendor Info" at https:// www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON .
6. **Schedule of Events**

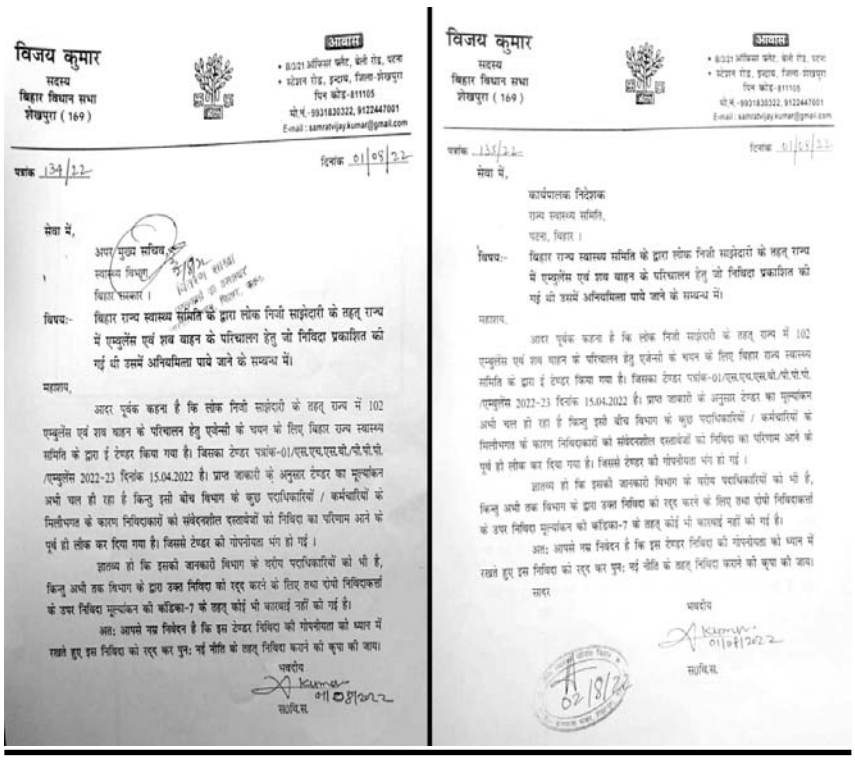

S.no.	Event Description	Timeline
6.1	Time of downloading the Tender	Till **28/04/2022 (Thursday)** up to 05:00 PM, on the e-Procurement Portal (https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON).
6.2	Last date & time for submission (upload) of online bidding document	Till **29/04/2022 (Friday)** up to 05:00 PM, on the e-Procurement Portal (https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON).
6.3	Last date & time for submission of EMD and Tender Cost in Hard (Physical) Copies (Offline Mode)	**02/05/2022 (Monday)** by 05:00 PM, to *"The Executive Director, State Health Society, Bihar, Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014"*
6.4	Time, Date of opening of Technical Bid	**04/05/2022 (Wednesday)** at 11:00 A.M., on the e-Procurement Portal https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON
6.5	Time, Date of opening of Financial Bid	To be announced later on the e-Procurement Portal (https://www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON)
6.6	Pre-bid meeting (Date & time)	**11/04/2022 (Monday)** at 11:00 AM
6.7	Pre- bid meeting venue	Conference Hall, State Health Society, Bihar, Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014

Note – i) Interested bidders/agencies may obtain further information about this Notice Inviting Tender (NIT) from the office of SHSB.
ii) No tender will be accepted after closing date and time in any circumstances.

7. Tenderer may also download the tender documents (a complete set of documents is available on website) from e-Procurement Portal (https:// www.eproc.bihar.gov.in/BELTRON) and submit its tender by using the downloaded document.
8. The tender shall be accompanied by Earnest Money Deposit (EMD) of **Rs. 9 Crore** (Nine Crore Rupees only) in the shape of Demand Draft/Bank Guarantee from any Schedule Bank in favour of State Health Society, Bihar payable at Patna. All Tenders must be accompanied by EMD as mentioned above. No bidder is exempted from submitting of EMD as mentioned in the tender document. Tenders without EMD shall be summarily rejected.

Page 1 of 2

मुकेश कुमार रौशन
सदस्य
बिहार विधान सभा
126, महुआ।

निवास
साईं निवास
(अंजानपीर, हाजीपुर)
मो.- 9934466447
mla-mahua@nic.in

पत्रांक : 50/22 (आ.)

दिनांक : 27/07/22

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

विषय:- **बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा लोक निजी साझेदारी के तहत् राज्य में एम्बुलेंस एवं शव वाहन के परिचालन हेतु जो निविदा प्रकाशित की गई थी उसमें अनियमितता पाये जाने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

आदरपूर्वक कहना है कि लोक निजी साझेदारी के तहत् राज्य में एम्बुलेंस एवं शव वाहन के परिचालन हेतु एजेन्सी के चयन के लिए बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा ई टेण्डर निकाला गया था। जिसका टेण्डर पत्रांक-01/एस.एच.एस.बी./पी.पी.पी./एम्बुलेंस/2022-23 दिनांक 05.04.2022 है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टेण्डर का मूल्यांकन अभी चल रहा है। किन्तु इसी बीच विभाग के कुछ पदाधिकारियों / कर्मचारियों के मिलीभगत के कारण निविदाकारों के संवेदनशील दस्तावेजों को निविदा का परिणाम आने के पूर्व ही लीक कर दिया गया है।

ज्ञातव्य हो कि इसकी जानकारी विभाग के वरीय पदाधिकारियों को भी है, किन्तु अभी तक विभाग के द्वारा उक्त निविदा को रद्द करने के लिए तथा दोषी निविदाकर्त्ता के उपर निविदा मूल्यांकन की कंडिका-7 के तहत् कोई भी कारवाई नहीं की गई है।

अत: आपसे नम्र निवेदन है कि इस टेण्डर निविदा की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए इस निविदा को रद्द कर पुन: नई नीति के तहत् निविदा कराने की कृपा की जाय।

भवदीय
27/7/22
(मुकेश कुमार रौशन)
स०वि०स०

मुकेश कुमार रौशन
सदस्य
बिहार विधान सभा
126, महुआ।

निवास
साईं निवास
(अंजानपीर, हाजीपुर)
मो.- 9934466447
mla-mahua@nic.in

पत्रांक : 51/22 (आ.)

दिनांक : 27/7/22

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक,
राज्य स्वास्थ्य समिति,
पटना, बिहार।

विषय:- **बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा लोक निजी साझेदारी के तहत् राज्य में एम्बुलेंस एवं शव वाहन के परिचालन हेतु जो निविदा प्रकाशित की गई थी उसमें अनियमितता पाये जाने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

आदरपूर्वक कहना है कि लोक निजी साझेदारी के तहत् राज्य में एम्बुलेंस एवं शव वाहन के परिचालन हेतु एजेन्सी के चयन के लिए बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा ई टेण्डर निकाला गया था। जिसका टेण्डर पत्रांक-01/एस.एच.एस.बी./पी.पी.पी./एम्बुलेंस/2022-23 दिनांक 05.04.2022 है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टेण्डर का मूल्यांकन अभी चल रहा है। किन्तु इसी बीच विभाग के कुछ पदाधिकारियों / कर्मचारियों के मिलीभगत के कारण निविदाकारों के संवेदनशील दस्तावेजों को निविदा का परिणाम आने के पूर्व ही लीक कर दिया गया है।

ज्ञातव्य हो कि इसकी जानकारी विभाग के वरीय पदाधिकारियों को भी है, किन्तु अभी तक विभाग के द्वारा उक्त निविदा को रद्द करने के लिए तथा दोषी निविदाकर्त्ता के उपर निविदा मूल्यांकन की कंडिका-7 के तहत् कोई भी कारवाई नहीं की गई है।

अत: आपसे नम्र निवेदन है कि इस टेण्डर निविदा की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए इस निविदा को रद्द कर पुन: नई नीति के तहत् निविदा कराने की कृपा की जाय।

भवदीय
27/7/22
(मुकेश कुमार रौशन)
स०वि०स०

विजय कुमार
सदस्य
बिहार विधान सभा
शेखपुरा (169)

आवास
• B/3/21 अधिकारी फ्लैट, बेली रोड, पटना
• स्टेशन रोड, इन्दाय, जिला-शेखपुरा
पिन कोड-811105
मो.नं.-9931830322, 9122447001
E-mail : samratvijay.kumar@gmail.com

पत्रांक 134/22

दिनांक 01/08/22

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
स्वास्थ्य विभाग,
बिहार सरकार।

विषय:- बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा लोक निजी साझेदारी के तहत् राज्य में एम्बुलेंस एवं शव वाहन के परिचालन हेतु जो निविदा प्रकाशित की गई थी उसमें अनियमितता पाये जाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

आदर पूर्वक कहना है कि लोक निजी साझेदारी के तहत् राज्य में 102 एम्बुलेंस एवं शव वाहन के परिचालन हेतु एजेन्सी के चयन के लिए बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा ई टेण्डर किया गया है। जिसका टेण्डर पत्रांक-01/एस.एच.एस.बी./पी.पी.पी./एम्बुलेंस 2022-23 दिनांक 15.04.2022 है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टेण्डर का मूल्यांकन अभी चल ही रहा है किन्तु इसी बीच विभाग के कुछ पदाधिकारियों / कर्मचारियों के मिलीभगत के कारण निविदाकारों को संवेदनशील दस्तावेजों को निविदा का परिणाम आने के पूर्व ही लीक कर दिया गया है। जिससे टेण्डर की गोपनीयता भंग हो गई।

ज्ञातव्य हो कि इसकी जानकारी विभाग के वरीय पदाधिकारियों को भी है, किन्तु अभी तक विभाग के द्वारा उक्त निविदा को रद्द करने के लिए तथा दोषी निविदाकर्त्ता के उपर निविदा मूल्यांकन की कंडिका-7 के तहत् कोई भी कारवाई नहीं की गई है।

अत: आपसे नम्र निवेदन है कि इस टेण्डर निविदा की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए इस निविदा को रद्द कर पुन: नई नीति के तहत् निविदा कराने की कृपा की जाय।

भवदीय
Kumar 01/08/2022
स०वि०स०

विजय कुमार
सदस्य
बिहार विधान सभा
शेखपुरा (169)

आवास
• B/3/21 अधिकारी फ्लैट, बेली रोड, पटना
• स्टेशन रोड, इन्दाय, जिला-शेखपुरा
पिन कोड-811105
मो.नं.-9931830322, 9122447001
E-mail : samratvijay.kumar@gmail.com

पत्रांक 135/22

दिनांक 01/08/22

सेवा में,

कार्यपालक निदेशक
राज्य स्वास्थ्य समिति,
पटना, बिहार।

विषय:- बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा लोक निजी साझेदारी के तहत् राज्य में एम्बुलेंस एवं शव वाहन के परिचालन हेतु जो निविदा प्रकाशित की गई थी उसमें अनियमितता पाये जाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

आदर पूर्वक कहना है कि लोक निजी साझेदारी के तहत् राज्य में 102 एम्बुलेंस एवं शव वाहन के परिचालन हेतु एजेन्सी के चयन के लिए बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा ई टेण्डर किया गया है। जिसका टेण्डर पत्रांक-01/एस.एच.एस.बी./पी.पी.पी./एम्बुलेंस 2022-23 दिनांक 15.04.2022 है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टेण्डर का मूल्यांकन अभी चल ही रहा है किन्तु इसी बीच विभाग के कुछ पदाधिकारियों / कर्मचारियों के मिलीभगत के कारण निविदाकारों को संवेदनशील दस्तावेजों को निविदा का परिणाम आने के पूर्व ही लीक कर दिया गया है। जिससे टेण्डर की गोपनीयता भंग हो गई।

ज्ञातव्य हो कि इसकी जानकारी विभाग के वरीय पदाधिकारियों को भी है, किन्तु अभी तक विभाग के द्वारा उक्त निविदा को रद्द करने के लिए तथा दोषी निविदाकर्त्ता के उपर निविदा मूल्यांकन की कंडिका-7 के तहत् कोई भी कारवाई नहीं की गई है।

अत: आपसे नम्र निवेदन है कि इस टेण्डर निविदा की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए इस निविदा को रद्द कर पुन: नई नीति के तहत् निविदा कराने की कृपा की जाय।

सादर

भवदीय
Kumar 01/08/2022
स०वि०स०

02/8/22

तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया। राज्य स्वास्थ्य समिति ने ZIQITZA हेल्थ केयर लिमिटेड और GVK एमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंडिया लिमिटेड तेलंगाना और पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड पटना को तकनीकी रूप से योग्य घोषित करते हुए इसकी वित्तीय निविदा खोली। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड को L1 घोषित किया गया इस फैसले से नाखुश BVG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, पटना उच्च न्यायालय ने CWJC नंबर-16899/2023 में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति P.B. BAJANTHI और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड पटना को अयोग्य घोषित कर दिया और BVG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वित्तीय निविदा खोलने का आदेश दिया। इस फैसले के खिलाफ ZIQITZA हेल्थ केयर लिमिटेड और राज्य स्वास्थ्य समिति ने उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में याचिका दायर की राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारी राजू प्रियदर्शी ने पीडीपीएल के आर्थिक प्रभाव में आकर बड़े-बड़े अधिवक्ता को इस केस के पेरवी में लगाया फिर भी के लिए लगाया, फिर भी उच्चतम न्यायालय में याचिका संख्या एसएलपी सिविल-28378/2023 में उच्चतम न्यायालय में न्यायमूर्ति एम. सुंदरेष और न्यायमूर्ति एस.बी.एन. भट्टी की खंडपीठ ने अपने आदेश में BVG इंडिया लिमिटेड और पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड दोनों को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित कर, ZIQITZA हेल्थ केयर लिमिटेड और GVK एमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंडिया लिमिटेड

37 **Annexure – P/7 (TC)**

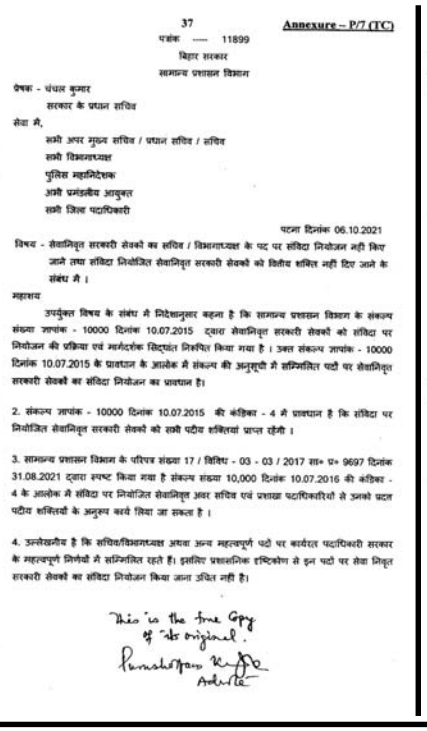

पत्रांक —— 11899

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक - चंचल कुमार

सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

पुलिस महानिदेशक

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना दिनांक 06.10.2021

विषय - सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का सचिव / विभागाध्यक्ष के पद पर संविदा नियोजन नहीं किए जाने तथा संविदा नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को वित्तीय शक्ति नहीं दिए जाने के संबंध में ।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापांक - 10000 दिनांक 10.07.2015 द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को संविदा पर नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत निरूपित किया गया है । उक्त संकल्प ज्ञापांक - 10000 दिनांक 10.07.2015 के प्रावधान के आलोक में संकल्प की अनुसूची में सम्मिलित पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा नियोजन का प्रावधान है।

2. संकल्प ज्ञापांक - 10000 दिनांक 10.07.2015 की कंडिका - 4 में प्रावधान है कि संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सभी पदीय शक्तियां प्राप्त रहेंगी ।

3. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 17 / विविध - 03 - 03 / 2017 सा॰ प्र॰ 9697 दिनांक 31.08.2021 द्वारा स्पष्ट किया गया है संकल्प संख्या 10,000 दिनांक 10.07.2016 की कंडिका - 4 के आलोक में संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त अवर सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारियों से उनको प्रदत्त पदीय शक्तियों के अनुरूप कार्य लिया जा सकता है ।

4. उल्लेखनीय है कि सचिव/विभागाध्यक्ष अथवा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत पदाधिकारी सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित रहते हैं। इसलिए प्रशासनिक दृष्टिकोण से इन पदों पर सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा नियोजन किया जाना उचित नहीं है।

This is the true Copy of its original.
Purushottam Kumar
Advocate

38

5. साथ ही उपर्युक्त संकल्प के प्रावधानों के आलोक में संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को निकासी एवं पदाधिकारी का दायित्व अथवा अन्य वित्तीय शक्तियां दिया जाना भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है

"6. वर्णित तथ्यों के आलोक में निर्णय लिया गया है कि :-

(क) (i) संकल्प ज्ञापांक – 10000 दिनांक 10.07.2015 के प्रावधान के आलोक में सचिव / विभागाध्यक्ष अथवा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का नियोजन नहीं किया जाय। "

(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व अथवा अन्य वित्तीय शक्ति संविदा के आधार पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को नहीं दी जाय।

(iii) अत्यंत विशेष परिस्थिति में यदि संविदा पर नियोजित सरकारी सेवकों को वित्तीय शक्ति दिये जाने के लिए प्रशासी विभाग की बाध्यता हो तो ऐसी स्थिति में वित्तीय शक्ति दिए जाने के पूर्व प्रशासी विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या – 17 / विविध – 03 – 03 / 2017 सा॰ प्र॰ - 9697 दिनांक 31.08.2021 को उक्त हद तक संशोधित समझा जाय।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका आठ के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/क्र मवा रियो को निर्देशित करने की कृपा की जाए.

विश्वासभाजन

ह/- पांचअस्पष्ट

चंचल कुमार

सरकार के प्रधान सचिव

This is the true Copy of its original.
Purushottam Kumar
Advocate

तेलंगाना की वित्तीय निविदा खोलने का आदेश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि यह पूरा प्रोसेस 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो निविदा की शर्तों में जरूरी बदलाव भी कर सकती है ताकि निविदा पारदर्शी हो सके। अब प्रश्न उठता है कि सभी तकनीकी योग्य कंपनियों ने निविदा से अपना अग्रधान राशि वापस ले लिया है, इसलिए वर्तमान में यह निवेदन निष्फल हो चुका है। दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जब GVK एमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंडिया लिमिटेड तेलंगाना वित्तीय निविदा में L2 आना निश्चित है तो GVK एमरजेंसी मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंडिया लिमिटेड, तेलंगाना पुनः निविदा में अग्रधन राशि क्यों जमा करेगी। कुल मिलाकर अब सरकार को निविदा रद्द करने और पुनः निविदा करने के सिवा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और प्रश्न उठता है कि जब राज्य के माननीय विधायक विजय कुमार, मुकेश कुमार रौशन, भाई वीरेंद्र सहित कई विधायकों ने राज्य के मुख्यमंत्री सहित आला अधिकारियों को निविदा लिक होने तथा इसमें भ्रष्टाचार होने की शिकायत कर निविदा रद्द करने की मांग की थी तो निविदा रद्द क्यों नहीं किया गया? अब निविदा तथा कानूनी खर्च किसके जेब से जाएगा-जनता, पूर्व कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, राज्य स्वास्थ्य समिति के एंबुलेंस देख रहे अधिकारी या फिर स्वास्थ्य विभाग के मुखिया। इसी प्रश्न को लेकर केवल सच ने राज्य स्वास्थ्य समिति में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना भी मांगी है ताकि जनता के एक-एक पैसे का हिसाब हो सके।

कुल मिलाकर पूरा स्वास्थ्य विभाग सिर्फ भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार और और अनियमिता का महासागर हो गया है। सुशासन बाबू का सुशासन स्वास्थ्य विभाग में नहीं चलता है, यह सिद्ध हो गया है। आपको बताते चले की सुशासन बाबू के प्रिय अधिकारी वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख अधिकारी हैं।●

असुविधा. पीएमसीएच और गर्दनीबाग अस्पताल में अव्यवस्था

गर्मी में भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं शौचालय से रिसाव से फैली है गंदगी

पड़ताल

शांतनु राज, पटना

गर्मी में राजधानी में हर जगह पीने लायक पानी की व्यवस्था की जा रही है, ताकि राह चलते लोगों को पानी पीने में किसी तरह की परेशानी न हो. लेकिन सरकारी अस्पतालों में अब भी पीने के पानी को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं. पीएमसीएच के टाटा वार्ड की बात करें, तो अस्पताल में नल तो लगा हुआ है, लेकिन उससे पानी नहीं आता है. इसके अलावा गर्मी में भीड़ बढ़ जाने के कारण लोग जमीन पर सोने को मजबूर है. वहीं गर्दनीबाग अस्पताल में भी कई असुविधाएं हैं. शौचालय की स्थिति बदहाल है. गर्मी के दिनों में मरीज वार्ड का पंखा भी खराब है.

पीएमसीएच में जमीन पर सोये परिजन.

शौचालय की स्थिति बदहाल

गर्दनीबाग अस्पताल के वार्ड के पीछे शौचालय का पानी बाहर निकल रहा है. मरीजों ने बताया कि इससे बदबू आती है. शौचालय भी बहुत गंदा था. इससे मरीज अस्पताल के बाहर के शौचालय का प्रयोग करते हैं. स्त्री व प्रसूति विभाग वार्ड में पंखा भी खराब है. इससे अस्पताल में भर्ती मरीजों को गर्मियों में काफी परेशानी हो रही है.

गर्दनीबाग अस्पताल

जेनरेटर भी हो गया खराब

गर्दनीबाग अस्पताल में फेज में गड़बड़ी के कारण घंटों बिजली कटे रहने से मरीज दिन भर परेशान रहे. मरीजों का मजबूरन मोबाइल की रोशनी से इलाज करना पड़ा. समस्या तो तब हुई, जब बिजली कटने के बाद अस्पताल का जनरेटर भी खराब हो गया. सुबह साढ़े नौ बजे से बिजली गुल हो गयी, जो शाम में चार बजे के करीब बहाल की गयी.

पोस्टमार्टम वार्ड के बाहर मेडिकल कचरे का अंबार

पीएमसीएच

पीएमसीएच के टाटा वार्ड में नल से पानी नहीं आ रहा है. दरअसल वार्ड में मरीज व परिजनों के लिए बाहर वाटर फिल्टर लगाया गया है. लेकिन फिल्टर में लगे नल से पानी नहीं आता है. साथ ही अस्पताल में क्षमता

में सोने को मजबूर हैं. वहीं, पोस्टमार्टम वार्ड में लिफ्ट खराब है. पोस्टमार्टम वार्ड में लगे हुए मीटर बॉक्स से तार बाहर आ रहे हैं. इससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है. इसके अलावा पोस्टमार्टम वार्ड की बगल में ही मेडिकल कचरे का अंबार लगा हुआ है.

केजरीवाल जेल में

पार्टी की अनर्गल बयानबाजी से खराब हो रही जांच एजेंसी और देश की छवि

● जितेन्द्र कुमार सिन्हा

देश में विपक्षी पार्टियाँ, सरकार के बदलाव की, बयार का सपना देखने वाले अब चिंतित और चिंतनशील दिखने लगे हैं। देश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुका है और सभी पार्टियाँ अपनी अपनी पार्टियों का चुनाव प्रचार करने में लग गए है। एक लंबे अंतराल के साथ चुनाव सात चरणों में पूरा होगा। अधिकांश विपक्षी पार्टियाँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई प्रतीत होती है। कुछ दिग्गज नेता या तो जेल जा चुके है, या जमानत पर हैं या जेल जाने की तैयारी में है। वर्तमान समय में देखा जाय तो अधिकांश राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक पार्टियाँ मानना और कहना भी गुनाह लगता है, क्योंकि उन्हें तो 'पारिवारिक' पार्टियाँ कहना ही ज्यादा उचित लगता है।

संविधान निर्माताओं ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी की देश में ऐसी स्थिति आयेगी जहां मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की भी नौबत आयेगी। आज देश के समक्ष पहली बार मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है और यह मुख्यमंत्री जेल से सरकार चलाएंगे। जहां तक मैं समझता हूँ कि आजादी के बाद यह पहली बार ही हुआ है कि जब किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। जबकि पहले यह होता था कि, जब मुख्यमंत्री पर आरोप लगते थे तो गिरफ्तारी से ठीक पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे दे देते थे। ऐसे में उदाहरण के रूप में बिहार के लालू प्रसाद और झारखंड के हेमंत सोरेन का नाम है। चारा घोटाले के मामले में 30 जुलाई, 1997 को लालू यादव ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण किया था, इससे पहले 25 जुलाई, 1997 को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। मामले में रक्षा भूमि घोटाला मामले में ईडी ने 31 जनवरी 2024 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके आवास पर जाकर पूछताछ की थी और हिरासत में लिया था। हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर अपनी इस्तीफा दिया था और चम्पई सोरेन के नेतृत्व में नयी सरकार बनाने का पत्र सौंपा था। आय से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की भी गिरफ्तारी हुई थी। 7 दिसंबर, 1996 को जयललिता की गिरफ्तार हुई, जबकि 5 दिसंबर, 1996 तक ही जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही थी। जमीन मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 15 अक्तूबर, 2011 को लोकायुक्त अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इससे पहले 31 जुलाई, 2011 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।

अब देखा जाय तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी की नौबत आने पर वे गिरफ्तारी से बचने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी चाही लेकिन हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। ऐसी स्थिति में अब प्रश्न उठता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल से सरकार चलाना, क्या संभव है? या सही होगा? जब कोई सरकारी सेवक जेल जाता है तो उसे 48 घंटे बाद निलंबित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री अपने पद पर कैसै बने रह सकता हैं? जबकि सर्वविदित है कि किसी भी राज्य की सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए गिरफ्तारी की नौबत या जेल जाने के पहले मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। जहां तक जेल नियमों के समय में

बताया जाता है कि किसी कैदी को सप्ताह में दो दिन ही परिजन से मिलने की छूट मिल सकती है और यह भी जेल अधीक्षक की अनुमति पर ही संभव होता है। जेल से कोई पत्र भी जेल अधीक्षक की अनुमति और माध्यम के बिना बाहर किसी को नहीं भेजा जा सकता है। वर्तमान स्थिति में दिल्ली के उप राज्यपाल के रुख पर ही अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री के पद पर बना रहना मुमकिन प्रतीत नहीं होता है। संविधान के जानकार का माने तो कानून की नजर में गिरफ्तारी होना दोष सिद्धि नहीं माना जाता है। ऐसे में किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा सकता है। जेल से सरकार चलाने के सवाल पर कानून के जानकार कहते हैं, जेल से सरकार चलाना जेल के नियमों पर काफी निर्भर करेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यह निर्भर कर रहा है कि वे संविधान और कानून की मर्यादा का ख्याल किस प्रकार रखते है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देश के इतिहास में लंबे समय तक याद रखे जायेंगे। क्योंकि भविष्य में लोग यह कहेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लगने के बावजूद नैतिकता को ताक पर रखकर शासन करते रहे हैं। जबकि उन्हें चाहिए था कि संवैधानिक पद से इस्तीफा देकर संविधान की रक्षा करते हुए अपने ऊपर लगाये गये आरोपों का मजबूती से सामना करना चाहिए। सर्वविदित है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता, लालू प्रसाद, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरने के बाद जेल जा चुके है, लेकिन जेल जाने से पहले सभी लोगों ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह से कुर्सी पर बने रहना चाहते है। जबकि जेल से शासन करना हास्यास्पद प्रतीत होता है।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफी जहीन नेता हैं क्योंकि वह देश की आईआरएस की प्रतियोगिता परीक्षा पास किए है। इसलिए वे कानूनी दाव-पेंच का लाभ उठाकर जेल जाने के बाद भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। दिल्ली सरकार (मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंत्रिमंडल) के मंत्रियों और प्रवक्ताओं के अनर्गल व्यानबाजी से जाँच एजेंसियों की छवि खराब तो हो ही रहा है। साथ ही देश की भी छवि खराब हो रहा है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकाल के दौरान पहली बार 28 दिसम्बर 2013 से 14 फरवरी, 2014 तक 49 दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे थे। उस समय केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाया था। कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के कारण मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। अब इन्हें पद छोड़ने में कठिनाई हो रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरह कुर्सी कुमार बनने की फिराक में तो नहीं है? जबकि नीतीश कुमार सरकार बनाने में माहिर खिलाड़ी है और उसमें अपने को मुख्यमंत्री बनाये रखते है। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आरोपों में घिरने के कारण आज जेल में है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किस प्रकार संविधान और कानून की मर्यादा का ख्याल रखते है। ●

बिहार बना अपराध की नगरी

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

पूरे बिहार में अपराध और पुलिस संख्या बढ़ती जा रही है। लगता है कि संख्याओं में कंपटीशन की होड़ मची हुई है। बताया जा रहा है कि बिहार में अब एक लाख की आबादी पर एक थाना होगी। अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ते जा रही है, आम नागरिक के कौन कहे पुलिस पर भी हमले हो रहे हैं, पुलिस को कौन बचाए? कई ऐसे उदाहरण है जिनमें कुछेक निम्न प्रकार है :-

☞ 2 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या। कटिहार मनिहारी नगर के वार्ड नंबर 8 चरवाहा विद्यालय में बच्ची को गला दबाकर हत्या कर दी गई।

☞ बाढ़ अथमलगोला के जमालपुर गांव में एक बेटे ने अपने वृद्ध पिता दिनेश सिंह की लाठी से पीट-पीट कर हत्या कर दी ।

☞ घर से बुलाकर युवक की हत्या। बाढ़ थाना क्षेत्र के राणा बीघा गांव स्थित फतेहपुर टोला निवासी युवक कारु सिंह की घर से बुलाकर पीट पीटकर हत्या कर दिए।

☞ दानापुर क्षेत्र के माधोपुर गांव में 62 वर्षीय धनु राय को पीट-पीटकर हत्या कर दी।

☞ महिला की हत्या कर शव को जानीपुर में फेंका। फुलवारी शरीफ में अपराधियों ने एक महिला की हत्या कर शव को जानीपुर में फेंक कर फरार हो गए।

☞ मुजफ्फरपुर में गोली मारकर हत्या। जैतपुर थाना क्षेत्र के मठ टोला में स्थित आभूषण दुकान दार को गोली मारकर हत्या कर दी स्वर्ण व्यवसाय की पहचान साहिबगंज थाना क्षेत्र के ओम प्रकाश वर्मा 40 वर्ष के रूप में हुई।

☞ बांका सदर थाना क्षेत्र के गोरा गांव में पति से विवाद होने के बाद महिला ने अपने दो बच्चों की गला दबाकर हत्या करने के बाद खुद फंदे से लटक कर जान दे दी। जानकारी के अनुसार महिला ने अपने चार वर्षीय पुत्री ऋतिका कुमारी एवं एक वर्षीय पुत्र ऋतिक कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद साड़ी का फंदा बनाकर कमरे के अंदर लटक गई।

☞ धनरूआ में पांचवी के छात्र को गला रेतकर हत्या। अपराधियों ने संपतचक गोसाई मठ इलाके से लापता पांचवी कक्षा के छात्र कुणाल कुमार 12 वर्ष की गला बैठकर हत्या कर दी।

☞ दानापुर में स्कूल परिसर से युवक का शव बरामद। पुलिस ने धनेश्वरी देवनंदन कन्या उच्च विद्यालय के परिसर से एक युवक का शव बरामद किया। मृतक का पहचान गोला पर झखड़ी महादेव निवासी बालेश्वर चौधरी के 24 वर्ष के पुत्र सुजीत कुमार के रूप में की गई।

☞ मसौढ़ी में अधेड़ की हत्या कर शव को लटकाया। मसौढ़ी नगर परिषद के केशवाचक निवासी दिनेश कुमार 46 वर्ष की गला दबाकर रिपोर्ट हत्या के बाद शव को फांसी पर लटकाने का मामला प्रकाश में आया।

☞ पंडारक में किशोर ने की आत्महत्या। पंडारक के मानिकपुर गांव में तनु कुमारी 14 वर्ष में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

☞ लखीसराय टाउन थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या दो इंग्लिश मोहल्ला में एक विवाहिता ने बंद कमरे में पंखे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

☞ फुलवारी शरीफ बदमाशों ने एक युवक की सिर में गोली मार कर हत्या कर दी। युवक की पहचान रानीपुर गांव निवासी भृगु नंदन के पुत्र सुकेश कुमार 45 वर्ष के रूप में की गई।

☞ दहेज के लिए एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या। दीदारगंज थाना क्षेत्र के बिचला टोला में दहेज प्रताड़ना में 25 वर्षीय विवाहिता के साथ मारपीट कर गला दबाकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है।

☞ गौरीचक

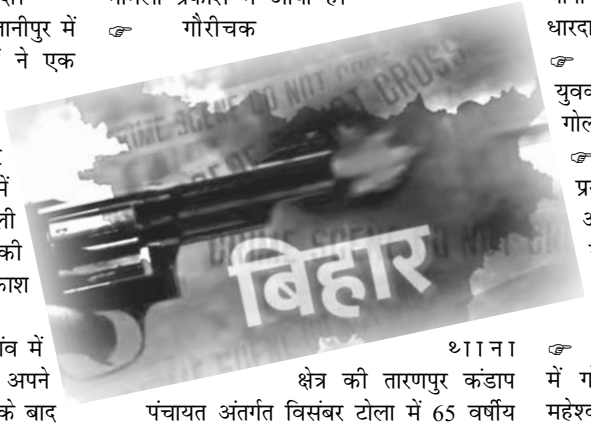

थाना क्षेत्र की तारणपुर कंडाप पंचायत अंतर्गत विसंबर टोला में 65 वर्षीय बुजुर्ग की गया की ईट से कूट-कूट कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान अखिलेश प्रसाद के रूप में की गई।

☞ फतुहा की जेठुली गांव में शिक्षक की गोली मारकर हत्या। नदी थाना क्षेत्र के जेठुली गांव में एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई बताया जाता है कि जेटली गांव निवासी रणवीर कुमार जो लखीसराय में नवोदय स्कूल में शिक्षक पद पर कार्यरत्त थे।

☞ औरंगाबाद में घर में सोई अकेली किशोरी की दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या। औरंगाबाद ओबरा थाना क्षेत्र के गांव में 15 वर्षीय किशोरी की दुष्कर्म के बाद मिथिलेश कुमार ने गला दबाकर हत्या कर दी।

☞ पूर्णिया भवानीपुर थाना क्षेत्र की रघुनाथपुर पंचायत के महथवा चाप में निवासी की हत्या कर दी। मृतक ज्योति चाप निवासी देवनाथ महतो की पुत्री स्वीटी कुमारी थी।

☞ किसान की हत्या। गोपालगंज बैकुंठपुर थाना के महुआ गांव में किसान चंद्रमा सिंह की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी।

☞ सासाराम में स्कूल जा रही छात्रा को युवक ने रोका, नहीं रुकी तो सीने में मार दी गोली।

☞ भागलपुर सीडीपीओ आवास के सामने प्रखंड प्रमुख के बेटे की हत्या। नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की आवास के सामने अपराधियों ने इस्माइलपुर प्रमुख के पुत्र मिथुन कुमार को गोलियों से छलनी कर दिया।

☞ वैशाली में दरवाजे पर बैठे व्यक्ति की मुंह में गोली मारकर हत्या कर दी। जंदाहा के महेश्वर नवरी थाना क्षेत्र के महेश्वर गांव में अपने दरवाजे पर बैठे एक व्यक्ति को मुंह में गोली मार दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक की पहचान लाखों साहनी के पुत्र इसरी साहनी के रूप में की गई।

☞ युवक की हत्या। पटना राजधानी में निर्माण अधीन एमएससी आवास में कृष्ण और अंशु की पिटाई के बाद हत्या कर दी बदमाशों ने शव को ग्रिल से हाथ पैर बांधकर लटका दिया।

☞ नर्सिंग स्कूल के प्राचार्य को गोली मारकर हत्या। ●

नेता वोट मांगने आये तो करें सवाल

हम किसे वोट दें, तय उम्मीदवार को या अन्य को : पंडित दीनदयाल

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

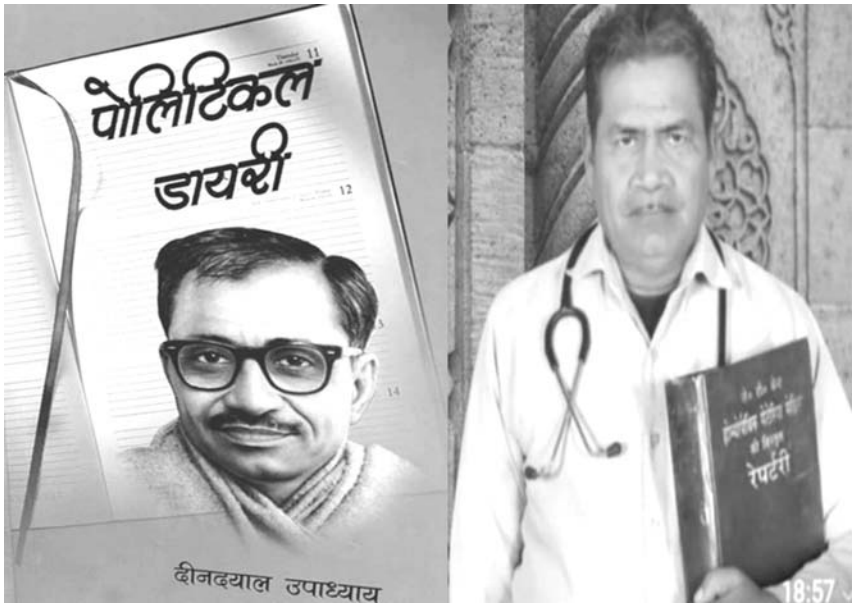

आज के बाद कब होगी आपका दर्शन? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई जा रही कितनी योजनाओं के बारे में आप लोग जानते हैं तो बताएं, आप लोग कितने लोगों को मुद्रा योजना, विश्वकर्मा योजना का लाभ जनता को दिलवा चुके हैं। कुछ लोगों को नाम बताएं। मोदी जी कहते हैं कि यह भ्रष्टाचार देश को खोखला कर रहा है, सबों को आगे आना होगा मतलब सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को आगे आना होगा? आप लोग कितनी बार भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रखंड, अंचल आदि जगहों पर प्रदर्शन, अनशन, आमरण अनशन आदि किए हैं। पंडित दीनदयाल ने कहा था कि उम्मीदवार तय होने के बाद हम किसे वोट दें? यह जरूरी नहीं की तेरी उम्मीदवार को ही वोट दें। क्या आप लोगों ने पंडित दीनदयाल का पॉलिटिक्स डायरी पढ़े हैं? ये नेता जो आपके बीच वोट मांगने आया है उसे जरूर सवाल करें कि मोदी की योजनाओं को सफल बनाने हेतु अपने क्या-क्या किया? किसी नागरिक की समस्या का समाधान करने के लिए आपने क्या-क्या प्रयास किया जनता आपको वोट क्यों दें हम आपसे क्या उम्मीद रखें आप जीतने के बाद अपने क्षेत्र में कितना समय बिताएंगे या आपसे कहां मिल पाएंगे। ●

भाजपा का मुखौटा नहीं संस्कार ग्रहण करना होगा

● डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह

किसी संगठन के तीन रूप होते हैं पहला समर्थक जिसे देश का भविष्य झलकता है। दूसरा कार्यकर्ता? कार्यकर्ता को भी तीन रूप होते हैं। पहला देशभक्त जिसकी संख्या अपवाद ही है। दूसरा पद का लालसा तथा ठेकेदारी करना बड़े-बड़े पद पर बैठे लोगों को स्वागत में नारा लगाना, माला पहनाना , ऐसे लोगों को सिद्धांत से कोई मतलब नहीं है। ऐसे अधिकांश अपने को भाजपा का पदाधिकारी बताते हैं, परंतु अधिकांश लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय का पॉलिटिक्स डायरी नहीं देखा होगा। पुस्तक में लिखा है हम किसी से विधायक सांसद चुने। तीसरा है। नेतृत्व कर्ता जो विधायक सांसद मंत्री बन जाता है परंतु योगी मोदी का चरित्र ग्रहण नहीं करता है। वह कभी अपराध, है भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है तथा मोदी जी द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा तक नहीं करेगा, जबकि 200 से ज्यादा लेना है चलाई जा रही है। पुल, समय से पहले मकान आदि समय से पहले ध्वस्त हो जाता है, बताया जाता है कि इसका मुख्य कारण इंजीनियर द्वारा भारी कमिशन। इस संदर्भ में विधायक, सांसद, मंत्री चर्चा तक नहीं करना चाहता। विधायक को वेतन मिलता है उसके बावजूद मुफ्त में फोन, बिजली, फर्नीचर, अखबार आदि लेता है, तथा एक व्यक्ति यदि पांच बार विधायक बनता है तो पांच पेंशन,10 बार बनता है तो 10 पेंशन यह कितना बड़ा महा लूट है। ऐसे लोगों के नजरों में शाय किसान मजदूर मूर्खो की जमात झलकती है तथा वीडियो को पुलिस अधिकारी सीडीपीओ, आदि सत्य हरिश्चंद्र होते हैं।●

राजद-भाजपा के सामने को पटकनी देने की जुगाड़ में लगे हैं विनोद व गुंजन

अपनो से पार पाने की है बड़ी चुनौती

● मनीष कमलिया/कृष्णा कुमार चंचल

लोकसभा चुनाव का रंग अब चढ़ने लगा है। झारखंड से सटे बिहार का दक्षिणी क्षेत्र नवादा। यहां अब चुनाव की गर्मी महसूस की जा सकती है। मतदान पहले चरण में 19 अप्रैल को है। मोदी, नीतीश, तेजस्वी का आगमन हो चुका है, योगी सोमवार को अकबरपुर में हुंकार भरेंगे। बिहारशरीफ-मोकामा रोड से उतरकर कवटी चेकपोस्ट के रास्ते बरबीघा में प्रवेश करते ही लगने लगता है कि चुनाव है। चुनाव आयोग के अनुशासन के डंडे का भय भी दिख रहा, क्योंकि कहीं झंडा-बैनर नहीं दिख रहा। पर, जनता का मन-मिजाज बता रहा है कि उनपर यह रंग चढ़ने लगा है। बरबीघा शेखपुरा जिले में पड़ता है, लेकिन नवादा लोकसभा के चुनाव परिणाम में अहम भूमिका निभाता है। यहां बाजार में प्लस टू हाईस्कूल के पास फर्नीचर बनाने का धंधा करने वाले रामनाथ प्रसाद कहते हैं कि अभी मुद्दा तो जाति और जमात ही है, लेकिन मोदी और विकास भी बड़ा फैक्टर है, जो अंतिम समय में जाति और जमात पर भारी पड़ सकता है।

☞ **राजद में अपने भी नहीं नहीं दे रहे साथ** :- यहां ऊपर से सीधी लड़ाई दिख रही है, लेकिन राजग और एनडीए दोनों में 'अपनों' से पार पाने की बड़ी चुनौती है। भाजपा प्रत्याशी विवेक ठाकुर और राजद से श्रवण कुशवाहा हैं। नवादा के केंदुआ में राजद के समर्पित कार्यकर्ता संटू सिंह की बातों से इसे बल मिलता है कि खेमे में अपनों की भी चुनौती है। वे कहते हैं, पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव के नाम पर हमलोग श्टेंपूश् चला रहे हैं। यही बात सिरदला में मिले किशोर यादव और लोहानी बिगहा के रामा सिंह यादव ने कही। 'टेंपू' निर्दलीय प्रत्याशी और नवादा शहर की राजद विधायक विभा देवी के देवर विनोद यादव का चुनाव चिह्न है।

☞ **दोनों खेमे में अपनों से ही मिल रही चुनौती** :- राजबल्लभ की विधायक पत्नी विभा देवी खुद पार्टी लाइन से अलग हटकर अपने देवर के साथ सभा में दिख रहीं हैं। रजौली विधायक प्रकाश वीर भी मजबूती से विनोद यादव के साथ खड़े हैं। बरबीघा-वारसलीगंज रोड पर मिले पैन गांव के किसान सुरेश प्रसाद सिंह अपने अनुभव के आधार पर बताते हैं कि यहां चुनाव में जाति का बोलवाला रहा है, उम्मीदवार भी मुद्दों से ज्यादा इसी पर भरोसा करते हैं, लेकिन इस बार दोनों खेमे में अपनों से ही चुनौती मिल रही है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी गायक गुंजन सिंह उनके यहां से हैं और युवाओं की बड़ी टोली उनके साथ घूम रही है। राजग से यहां भाजपा के प्रत्याशी विवेक ठाकुर हैं, जो भूमिहार जाति से आते हैं। इसी जाति से आने वाले गुंजन सिंह ने भाजपा के टिकट का प्रयास किया था, अब निर्दलीय मैदान में हैं। उन्होंने बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा बनाने की कोशिश की है। हालांकि, कोसरा गांव में अपने प्रत्याशी के प्रचार में जुटे भाजपा के सहकारिता जिला संयोजक वरुण कुमार कहते हैं कि शुरू में कुछ कार्यकर्ता दिग्भ्रमित थे, लेकिन अब सब साथ हैं और भीतरघात की कोई आशंका नहीं है। भाजपा प्रत्याशी के प्रचार में मिले जदयू के प्रदेश महासचिव अंजनी कुमार ने बताया कि यहां राजग में सभी दल एकजुट होकर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जबकि विरोधियों में बिखराव है। पार्टी के हैं, सो अपना दावा कर रहे।

☞ **नवादा में कुल आठ प्रत्याशी चुनाव मैदान में** :- नवादा में कुल आठ प्रत्याशी मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी से रंजीत कुमार भी जातीय वोट में प्रवेश का प्रयास कर रहे हैं।

☞ **विकास है मुद्दा, लेकिन जाति भी अहम** :- वारसलीगंज के मुन्ना चक के शिव जी यादव रास्ते में मिलते हैं। वे कहते हैं, विगत 10 सालों में उनके यहां काफी विकास हुआ है, खास तौर पर रेलवे और सड़क में। किऊल-गया लाइन का दोहरीकरण हुआ और बिजली अच्छी मिल रही है। मतदान इस आधार पर होगा कि जाति पर, यह प्रश्न पूछते ही मुस्कराते हुए बात को टाल देते हैं। यहीं मिले प्रमोद यादव ने कहा कि अपने विधायक जी के भाई भी मैदान में हैं, अभी कोई उनके गांव में नहीं आया है, आएगा तो सोचेंगे क्या करना है।

☞ **वोट उसी को देंगे जो उनके वर्ग का ध्यान रखता है वोटर** :- नवादा के खरांट मोड़ पर मिले राजेन्द्र मिस्त्री ने कहा कि इस मोड़ पर कभी दिन में 12 बजे लोग नहीं मिलते थे, अब देर शाम तक मोड़ गुलजार रहता है, वोट उसी को देंगे जो उनके वर्ग का ध्यान रखता है, जो उनके लिए अनाज-पानी की व्यवस्था करता है।

☞ **नवादा का जातीय गणित** :- नवादा लोकसभा क्षेत्र का जातीय गणित उलझा हुआ है। यहां कुल वोटरों में 50 प्रतिशत भूमिहार और यादव समाज से आते हैं। पांच प्रतिशत मुस्लिम वोटर हैं। 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं जनजाति से आते हैं और 30 प्रतिशत अन्य पिछड़ा एवं अति पिछड़ा की मिश्रित आबादी है। भाजपा से

विवेक ठाकुर हैं, जिन्हें जातीय के साथ सवर्ण और गठबंधन में शामिल चिराग पासवान का भरोसा है तो राजद ने पिछड़ों की मिश्रित आबादी में शामिल स्वजातीय वोटर को साधने के लिए श्रवण कुशवाहा को मैदान में उतारा है, लेकिन राजबल्लभ यादव ने छोटे भाई को मैदान में उतार गुणा-गणित को बराबर कर दिया है।

☞ **नवादा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत छह विधानसभा सीटें :-** इधर, निर्दलीय गुंजन सिंह भी भाजपा प्रत्याशी की ही बिरादरी के हैं। सो, दोनों ओर हिसाब-किताब लगभग बराबर है। क्षेत्र के छह विधानसभा में मतदाता नवादा लोकसभा में कुल 20 लाख 6124 मतदाता हैं, जिनमें 10 लाख 45 हजार 788 पुरुष मतदाता और 962186 महिला मतदाता है 150 थर्ड जेंडर भी हैं। नवादा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत छह विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें तीन पर राजद के विधायक हैं। एक-एक पर भाजपा, कांग्रेस और जदयू के विधायक हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में थी और सूरजभान के भाई चंदन सिंह ने राजद की उम्मीदवार विभा देवी को डेढ़ लाख मतों के अंतर से हराया था। पिछले तीन बार से भाजपा या भाजपा समर्थित उम्मीदवार चुनाव जीत रहे हैं। 2009 में भोला प्रसाद चुनाव जीते थे, जबकि 2014 में गिरीराज सिंह ने यहां से बाजी मारी थी।●

दो जिलों को जोड़ने वाला पथ आजादी के बाद भी नहीं बना

● कृष्णा कुमार चंचल/मनीष कमलिया

देश आजादी के बाद भी दो जिलों क्रमशः शेखपुरा नवादा जिले को जोड़ने वाला पकरीबरावां शेखपुरा पथ आज भी कलीकरण से कोसों दूर है। नवादा जिले के पकरीबरावां सीमा क्षेत्र के तनपुरा तथा शेखपुरा जिले के चोरबर के बीच मात्र एक किलोमीटर से भी कम दूरी है बाबजूद भी इस पथ को नहीं बनाया गया है, जिसके कारण लोगों को एक किलोमीटर के जगह दस किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है। इस बाबत दोनो जिले के ग्रामीणों ने दोनों जिले के सम्बंधित प्राधिकारी से लेकर सांसद विधायक तक गुहार लगाते लगाते थक गए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इस मामले को लेकर दोनों जिले के लोगों ने कई बार कमिटी बनाकर दोनों जिले के पदाधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक को इस ओर ध्यान आकर्षित करवाया गया परन्तु कोई नहीं सुनने को तैयार है।

☞ **कहां है यह पथ :-** नवादा जमुई पथ के कौड़िहारी नहर से नवादा जिले के जिलवरिया, पिंपड़वा, तनपुरा, सिलौर, बैरयाबीघा, जस्त आदि जबकि शेखपुरा जिले के चोरबर, मसौढा, धरसी, बौर्णा, बौर्णी, महुली होते शेखपुरा जाती है। इस पथ से शेखपुरा जाने में 25 किलोमीटर लगती है जबकि वर्तमान में जमुई जिले के आढ़ा भाया ध मौल होकर जाने में 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।

☞ **यह समस्या किस संसदीय क्षेत्र में है :-** यह समस्या नवादा व जमुई लोकसभा क्षेत्र से

क्या कहते हैं प्रखंडवासी :-

सबसे आश्चर्य यह है कि दोनों जिले के लोकसभा क्षेत्र पर लोजपा पार्टी का कब्जा है एक नवादा लोकसभा सीट पर सांसद चंदन सिंह तो दूसरे पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है बाबजूद यह हाल है। जब दूसरे दल के रहते थे तो यह बताया जाता था कि यह मेरे संसदीय क्षेत्र में नहीं है जिसके कारण शेखपुरा जिले के चोरवर और नवादा जिले के तनपुरा तक पथ का कलीकरण हो जाता है शेष लगभग एक किलोमीटर क्षेत्र सीमाकन के कारण अधूरा रह जाता है। यह दुर्भाग्य ही कहा जाय कि नवादा से लोजपा की सीट खाली हो गई और चिराग पासवान ने अपना लोकसभा क्षेत्र ही बदल लिया है।

महेन्द्र बरनवाल, पकरीबरावां बाजारवासी

एक किलोमीटर की पथ नहीं रहने के कारण हमलोगों को 12 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ता है उसके बाद लगभग 2 किलोमीटर तक पैदल कौड़िहाड़ी नहर तक पैदल चलना पड़ता है और उपर से किराया और समय भी अधिक लगता है। इस पथ से नवादा जिले के पिंडपड़वा, जिलवारिया, तनपुरा, सिलोर, बरैयाबीघा,जस्त आदि जबकि शेखपुरा जिले के चोरवर,ढरसी, बौरनी,बौरना, महुली सहित दर्जनों गांव के लोगों के लिए यह काफी ही अतिउपयोगी यह पथ है।

बाल्मिकी मेहता, पकरीबरावां

सूखे के दिन में ट्रैक्टर व हल्की चार पहिया वाहन तो आते जाते रहते हैं लेकिन हल्की फुल्की भी बारिश हो जाए तो यह कीचड़ में तब्दील हो जाती है। हालांकि पिछले वर्ष दोनो जिले के लाभान्वित गांव के ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से राशि को संग्रह कर गड्ढे में मिटी व मोराम का कार्य करवाया गया था परन्तु वह भी अब धीरे धीरे पुनः पुरानी स्थिति में आ गई है। अगर एक किलोमीटर से भी कम की दूरी का कालीकरण कर दिया जाए तो लोग आसानी से इधर से उधर जा सकेंगें।

बिनोद वर्णवाल, पकरीबरावां बाजार बासी

नवादा जमुई पथ से शेखपुरा जाने के लिए यह बहुत ही उपयोगी पथ है। इस पथ के बन जाने से सिर्फ पकरीबरावां प्रखंड वासियों की ही नहीं बल्कि रोह और कौआकोल प्रखंड वासियों के लिए भी अति उपयोगी पथ माना जाता है। सभी मात्र एक किलोमीटर से भी कम पथ के अधूरा रहने के कारण लोगों को दस किलोमीटर की दूरी को तय करना पड़ता है। कभी कभी तो शेखपुरा जाने के लिए दी दो वाहनों का उपयोग करना पड़ता है। जिसके कारण समय और धन दोनो बर्बाद होती है। दोनो जिले के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के अड़ियड़ रवैया के कारण इतनी दूरी पथ का निर्माण अधर में लटका हुआ है सिर्फ सीमाकन को लेकर।

शिव प्रसाद चौरसिया,
पकरीबरावां बाजार वासी

आता है सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि दोनों लोकसभा में लोजपा का ही सांसद थे बाबजूद भी इस पथ के समस्या का निदान नहीं हो पाया यह दुर्भाग्य ही कहा जाय कि राष्ट्रीय पार्टी का भी सांसद होते हुए स्थिति यथावत है।●

कालपनिक घटना में एक रिटायर प्रिंसिपल जेल के द्वार पर खड़ा है

● **डॉ० लक्ष्मीनारायण सिंह**

वाह पुलिस और उसकी व्यवस्था में आज कितना बदलाव आया है। आज समाज को सुरक्षा देने वाली पुलिस को देखते ही आम आदमी का पसीने छूटने लगते हैं। पांच दशक पूर्व महिलाएं कोलकाता से पेशावर तक घूम लेती थी उस महिला की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। पुलिस ईमानदार होते थे, समाज के बड़े लोग या छोटे उसे पकड़ने में अपने प्राणों की बाजी तक लगा देते थे। संस्कारों से लैस पुलिस अपने कर्तव्य का प्रति इतना वफादार होते थे की सफेद पोश तथा कथित लोगों को बेनकाब पल भर में कर डालते थे। बताया जाता है कि आज ऐसे -ऐसे पुलिस है जिनके पास वर्दी है परंतु संस्कार नहीं है। यदि बगैर मूर्ति के मंदिर हो तो किसे आराधना करगें ? बगैर संस्कार वाले पुलिस का ही नतीजा है कि भारी संख्या में निर्दोष व्यक्ति जेलों में न्याय के लिए तड़प रहे हैं। इसी प्रकार एक रिटायर्ड प्रिंसिपल विमल कुमार सिंह के विरुद्ध नालंदा जिला के चांदी थाना कांड संख्या 31/ 2024 दिनांक 17/ 1 /2024 को एक काल्पनिक मुकदमा कर दिया गया था। बताया जाता है कि विमल कुमार जेल के मुहाने पर खड़ा है तथा न्याय के लिए तड़प रहे हैं। बताया जाता है कि इस संदर्भ में कोई घटना नहीं हुआ बल्कि उनकी अपनी जमीन पर पुलिस और सीओ से मिलकर जमीन का कब्जा करने की साजिश चल रही है। विमल कुमार ने इस झूठे मुकदमे से न्याय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा बिहार के डीजीपी भट्टी से न्याय की गुहार लगाई है।●

कड़ाही फ्रेश रेस्टुरेंट के संचालक ने नौकरी की बदली परिभाषा

● मिथिलेश कुमार

आम तौर पर लोगों का यह मानना होता है की खुशहाल जीवन जीने के लिये सरकारी नौकरी ही जरूरी है. लेकिन बदलते परिवेश में कई युवाओं ने इस मिथक को तोड़ धीरे धीरे सरकारी नौकरी से नाता तोड़कर स्टार्टप से अपनी जिंदगी को खुशहाल बना रहें हैं.हालांकि ऐसा भी नहीं हैं की सरकारी नौकरी की कोई अहमियत नहीं है. नौकरी की अहमियत तो बहुत है लेकिन यह पोस्ट वैसे छात्र-छात्राओं के लिये भी है जो बहुत मेहनत करने के बाबजूद नौकरी पाने में सफल नहीं होते हैं, या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में फेल हो जाते हैं, अवसाद में जीना प्रारम्भ करते हैं और मानसिक यातना का शिकार हो जाते हैं. घर -परिवार, समाज के तीखे बोल एवं दिउर्थी भाषा से विचलित होकर गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं.वैसे छात्रों के लिये बहुत ही उपयोगी है.

मैं बात कर रहा हूँ नगर परिषद क्षेत्र के बलवा पर (स्टेशन से पूरब)मुहल्ला जहां अधिकतर परिवार अपनी रोजी रोटी से जुड़े हैं और मेहनतकश हैं. कुछ धनाढंय परिवार भी हैं, हाल के कुछ बर्षो में नौकरी पेशा में भी जुड़े हैं. मुहल्ले में निवास करने वाले सोनू का जो करीब पांच वर्षो तक सरकारी नौकरी करने के बाद नौकरी को छोड़कर रेस्टुरेंट खोलकर खुश हैं. आज संयोगवश उनके रेस्टुरेंट में पहुंचा, सोनू जी अपने काउंटर पर बैठे हुए थे उनकी नजर ज्यों ही मेरे ऊपर गयी गर्म जोशी से स्वागत किया और रेस्टुरेंट के एक कोने में बैठाया, हमारे साथ शांति मेहता पेट्रोल पम्प के संचालक बड़े भाई अरूंजय मेहता भी साथ में थे. उन्होंने सबसे पहले हमलोगों को पानी पिलाते हुए पूछा, क्या लेंगे सर.चुंकि सोनू जी से हमारी मुलाकत पहले से भी थी और शोशल मीडिया पर हमारे फ्रेंड लिस्ट में भी हैं, हमारे अच्छे कंटेंट की तारीफ भी करते हैं, जब की तारीफ के लायक मैं वैसा कुछ लिखता भी नहीं हूं. उन्होंने वेज सूप का ऑर्डर दिया, फिर इधर उधर की बातों के साथ मैंने उनसे रेस्टुरेंट के बारे में बात किया. मैंने उनसे उनकी नौकरी के बारे में पूछ दिया की आप अच्छी भली नौकरी को छोड़ कर इस व्यवसाय में क्यों आ गए,उन्होंने बताया की सर, यह ठीक बात हैं की एक अच्छी सरकारी नौकरी जीवन की दशा बदल देती है परन्तु हमारी स्वतन्त्रता छीन जाती है हम सिर्फ जहां कार्य करते हैं मशीन की भांति कार्य करते रहते हैं लेकिन अगर आप स्टार्टप में हैं तों थोड़ी सी रिस्क तो है लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति हमें सफलता के मार्ग को प्रशस्त करती है. मैं अपनी नौकरी छोड़कर शुरुआती दौर में इस व्यवसाय में आया तो मुझे भी कुछ समय ऐसा महसूस हुआ था लेकिन हमारे अंदर कुछ अलग करने का जूनून भी था. मैं जीविकोपार्जन के साथ साथ समाज के लिये भी कुछ करना चाहता था. आज मुझे लगता है की मेरा फैसला सही था. मैं पूर्ण संतुष्ट हुँ और खासकर वैसे विधार्थियो से आग्रह भी करता हुँ की आप असफल होने पर गलत कदम नहीं उठायें जिंदगी में अपार सम्भावनायें हैं जो आपको स्वयं तय करनी हैं. आप अपसाद में नहीं जियें. आपका स्वर्णिम भविष्य आपकी राह तक रही है सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहें. उन्होंने कहा की कुछ करने के लिये जीवन में आई परीक्षाओं को पास करें. हर किसी का वक्त बुरा नहीं हो सकता है. आज सोनू जी व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक कार्यो में भी रूचि रखते हैं, प्रखंड के मध्य विद्यालय बल्लोपुर (हिंदी)में निजी कोष से बच्चो के लिये पठन पाठन की सामग्री के साथ साथ पेंटिंग के लिये भी बच्चो को प्रेरित किया है. सोनू जी के रेस्टुरेंट में काम कर रहें सभी सर्विस कर्मचारियों से परिचय कराया, खासकर वेज व्यंजन तो बहुत ही जायकेदार थी. ऐसा नहीं की हम उनकी तारीफ कर रहें हैं लेकिन अच्छे कार्यों का कद्र भी नहीं हों यह भी ठीक नहीं है. उन्होंने हमारे साथ फोटो भी सूट कराया. कड़ाही रेस्टुरेंट वारिसलीगंज रेल ओवर ब्रीज के पूर्वी छोर पर मेहता नगर शेरपुर के पूर्व में स्थित है. आपलोग भी एक बार अवश्य जाएँ मुझे उम्मीद है की आप निराश नहीं होंगे.

☞ **निष्कर्ष :** अधिकतर लोगों को अभी भी लगता है कि सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी या व्यवसाय की तुलना में आरामदेह और सुरक्षित होती है, किन्तु ऐसा 20 से 25 साल पहले तक होता था। यद्यपि सरकारी नौकरी सुरक्षित तो है पर वर्तमान परिवर्तन शील युग में चुनौतीपूर्ण होती जा रही है इसीलिए इसे आरामदेह बोलना अब सही नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण जागरूकता है। सरकार जनता को सुविधाएं देने के लिए नित नए नए परिवर्तन कर रही है और इस से उन सरकारी व्यक्तियों को समस्या हो रही है जो पुराने हैं और जिन्होंने नवीनीकरण और सीखना छोड़ दिया था क्योंकि वो अब इसकी जरूरत भी नहीं समझते थे।आज के समय सरकारी नौकर चाहे वो चपरासी हो या अधिकारी सभी जवाबदेह है और अगर वो गलत काम करते हैं जैसे भ्रष्टाचार या अनियमितता तो उन्हें भी निजी नौकरी वालों की तरह नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके अलावा काम का तनाव भी काफी अधिक हो गया है। नेतागिरी, रिश्वतखोरी, आपसी कर्मचारियों में वैमनस्यता कि भी समस्या का सामना करना पड़ता है। सरकार अब धीरे-धीरे सरकारी विभागों को प्राइवेट बना रही हैं अथवा ठेके पर देना चालू कर दिया है। इसलिए व्यवसाय भी बुरी नहीं है. ●

सम्राट अशोक जयंती समरोह के मुख्य अतिथि बने निशिकांत

● **मिथिलेश कुमार**

बिहार के नवादा जिले के काशीचक प्रखंड अंतर्गत भट्टा गावं निवासी एवं बड़ोदरा के जाने मैने सफल व्यवसाई रिच माइंड डिजिटल कम्पनी के निदेशक निशिकांत सिन्हा को मुंबई में आयोजित होने वाली सम्राट अशोक जयंती सह पारिवारिक मिलन समारोह में मुख्य अतिथि बनकर नवादा जिले के गौरव को बढ़ाया है. समारोह का आयोजन कुशवाहा, मौर्य, माली, सैनी, प्रगतिशील फाऊंडेशन, मुंबई. के द्वारा आयोजित की गयी थी समारोह के मुख्य अतिथि निशिकांत सिन्हा ने सम्राट महान के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा की सम्राट अशोक विश्वप्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी राजा थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानांप्रिय अशोक थे उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से, 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक राज्य का मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिन्दुकुश, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश, पाटलीपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुँच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का सम्पूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यान्मार के अधिकांश भूभाग पर था, यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट है। सम्राट अशोक को 'चक्रवर्ती सम्राट अशोकश कहा जाता है, जिसका अर्थ है – 'सम्राटों के सम्राट', और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने कहा की सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य आज के सभी महाद्विपों में भी बौद्ध पन्थ का प्रचार किया। सम्राट अशोक के सन्दर्भ के स्तम्भ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहूत व्यापक रूप में मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णूता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवनप्रणाली के सच्चे समर्थक थे, इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में ही दर्ज हो चुका है। कल्हण के राजतरंगणी मे धर्माशोक का उल्लेख आता है। समारोह को मुंबई के दर्जनों प्रसिद्ध व्यवसाईयों एवं बुद्धिजीवीयों ने संबोधित करते हुए अशोक महान के पदचिन्हो पर चलने का संकल्प लिया. समारोह में आये अतिथियों का स्वागत अंगवस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया. स्टेशन मास्टर सह हिंदी के कवि मुकेश कुमार ने मुख्यअतिथि को अपनी स्वयं रचित कविता को प्रतीक चिन्ह के रूप में समर्पित किया.

☞ **मौके पर अति विशिष्ट अतिथि :-** श्री.जे.पी. वर्मा (उद्योगपति), श्री. मनोज कृष्ण (IRS) पूर्व प्रधान महानिदेशक वित्त विभाग, भारत सरकार, श्री. अरुण कुमार (IRS) आयुक्त आयकर, श्री. दुर्गादत (IRS) आयुक्त आयकर, (IRMSCHD) रेलवे हॉस्पीटल भायखला, मुंबई, डॉ० बीना कुमारी, श्री. डी. के. माली (अध्यक्ष माली समाज, मुंबई)

☞ **समाजसेवी एवं विशिष्ट अतिथि :-** सोनू कुशवाहा, उद्योगपति, श्री प्रशांत पंकज, उद्योगपति, डॉ० एस. कुशवाहा, एस. पी. सिंह, राजू यशवंत जाधव, उद्योगपति, कुशवाहा मौर्य माली सैनी प्रगतिशील फाऊंडेशन, मुंबई, प्रशांत कुमार सिन्हा, सचिव, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉ० कुमार राजीव अध्यक्ष सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे।●